• बुंदेलखंड पैकेज की बंदरबांट! • बिना बिजली 3,329 करोड़ की चपत

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

खतरा टला...लेकिन कब तक?

वर्ष 18, अंक-20 | 16 से 31 जुलाई 2020 | पृष्ठ-48 | मूल्य 25 रूपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2018-20

मध्यप्रदेश में बिछी चुनावी बिसात

बारिश के पानी का
संरक्षण करें...
लक्ष्मीकांत शर्मा
कॉन्ट्रैक्टर, शहडोल, (मप्र)
जल ही जीवन है... आओ इसे बचाएं...

इस अंक में

राजतंत्र

9 | योग्यता या उपहार

देश की शिक्षण और संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की लॉबी हावी होती दिखाई दे रही है। संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्तियों पर संघ की छाप नजर आने लगी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा...

राजपथ

10-11 | सिंधिया ही टाइगर

भाजपा आलाकमान का मकसद हर हाल में मध्यप्रदेश में सत्ता हासिल करने का रहा, जिसके चलते कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो डील हुई उसी को अब पूरा किया जा रहा है। नतीजतन सिंधिया...

कुपोषण

17 | 11 लाख कुपोषित

कुपोषण मुक्त होने के लाख दावे-वादे और घोषणाएं की जाएं परंतु विभागीय आंकड़े सबकी पोल खोलकर रख रहे हैं। साल 2019 दिसंबर में पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कम वजन और 1 लाख से ज्यादा अति कम वजन वाले सामने आए हैं।

लापरवाही

19 | रसूखदारों का मास्टर प्लान

देश के खूबसूरत शहरों में शुमार मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को किसकी नजर लग गई है और वो मास्टर माइंड (रसूखदार) कौन लोग हैं, जो एशिया की बड़ी झील के साथ ही भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले प्राकृतिक स्त्रोतों, पहाड़ियों और कोई पांच हजार एकड़ सरकारी ग्रीन लैंड...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

किसी भी सरकार का आईना होता है उसका मंत्रिमंडल। शिवराज मंत्रिमंडल का स्वरूप देखकर हर कोई कह सकता है कि यह चुनावी बिसात है। कांग्रेस इस मंत्रिमंडल को विडंबना, अवसरवाद और अंदरूनी खींचतान का पुतला मान रही है। वहीं भाजपा इसे संतुलित जमावट बता रही है। असल में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का बंटवारा कुछ नए समीकरण और संदेश लेकर आया है। अब देखना यह है कि यह नया समीकरण क्या गुल खिलाता है।

14

29

37

44

राजनीति

30-31 | राष्ट्रनीति का समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लेह यात्रा की अलग-अलग नजरिए से व्याख्या संभव है, लेकिन सच यही है कि अपनी चौंकाने वाली कार्यशैली के इस नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण कदम से उन्होंने एक साथ कई निशाने साधे हैं, कई संदेश दिए हैं। यह संदेश बिना संवेदनशीलता...

सियासत

32-33 | विरासत की वक्रदृष्टि

करीब 70 वर्षों तक देश की सत्ता पर आसीन रहा नेहरू-गांधी परिवार आज भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों से घिरा हुआ है। इस परिवार की देखरेख में चल रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के इतने नए और बड़े मामले सामने आए...

राजस्थान

35 | खतरा टला... लेकिन कब तक?

राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। यानी पायलट की कांग्रेस से विदाई हो गई है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायक दल की बैठक...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 फिल्म
45 खेल
46 व्यंग्य

अपनी बात

हमारी मीडिया के पतन की पराकाष्ठा

किसी ने क्या खूब कहा है...

सुना है मैंने पत्रकार हो गए हो तुम, इतने कब समझदार हो गए हो तुम।
ऐब के दौर में भी हुनर लेकर, तरक्की करते बेशुमार हो गए हो तुम।।

ये पंक्तियां पत्रकारिता के पतन की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। दरअसल, पत्रकारिता को इस समय कतिपय लोगों ने बाजारू बना दिया है। ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे यानी हर कोई मीडिया को अपनी सफलता का माध्यम बनाना चाहता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गोरखधंधा करने वाले मीडिया को अपनी ढाल बना रहे हैं। देश को छोड़िए मप्र में ही पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता की आड़ में वह सभी गैर-कानूनी धंधे किए जिससे पत्रकारिता कलंकित हुई है। अभी तक इंदौर में दो मीडिया घरानों की काली करतूत के किस्से चल ही रहे हैं कि राजधानी में भी एक चेहरा बेनकाब हुआ है। नाबालिग बच्चियों का शोषण कर उनका सेक्स रैकेट चलाने वाले की काली कमाई पर पुलिस का कहर तो बरपा है, लेकिन पत्रकारिता पर जो कलंक लगा है, वह धुलने वाला नहीं है। दरअसल, ऐसे लोगों को पत्रकारिता में उच्च मुकाम मिल जाना भी गहरी साजिश का परिणाम है। पत्रकारिता को मिशन मानकर कलम घिसने वाले पत्रकारों को न तो शासन और न ही प्रशासन का समर्थन और सहयोग मिल पाता है। जबकि एक रैकेट व एक दलाल के रूप में काम करने वाले को हर जगह मान और सम्मान मिलता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े धन्नासेठ और धंधेबाज पत्रकारिता की ओर सम्मोहित हो रहे हैं। इस वर्ग में हर उमर की हसीना से लेकर, दौलत का अंबार परोसकर, कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में असल पत्रकारिता या असल पत्रकारों की मेहनत मिशन व मशक्कत के साथ उनकी इज्जत और उन्हें मिलने वाली सहायता हड़प जाते हैं। मप्र में कारोबारियों, उद्योगपतियों, शराब माफियाओं को पलभर में पत्रकार बना देना, इनके लिए चुटकियों का और दाएं-बाएं हाथ का काम रहता है। चाहे जिसे जब चाहे अधिमान्यता दिलाना या छीन लेना इनके लिए इनका मूल पेशा है। शराब, शबाब और कबाब परोसने के बादशाह, हालांकि पत्रकारिता की दुनियां में कुछ नहीं जानते, अ ब स द का भी ज्ञान नहीं रखते। मगर इनकी हैसियत राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में किसी महान लिखक्कड़ से कम नहीं होती है। शासकीय कार्यालयों में इनका मायाजाल हर जगह फैला रहता है। सेक्स एंड भ्रष्टाचार टैक्स ऐसा कौन-सा कार्यालय है, जहां नहीं चलता। इसलिए इनका धंधा और पेशा बदस्तूर खुलकर चलता है। हैरानी की बात तो यह है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जिस पत्रकारिता के दम पर भारतीय साहित्य और संस्कृति को परिष्कृत किया आज उन्हीं के प्रदेश में पत्रकारिता का पतन पराकाष्ठा को पार कर रहा है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि उनके नाम पर संचालित पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी पत्रकारों की ऐसी फौज खड़ा कर रहा है, जो पत्रकारिता को मिशन की जगह कमीशन पर जोर देते हैं। इसकी वजह यह है कि इस विश्वविद्यालय को अच्युतानंद मिश्र के बाद कोई योग्य कुलपति नहीं मिल पाया है। अब तो इस विश्वविद्यालय में पार्टी और विचारधारा वाले लोगों को ही कुलपति बनाया जाता है। इससे यह विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है और मीडिया भी इसके रंग में रंगती जा रही है। इसलिए मीडिया को बाजारू होने से बचाने के लिए मिशन की पत्रकारिता करने वाले लोगों को आगे आना होगा, वरना मीडिया का भगवान ही मालिक है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 20, पृष्ठ-48, 15 से 31 जुलाई, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

आत्मनिर्भर देश बनाना है

भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमें चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और हमारे देश में बने सामानों का ही उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे देश के लोगों का भी फायदा है और इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा योगदान भी होगा।

● **प्रज्ञा शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

धूमिल हो रही चीन की छवि

चीन इस समय जो भी हरकतें कर रहा है उससे दूसरे देशों में उसकी छवि धूमिल हो रही है। ऐसे समय में, जब भारत और चीन समेत पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित कर कोरोना संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

● **मोहित कटारिया,** भोपाल (म.प्र.)

प्रवासी मजदूरों को काम मिले

कोरोनावायरस के इस संकटकाल में प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार को और अधिक योजनाएं लानी चाहिए। अभी सबसे अधिक मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना संकट के समय में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में मप्र पांचवें स्थान पर है।

● **राजीव मिश्रा,** ग्वालियर (म.प्र.)

किल कोरोना अभियान अच्छा कदम

प्रदेश में कोरोनावायरस को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा किल कोरोना अभियान प्रशंसनीय है। इस अभियान के द्वारा जहां एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में लोगों के घर-घर जाकर उनकी स्क्रैनिंग की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस अभियान में शामिल लोगों को कोविड मित्र के रूप में काम करने का मौका और रोजगार भी मिलेगा। इनसे 6 महीने तक काम लिया जाएगा, बदले में इन्हें हर महीने 1500 रुपए मेहनताना मिलेगा। इसके साथ ही सरकार इस अभियान को पूरा करने के लिए वालंटियर्स की भी मदद लेगी, जो सर्वे का काम करेंगे और सार्थक ऐप में जानकारी अपलोड करेंगे। ऐसे में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

● **हिमांशु सेन,** सीहोर (म.प्र.)

उपचुनाव की तैयारी में भाजपा-कांग्रेस

प्रदेश में राज्यसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी साख को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएंगी। असल में इन उपचुनावों के बाद ही सरकार का स्थायी भविष्य तय होगा। मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के चलते भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाए और बचाए रखने के लिए उपचुनावों में जीत का सिलसिला कायम रखना पड़ेगा।

● **मेघा पाठक,** शिवपुरी (म.प्र.)

मतदाता खुद चुने महापौर

शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले का पलटने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है। यह एक अच्छा फैसला है। हर मतदाता को अपनी पसंद का महापौर और अध्यक्ष खुद चुनने का हक है। इससे एक बार फिर मतदाता अब सीधे नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष चुन सकेंगे।

● **शालिनी सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कांग्रेस का हर राज्य में संकट

कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का संकट अभी खत्म ही हुआ था कि राजस्थान में संकट शुरू हो गया। वहां अभी मामला सुलझा भी नहीं है कि झारखंड में कांग्रेस विधायकों के बागी होने की खबरें हैं। प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस के 15 में से चार विधायक नाराज हैं। हालांकि ज्यादा विधायकों के नाराज होने की खबर है क्योंकि सरकार में होने के बावजूद न जेएमएम के मंत्री उनकी बात सुनते हैं और न कांग्रेस के। राज्य के प्रभारी आरपीएन सिंह ने पूरी तरह से जेएमएम और मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर किया हुआ है। तभी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस विधायक दल में टूट हो सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत है पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के घटनाक्रम के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के करीब 20 विधायकों को किसी न किसी निगम या बोर्ड, आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बनाने वाले हैं। उन्हें कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए यह उपाय हो रहा है। राजस्थान में भी कुछ विधायकों को संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में विधायकों को पद मिलने की चर्चा के बाद झारखंड में भी कांग्रेस विधायक इसकी मांग कर रहे हैं।

गुटबाजी कांग्रेस की संस्कृति

गुटबाजी कांग्रेस की संस्कृति है। फिर उत्तराखंड में ही पार्टी इस रोग से मुक्त कैसे रह सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा दो साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी है। जबकि कांग्रेस के छत्रप एक+दूसरे की टांग खींचने में ही व्यस्त हैं। सियासत में कोई किसी का सदा सगा नहीं रहता। यहां भी रणजीत सिंह रावत और संजय पालीवाल कल तक हरीश रावत खेमे में थे। अब सूबेदार प्रीतम सिंह की तरफदारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश भी हरीश रावत से खुश नहीं। रावत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं। विजय बहुगुणा कांग्रेस में थे तो हरीश रावत को कमजोर करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। भाजपा में उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अलग कर रखा है तो इससे हरीश रावत क्यों खुश न हों। प्रीतम सिंह अगर हरीश रावत पर भाजपाई मुख्यमंत्री के प्रति सदाशयता बरतने का मुलम्मा चढ़ाते हैं तो चढ़ाएं।

हर कोई पैंतरेबाज

चुनाव का साल है तो सियासी उठापटक और गहमागहमी भी होगी ही। बात बिहार की कर रहे हैं। राजद की फूट बेशक सार्वजनिक है पर खटास तो सत्तारूढ़ राजग के घटक दलों में भी कम नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कुमार उसके विस्तार में बाधा बने हैं। कहीं न कहीं दोनों दलों के शिखर नेतृत्व का आपसी अहम और हितों का टकराव भी मनमुटाव की दरार को चौड़ा कर रहा है। ताजा विवाद चिराग पासवान द्वारा मुंगेर जिले के पार्टी अध्यक्ष की छुट्टी करने से उठा है। गुनाह बना एक बयान कि बिहार में राजग एकजुट है। चिराग ने इसे पार्टी लाइन के खिलाफ माना और कहा कि इस तरह के नीति संबंधी बयान सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं। चिराग की टीस कई हैं। बिहार विधानसभा में भले उनके दो ही विधायक हैं पर घटक दल के नाते उन्हें एक मंत्रिपद तो मिलना ही चाहिए था। विधान परिषद् की राज्यपाल के द्वारा नामित होने वाली बारह सीटों में भी उन्हें हिस्सा चाहिए। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले की तर्ज पर कम से कम दो। पांच-जद (एकी) और पांच-भाजपा। पर नीतीश खुद सात सीट चाहते हैं। चिराग को सीटें लेनी हो तो वे भाजपा की पांच में से मांगें। नीतीश की शिकायत है कि चिराग हैसियत से ज्यादा पांव पसार रहे हैं।

महत्वाकांक्षा आत्मघाती

कांग्रेस पार्टी को लेकर एक खास बात है, जो इसे भाजपा या दूसरी पार्टियों से अलग करती है। वह बात ये है कि कांग्रेस काडर आधारित या किसी खास जाति के वोट बैंक के सहारे राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। काडर आधारित पार्टियों में या जातिगत वोट बैंक वाली पार्टियों का कोई नेता अगर पार्टी छोड़ता है तो उसका सफल होना नामुमकिन सा होता है। पर कांग्रेस से निकलकर कोई भी सफल हो जाता है क्योंकि उसका कोई कैप्टिव वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस की तरह राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस से बाहर भी सफल हो जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि कांग्रेस छोड़कर काडर आधारित पार्टी जैसे भाजपा में जाने वाले नेता सफल नहीं हो पाते हैं। वे एक निश्चित सीमा तक तरक्की करते हैं पर कांग्रेस में रहते वे अपनी जिस महत्वाकांक्षा के पूरा नहीं होने का विरोध करते हैं वह भाजपा में जाकर तो कतई पूरी नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं। फिर भी भाजपा में लोग जा रहे हैं।

अदला-बदली नहीं होगी!

भाजपा के संगठन और सरकार में कोई खास अदला-बदली नहीं होने वाली है। पहले कहा जा रहा था कि पार्टी संगठन के कुछ लोगों को सरकार में भेजा जाएगा और सरकार के कुछ मंत्री संगठन में भेजे जाएंगे पर अब इसकी संभावना कम बताई जा रही है। कम से कम सरकार का कोई आदमी यानी मंत्री संगठन में नहीं आने वाला है। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने राष्ट्रीय या प्रदेश संगठन से जुड़े नेताओं को ही राष्ट्रीय संगठन में जगह देने का फैसला किया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार में फेरबदल नहीं होगी या सारे मौजूदा मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। कुछ लोग हटाए भी जा सकते हैं पर जो हटाए जाएंगे उनके संगठन में आने की संभावना कम है। वैसे भी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि सरकार में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनका संगठन से नाता नहीं रहा है या बहुत मजबूत संगठनकर्ता नहीं रहे हैं। शीर्ष पद के थोड़े से मंत्रियों को छोड़ दें तो ज्यादातर को संगठन का अनुभव नहीं है। इसलिए संगठन के लिहाज से अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी।

सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी

अगर व्यक्ति विवेक से काम करे तो उसके सामने आने वाली सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। यह सिद्ध कर दिखाया है प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने। साहब वर्तमान समय में प्रदेश के एक बड़े जिले में आईजी के पद पर पदस्थ हैं। यह जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। हर एक की कोशिश होती है कि वह इस संभाग में पदस्थ हो। इसलिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही साहब की कुर्सी पर बैठने के लिए कई अधिकारी सक्रिय हो गए। इनमें से एक अधिकारी ने उक्त जिले का आईजी बनने के लिए जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी। यही नहीं उनको उक्त जिले का आईजी (जो वर्तमान में एडीजी हैं) बनाने के लिए सत्ता के चहेते राजधानी के एक उद्योगपति ने मोर्चा संभाला। ऐसे में यह तय माना जाने लगा की साहब की विदाई होकर रहेगी। लेकिन साहब ने सभी कयासों पर पानी फेर दिया। दरअसल, साहब ने अपने विवेक से काम लिया। उन्होंने सीधे मंत्री को ही सेट कर लिया। बताया जाता है कि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि आप निर्भीक होकर काम करें। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में कहा जा रहा है कि साहब ने अगर विवेक से काम नहीं लिया होता तो आज उनकी कुर्सी खतरे में रहती। यही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि उनके विवेक का ही कमाल है की सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है। साहब के विवेक का अब उनके साथ भी लोहा मानने लगे हैं।

हमें तो खुरचन ही मिल जाए

प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक महिला मंत्री और उनके पीए की करतूतों की खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि मंत्री के पीए जमकर माल कूट रहे हैं और अन्य अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब इस चर्चा की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त मंत्री ने एक प्राइवेट व्यक्ति को पीए रख रखा है। सूत्र बताते हैं कि उक्त पीए को मंत्री ने फ्री हैंड दे रखा है। यानी वे मंत्री की मंशानुसार, धंधा-पानी में जुटे हुए हैं। नैतिक-अनैतिक या अन्य तरीकों से मंत्री के पीए माल उगाही में लगे हुए हैं। उधर मंत्री के यहां पदस्थ सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की एक नहीं चल पा रही है। बताया जाता है कि मंत्री और उनके पीए की कार्यप्रणाली से उनके साथ अटैच सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों में रोष है। वे कहते हैं कि जब हमारी पदस्थापना मंत्री के पास हुई तो आस जगी थी कि कुछ ऊपरी कमाई का रास्ता खुलेगा। लेकिन मंत्री ने प्राईवेट पीए रख लिया है। वह हम सरकारी लोगों को भाव ही नहीं दे रहा है। वह कहते हैं कि एक तो मंत्री का पेट बढ़ा है, उस पर उन्होंने प्राईवेट पीए रख लिया है जिससे हमारी दाल गल ही नहीं पा रही है। वह कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमें खुरचन ही मिल जाए, लेकिन वह भी नसीब नहीं हो रहा।

खेल खतम... पैसा हजम

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इस कहावत को प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने पिछले दिनों सही साबित किया है। पुलिस विभाग में शीर्ष पद पर पदस्थ यह आईपीएस अधिकारी पिछली सरकार में खूब चर्चा में रहे। दरअसल, तत्कालीन सरकार के दौरान घटित हनी-मनी कांड में इन्होंने जमकर माल कूटा है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने हनी-मनी कांड में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए उनको लोक-लाज का वास्ता देकर खूब चढ़ोत्तरी ली है। एक अधिकारी कहते हैं कि साहब को जैसे ही जांच का जिम्मा मिला उन्होंने हनी कांड में शामिल महिलाओं के संपर्क में आए अधिकारियों से बड़े ही भावात्मक लहजे से कहा कि भई...! अगर आपका नाम सामने आ गया तो बीवी-बच्चों को क्या जवाब दोगे? अगर बदनाम हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? अगर चाहते हो कि इस दलदल से तुम्हारा नाम निकल जाए तो मैं जितना चढ़ावा मांगता हूं, उतना मुझे दे दो। बताया जाता है कि ऐसी ही भावनात्मक स्टोरियां सुनाकर साहब ने महिलाओं के संपर्क में आए सर्वजन से खूब वसूली की है। साहब ने वसूली तो कर ली, लेकिन हनी-मनी की जांच कहां गई, यह किसी को नहीं पता। यही नहीं सूत्र बताते हैं कि अगर कोई जांच करने वाले साहब से इस संदर्भ में पूछता है तो वे कुटिलता मुस्कान के साथ कहते हैं- भई...! खेल खतम...पैसा हजम। ऐसे में अब हनी-मनी कांड की जांच किस तरह हुई होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

पावरकट की तैयारी

मप्र में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन मंत्रिमंडल में कांग्रेसी विचारधारा के लोगों का दबदबा है। हालांकि ये लोग भगवा रंग में रंगने का उपक्रम कर रहे हैं। लेकिन इनकी महाराज भक्ति कम नहीं हो रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पूरी सरकार महाराज के पावर के नीचे दबी दिख रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह खबर जोरों पर चल रही है कि खांटी भाजपाई मंत्रियों ने महाराजा के पावरकट की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में एक अलग रणनीति बन रही है कि उपचुनाव में उतने ही प्रत्याशियों को जिताया जाएगा, जितने की सरकार बचाने के लिए जरूरत है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल गठन, विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरह भाजपा संगठन पर दबाव बनाया गया, उससे भाजपा की विचारधारा पर कुठाराघात हुआ है। सूत्र बताते हैं कि रणनीतिकारों ने सरकार और संगठन को संकेत दिया है कि अगर सरकार में महाराज परस्तों की संख्या बढ़ी तो वह आगे के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया है- जितनी सीटों की जरूरत है, उतनों को जिताएंगे। महाराज को पावरफुल होने से बचाएंगे।

दुक्कीबाजों की कमी नहीं

प्रदेश में दुक्कीबाजों की भरमार है। दुक्कीबाज शब्द सुनकर आप चौंक गए होंगे। तो हम आपको बता दें पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के जमाने में इन्हें गरम गोश्त का व्यापारी कहा जाता था। अब इन्हें दुक्कीबाज कहा जाने लगा है। ये दुक्कीबाज क्या करते हैं इसकी पूरी जानकारी पुलिस को रहती है। इनकी पूरी कुंडली पुलिस के पास रहती है। लेकिन वे इनके खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक ये किसी बड़े मामले में फंस न जाए। फिर शुरू होता है इनका सीरियल धमाकों का दौर। ये उक्त दुक्कीबाज पर मुकदमों की इस कदर बारिश करते हैं कि हर कोई आश्चर्यचकित होता है कि आखिरकार यह इतने गोरखधंधे करने के बाद भी अभी तक बचा कैसे रहा। वर्तमान सरकार में जो ताजा मामला चल रहा है या पूर्ववर्ती सरकार में हनी-मनी का जो मामला आया था, सबकी कहानी एक जैसी है। पुलिस प्रशासन को सब मालूम था कि ये लोग किन करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन किसी ने इन पर कार्रवाई नहीं की।

भारत कभी भी विस्तारवाद का पक्षधर नहीं रहा है। विस्तार की उम्र खत्म हो गई है। यह विकास की उम्र है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई हैं।

● **नरेंद्र मोदी**

हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी दवा कोरोनिल कोरोना वायरस का इलाज या उसे नियंत्रित करती है। हमने एक दवा बनाई है, जो कि परीक्षण में कोरोना मरीज के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। हां, हम यह कह सकते हैं कि हमने ऐसी दवाई बनाई है, जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन हमारी बात को अलग तरीके से बताया गया।

● **आचार्य बालकृष्ण**

खिलाड़ियों को जीत और हार के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ खेल को एन्जॉय करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में घर से लेकर स्कूल तक, किसी न किसी रूप में खेल होना बहुत जरूरी है। फिट रहने के लिए खेल जरूरी है। इसलिए हर कोई बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करे। इसी का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं।

● **पीवी सिंधु**

डोनाल्ड ट्रम्प के शासनकाल में अमेरिका की साख गिरी है। कई देश अमेरिका की नीतियों के खिलाफ हैं। दरअसल, ट्रम्प ने बिना सोचे-समझे कई निर्णय लिए हैं। देश में कई आंदोलन हुए हैं, जो घातक सिद्ध हुए हैं। इसका खामियाजा ट्रम्प को भुगतना पड़ेगा।

● **बिडेन**

मैं अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम कर रही हूं। अक्षय के काम में बुद्धिमतता और एक असर दिखता है। मैं उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करती हूं। इस फिल्म में मेरा रोल बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है, मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगी। मैं बहुत रोमांचित हूं कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनी हूं। फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के साथ हुई चंद मुलाकातों में उन्होंने मुझे काफी कम्फर्टेबल कर दिया है। हम दोनों एक-दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जान गए हैं। उम्मीद है कि स्क्रीन पर भी हम दोनों की जोड़ी बेहतर दिखेगी और लोगों को इंप्रेस कर पाएगी।

● **वाणी कपूर**

वाक्युद्ध

हम कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा सरकार गिराने के प्रयास में लगी हुई है। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। भाजपा राजनीति में पतन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन हमारे विधायक उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं।

● **अशोक गहलोत**

राजस्थान के मुख्यमंत्री जगे हुए भी सपने देख रहे हैं। दरअसल, उनकी पार्टी में ही विद्रोह पनप रहा है। विद्रोह को थामने में वे विफल हो रहे हैं। ऐसे में किसी संभावित अनहोनी को देखते हुए वे अभी से भाजपा पर इल्जाम लगाने में जुट गए हैं। पहले भी वे ऐसे आरोप लगा चुके हैं। लोग उनके आरोपों को महत्व नहीं देते हैं।

● **गजेन्द्र सिंह शेखावत**

योग्यता या उपहार

संस्कार भारती का संस्कृति मंत्रालय पर पूरा हस्तक्षेप

राष्ट्रीय स्वंय संघ की सहयोगी संस्था संस्कार भारती का संस्कृति मंत्रालय से जुड़े न्यासों, विभागों और कला अकादमी की नियुक्ति में पूरा दखल होता है। संस्कार भारती की स्थापना ललित कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना लाने के उद्देश्य सामने रखकर की गई है। समाज के वर्गों में कला के जरिए राष्ट्रभक्ति एवं योग्य संस्कार जगाने, विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण व नए कलाकारों को प्रोत्साहन देकर इनके माध्यम से 'सांस्कृतिक प्रदूषण' रोकने के उद्देश्य से संस्कार भारती कार्य कर रही है। इनमें राष्ट्रीय गीत प्रतियोगिता, राष्ट्रभावना जगाने वाले नुक्कड़ नाटक, नृत्य, चित्रकला, काव्य-यात्रा, स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम का आयोजन संस्कार भारती द्वारा किया जाता है।

देश की शिक्षण और संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की लॉबी हावी होती दिखाई दे रही है। संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्तियों पर संघ की छाप नजर आने लगी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा संघ के करीबियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईआईएमसी के महानिदेशक पद और प्रसार भारती के पहले भर्ती के बोर्ड प्रमुख पद पर संघ समर्थित लोगों को बैठाया है। वहीं, संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख संस्थाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ललित कला अकादमी और सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख पदों पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की सिफारिश के लोग बैठाए गए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने संघ के लोगों को शिक्षण व संस्कृति केंद्रों के अहम पदों पर बिठाए जाने की बात को न तो स्वीकार किया न अस्वीकार किया।

संघ विचारक शेषाद्रि चारी कहते हैं कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। कला और संस्कृति से जुड़ी सरकारी संस्थानों में नियुक्ति पूरी योग्यता के आधार पर की गई है न कि किसी संस्था की सदस्यता के आधार पर। अगर वे लोग कोई गलत काम कर रहे हैं या संस्था के अहित में काम कर रहे तो उन पर आरोप लगाया जा सकता है'। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा- 'कला और शिक्षा के क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं इनमें मैरिट के आधार पर लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन संस्थाओं पर काबिज है, क्या वह इन पदों के योग्य हैं। अगर वे अयोग्य होंगे तो स्वाभाविक है वे रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। यह सभी जानते हैं कि भाजपा और इन संस्थाओं का रिमोर्ट कंट्रोल नागपुर में है।' हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का पहला भर्ती बोर्ड स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने भारत प्रकाशन के निदेशक जगदीश उपासने को इस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जगदीश उपासने को राजधानी भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही राज्य की सत्ता पर कमलनाथ सरकार काबिज हुई उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। जगदीश उपासने संघ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के संपादक भी रह चुके हैं।

कुछ दिनों पूर्व ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्वायत संस्था इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी आईआईएमसी का महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी को नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल तीन साल का रहेगा। द्विवेदी कुछ दिन पहले ही मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। प्रोफेसर द्विवेदी शिक्षण के क्षेत्र में आने से पहले सक्रिय पत्रकारिता करते थे। प्रोफेसर द्विवेदी अखिल विद्यार्थी परिषद् से जुड़े रहे हैं। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी नजदीकियां किसी से छिपी हुई नहीं है। मार्च 2020 में राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें पत्रकारिता विवि का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। कुछ दिन बाद ही उन्हें विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति नियुक्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में सदस्य सचिव के पद पर डॉ. सच्चिदानंद जोशी पदस्थ हैं। इसके साथ ही वे भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कमेटी में डॉ. जोशी को सदस्य भी बनाया गया है। आईजीएनसीए में निदेशक (प्रशासन) के पद पर ले.क. (सेवानिवृत्त) आर.ए. रांगणेकर मराठी होने की वजह से ये यहां पदस्थ किए गए हैं। डॉ. हेमलता एस मोहन को सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का अध्यक्ष (सीसीआरटी) बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की सहयोगी संस्था संस्कार भारती के हस्तक्षेप के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। झारखंड की रहने वाली डॉ. हेमलता एस मोहन पूर्व में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकीं हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद् डॉ. हेमलता सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता के सलाहकार पैनल की सदस्य भी रह चुकीं हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे विदेश मंत्रालय की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्ष भी हैं। इसके पूर्व प्रोफेसर लोकेश चंद्रा इस पद 2014 से 2017 तक काबिज थे। चंद्रा के पूर्व कांग्रेस नेता डॉ. करण सिंह 2005 से 2014 तक इस पद पर थे। सहस्त्रबुद्धे फिलहाल मध्यप्रदेश के भाजपा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद भी हैं। एक मराठी होने के चलते संघ के मराठी नेताओं के विश्वासपात्र भी हैं।

● **सुनील सिंह**

सिंधिया ही टाइगर

मप्र की सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को 25 सीटों के उपचुनाव में कम से कम 9 सीटें जीतनी पड़ेंगी। इसके लिए भाजपा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। इसलिए उसने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही पूरा दांव लगा दिया है। इसकी वजह यह है कि 23 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी सिंधिया से जुड़े हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें ही आगे करके उपचुनाव लड़ेगी।

भाजपा आलाकमान का मकसद हर हाल में मध्यप्रदेश में सत्ता हासिल करने का रहा, जिसके चलते कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो डील हुई उसी को अब पूरा किया जा रहा है। नतीजतन सिंधिया खेमे के 9 और मंत्रियों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, दो पहले से ही मौजूद हैं। कांग्रेस की गलती भाजपा कतई नहीं दोहराएगी। सिंधिया को भाजपा में पूरी तवज्जो मिल रही है यानी टाइगर की ही चल रही है और विभागों के बंटवारे में भी यह स्पष्ट हो गया। भाजपा के असंतुष्टों के पास कोई विकल्प भी नहीं है और दो-चार दिन की नाराजगी के बाद पार्टी का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि संगठन काफी मजबूत है। प्रदेश की सत्ता पर लगातार कब्जा बनाए रखने के लिए उपचुनावों में भी जीत हासिल करने पर जोर रहेगा, क्योंकि सभी 22 समर्थक सिंधिया खेमे के ही हैं, जहां उपचुनाव होना है।

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार जिन शर्तों पर बनी उसका पूरा पालन दिल्ली में बैठे पार्टी आलाकमान से लेकर प्रधानमंत्री तक करेंगे, क्योंकि सिंधिया भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने अमित शाह से लेकर मोदी से बकायदा चर्चा की और अपनी सारी शर्तें भी उन्हें बता दीं। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में सिंधिया को पूरी तवज्जो दिल्ली दरबार से दी गई, चाहे भोपाल में बैठे भाजपा के तमाम पदाधिकारी और पूर्व मंत्री लाख हाथ-पैर मारते रहे हों। जो गलती कांग्रेस ने की उसे भाजपा नहीं दोहराएगी और महाराज को पूरी तवज्जो मिलेगी और संभव है कि आने वाले दिनों में शिवराज के विकल्प के रूप में भी महाराज को खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका चेहरा चमकदार है और ग्वालियर, चंबल सहित मालवा-निमाड़ तक की कई सीटों पर उनका अच्छा-खासा असर है। यहां तक कि कांग्रेस के लाख प्रयासों के बावजूद 22 बागी विधायकों में से एक भी नहीं टूटा और वे महाराज के साथ ही बंधे रहे। अभी 25 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर-चंबल संभाग से ही आती है, जिसे जीतने के लिए महाराज की ही जरूरत भाजपा आलाकमान को पड़ेगी। यही कारण है कि पहले राज्यसभा में उन्हें भेजा गया, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी उनके समर्थकों को लिया गया और विभागों के बंटवारे में भी उनका दबदबा कायम रहा। कांग्रेस आलाकमान के उलट भाजपा आलाकमान ने देशभर में सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की रणनीति कुबूल की और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा के विधायक कम जीते वहां भी जोड़-तोड़ कर सरकार बना ली। सिर्फ महाराष्ट्र में ही दांव शरद पवार ने फेल कर दिया और अब जो राज्य कांग्रेस के पास हैं उन्हें भी लगातार इसीलिए डिस्टर्ब किया जा रहा है और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में लगातार गच्चा खाते रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बचाने के भी कोई प्रयास **कांग्रेस आलाकमान ने नहीं किए।** इसकी तुलना में भाजपा आलाकमान से लेकर संघ सहित पूरा संगठन इसमें भिड़ गया और सरकार गिराकर अपनी बना ली। भोपाल आए सिंधिया ने भी लंबे समय बाद मुंह खोला और उनके खिलाफ हो रही बयानबाजी का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है... कांग्रेस की इतनी क्षमता नहीं है कि वह 10-15 भाजपाई विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर ले, क्योंकि केंद्र में भी उसकी हालत पतली है। लिहाजा असंतुष्टों के पास कोई विकल्प नहीं है। दो-चार दिन की नाराजगी के बाद मन मारकर उन्हें भाजपा का ही झंडा उठाए रखना पड़ेगा और प्रदेश की राजनीति में अब सिंधिया को कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में तवज्जो मिलती नजर आएगी।

उपचुनावों में भाजपा का ही रहेगा पलड़ा भारी

25 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 23 सीटें तो बागी कांग्रेसियों की हैं, जिस पर सिंधिया समर्थकों को ही भाजपा को टिकट देना पड़ेगा। बहुमत के आधार पर भी कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कमजोर है। वहीं कांग्रेस को सरकार में लौटने के लिए 23 सीटें जीतना जरूरी है, जो कि फिलहाल असंभव ही है और भाजपा को सत्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ 9 सीटों की ही जरूरत है, इसकी तुलना में वह दोगुनी से अधिक सीटें जीत लेगी। यही नहीं भाजपा के सभी नेताओं ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। कुछ वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो कुछ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस अभी भी चुनावी मोड में नजर नहीं आ रही है।

भाजपा में बने अब पांच पॉवर सेंटर

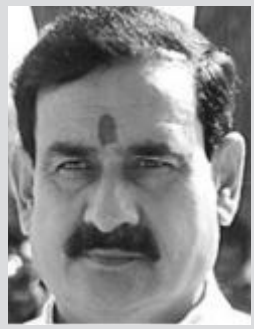

कुलीनों की पार्टी का तमगा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अप्रत्याशित रूप से बदलाव दिख रहा है। यही वजह है कि इस दल और सरकार में पहले संगठन ही सर्वोपरि होकर एकमात्र पॉवर सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद सूबे के सत्ता में अप्रत्याशित रूप से वापसी करने वाली भाजपा में अब एक-दो नहीं बल्कि पांच-पांच पॉवर सेंटर बन गए हैं। यही नहीं अब प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में पूरी तरह से सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बदले हुए समीकरणों में अब अंदर ही अंदर भाजपा संगठन व सरकार में वर्चस्व की अंदर ही अंदार जंग शुरू हो चुकी है, वहीं मप्र कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ही एकमात्र पॉवर सेंटर बना हुआ है। दरअसल आज भी प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जितने बड़े कद का कोई नेता नहीं है। कमलनाथ सरकार के बाहर होने के पहले तक ग्वालियर-चंबल संभाग में भाजपा के फैसले आरएसएस, पार्टी संगठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की राय से होते रहे हैं। अब परिस्थिति बदल चुकी है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर हर छोटे-छोटे मसलों पर भी निर्णय में देरी साफ-साफ देखी जा सकती है। पूर्व में भाजपा की सरकार व संगठन में शिवराज व तोमर ही पॉवर सेंटर रहा करते थे। इनमें भी शिवराज सिंह व तोमर के बीच तालमेल होने की वजह से वे कभी भी अलग-अलग नजर नहीं आए हैं। फिलहाल अब शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा के रूप में यह पॉवर सेंटर दिख रहे हैं।

कमलनाथ सरकार को सत्ता से बाहर करने के सियासी ऑपरेशन में बेहद बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के कद में यकायक वृद्धि हुई है। इसके पहले भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी होने की वजह से उन्हें ताकतवर बनने में मदद मिली है। कमलनाथ सरकार को बाहर करने के मुख्य किरदार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भाजपा संगठन में अहम महत्व मिलने से वे भी नए शक्ति केंद्र बन चुके हैं। अपने पहले के कद की वजह से उनकी भी एक अहम हैसियत है और सरकार बनवाने का असली श्रेय भी उन्हीं को जाता है। यही वजह है कि **अपने अभियान** के सहयोगियों को उपकृत कराने में वे पूरी तरह से सफल रहे हैं। सत्ता के अलावा संगठन में पकड़ मजबूत करने वालों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी चेहरा उभरकर सामने आया है। संगठन के मुखिया होने के नाते से उनकी पंसद-नापसंद का असर साफतौर पर दिखाई दिया है। इस वजह से अफसरों की तैनाती से लेकर कई फैसलों में सरकार में असमंजस की स्थिति दिखाई दी है।

कुछ माह पहले तक कांग्रेस में सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अलग-अलग पंसद और नापसंद का ध्यान रखना पड़ता था। पार्टी आलाकमान भी इसी को मद्देनजर रखकर फैसला करता था। टिकट बंटवारे से लेकर हर महत्वपूर्ण मामलों में दिग्विजय-सिंधिया के बीच रार सामने आती रही है। कई बार तो यह सार्वजनिक भी हो जाती थी और कभी नेतृत्व के स्तर पर ही इसे सुलझा लिया जाता था। अब सिंधिया कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं, लिहाजा संगठन में दिग्विजय की ताकत में भारी वृद्धि हुई है और उनके फैसले की अहमियत भी बढ़ चुकी है। खासतौर पर अब ग्वालियर-चंबल संभाग में उनका ही बोलबाला हो गया है। मध्यप्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा में संगठन ही फैसले लेता है। नेता और कार्यकर्ता सभी संगठन के फैसलों के अनुरूप ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे यहां गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई जैसी कोई बात नहीं है। मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस का मुखिया होने के नाते सभी फैसले कमलनाथ लेते हैं। उन्होंने उपचुनाव के लिए सर्वे कराकर प्रत्याशियों को चिन्हित कर दिया है। अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

उपचुनाव जीतने में शिवराज को महारत

पिछले दो दशकों से इंदौर में ताई-भाई की राजनीति चलती रही, जिसके कारण भोपाल से दिल्ली तक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, आलाकमान और संघ पदाधिकारियों के भी कान पक गए। टिकट वितरण से लेकर मंत्रिमंडल सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में ताई-भाई का विवाद सुर्खियों में रहा, लेकिन पार्टी आलाकमान ने होशियारी से ताई को टिकट भी नहीं दिया और एक तरह से हाशिए पर ला दिया। अब इसी तरह की स्थिति विजयवर्गीय की भी नजर आ रही है। प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के तहत आने वाली जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना हैं, वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के 20 फीसदी मतदाता होने की वजह से भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर इस वर्ग पर लगी हुई है। यही वजह है कि इस अंचल की उपचुनाव वाली सीटों पर जीत तय करने के लिए इन दोनों ही दलों के रणनीतिकार जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि इन सीटों पर पूरी तरह से दलित एजेंडा चलेगा। दरअसल इस बार उपचुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां काफी अलग हैं। यही उपचुनाव तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। इस अंचल के तहत आने वाली 4 सीटों पर यह वर्ग निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि बीते चुनाव में डबरा-करैरा सीट पर बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर रह चुके हैं। जातीय समीकरणों को देखते हुए ही बसपा ने पहली बार उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर बसपा की रणनीति सरकार बनने का गणित बिगाड़ने की रहने वाली है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने चेहरे उपचुनाव में अब भाजपा के टिकट पर वोट मांगते नजर आने वाले है।

शहर और गांवों के साथ ही अब वन क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। इसका असर नक्सलियों पर भी पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार देशभर में एक सैकड़ा से अधिक नक्सली कोरोना की चपेट में आए हैं। इन नक्सलियों को गांवों में वापस भेज दिया गया है।

नक्सलियों में कोरोना संक्रमण

दंडकारण्य के जंगलों में सक्रिय नक्सलियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। खुफिया विभाग के अनुसार, मप्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के वन क्षेत्र में सक्रिय एक सैकड़ा से अधिक नक्सलियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें नक्सली नेताओं ने अपने गांवों में रहने के लिए भेज दिया है। इस सूचना के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस को डर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित ये नक्सली गांवों में अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं।

पुलिस विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया से मिले इनपुट के बाद तीनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर संक्रमित माओवादियों की तलाश शुरू कर दी है। मप्र पुलिस ने बालाघाट सहित अन्य जिलों में अपने **मुखबिरों को सक्रिय** कर दिया है। वे कोरोना संक्रमित नक्सलियों की सूचना जुटाने में लग गए हैं। मप्र पुलिस 15-20 ऐसे माओवादियों की तलाश कर रही है जिन्हें वह मेडिकल सुविधा दिलाना चाहती है। ये वे माओवादी हैं जिन्हें कोविड-19 संक्रमण के शक में उनके नक्सली नेताओं ने अपने कैडर से अलग कर दिया है और अब वो अपने गांवों में छुपकर रह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी विरोधी अभियान में लगी पुलिस को सूचना मिली है कि 15-20 ऐसे माओवादी हैं जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अब अपने घरों में आकर रह रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनका पता लगाया जा रहा है और सभी को गिरफ्तार कर क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। इनकी कोविड-19 जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नक्सल अभियान में लगे एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक पुलिस को 15-20 ऐसे माओवादियों की जानकारी मिली है जिन्हें कुछ दिनों पहले नक्सल संगठन से अलग कर घर भेज दिया गया है। अपने गांवों को लौटे ये सभी नक्सली बीमार हैं और चुपचाप अपने घरों में रह रहें हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही सभी की तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और उनकी कोरोना जांच की जाएगी। वह कहते हैं कि अगर संक्रमित नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई तो वन क्षेत्र के गांवों में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा।

पुलिस ने नक्सली संगठन में रह रहे दूसरे माओवादियों और वन क्षेत्र के गांवों के लोगों से अपील की है कि वे बीमारों के बीच से बाहर आकर नियमानुसार आत्मसमर्पण करें जिससे कि उनका इलाज कराया जा सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने 17 जून को बीजापुर जिले में एक बीमार महिला नक्सली को उसके गांव से गिरफ्तार कर क्वारेंटाइन सेंटर में रखा है। पुलिस के अनुसार महिला माओवादी सुमित्रा चापा पिछले डेढ़ महीने से बीमार चल रही थी। उसे बुखार, खांसी और सर्दी की लगातार शिकायत थी। उसने पुलिस को जानकारी दी है कि नक्सली संगठन में बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में हैं।

इधर, मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और आसपास के इलाकों में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने की जानकारी मिल रही है। पुलिस की खुफिया जानकारी के मुताबिक जुलाई के शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बढ़ाने और अपना वर्चस्व कायम करने की फिराक में भी बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद नक्सली मध्य प्रदेश को अपनी पनाहगार बना रहे हैं। इन दिनों पेंच-कान्हा कॉरिडोर से नक्सली संगठन छत्तीसगढ़ से बालाघाट में प्रवेश कर मंडला-अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। बालाघाट के बैहर और मंडला के बिछिया-मवई तहसील में ग्रामीणों ने पुलिस को भी संदिग्ध लोगों को देखे जाने की सूचना दी है। बारिश से पहले भी इन क्षेत्रों में नक्सलियों ने शरण ली थी, तब नदी में पानी ज्यादा होने के कारण नक्सलियों के लिए सुरक्षित इलाका बन गया था। पिछले कई सालों से प्रदेश में नक्सलियों की जड़ें कमजोर हुई हैं। नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं। पुलिस भी इसके लिए रोजाना एरिया डोमिनेशन करवा रही है। लगातार नक्सल प्रभावित चौकियों को अलर्ट पर रखा गया हैं।

● **रजनीकांत पारे**

ऑपरेशन मानसून को फोर्स तैयार, हाईकोर नक्सली होंगे निशाने पर

यह बारिश एक बार फिर नक्सलियों को भारी पड़ने वाली है। पुलिस ऑपरेशन मानसून का ब्लू प्रिंट तैयार कर चुकी है। नक्सलियों के बड़े लीडर निशाने पर होंगे। ऑपरेशन के लिए कमांडो भी तैयार किए गए हैं। कई बड़े नक्सली और उनके नेता फोर्स के दबाव में इलाके से पहले ही पलायन कर चुके हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि पुलिस को उनकी लोकेशन लगातार मिल रही है। वह उनकी हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

भीगे गेहूं का क्या होगा?

मप्र में इस बार गेहूं का रिकार्ड उत्पादन और खरीदी हुई है। एक तरफ जहां गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान मालामाल हुए हैं, वहीं गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में ओपन कैप में लाखों मीट्रिक टन गेहूं रखा गया है। सरकार का दावा है कि यह गेहूं पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने ओपन कैप में रखे गेहूं को उठाने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह गेहूं भीग गया है और हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भीगे गेहूं का क्या होगा?

गौरतलब है कि इस साल गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश देश में सिरमौर बना है। मप्र ने 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदकर पंजाब के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। समर्थन मूल्य पर की गई गेहूं की खरीदी और उसके बाद उसके भंडारण को लेकर मध्यप्रदेश से कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण ओपन कैप में ही अधिकांश गेहूं का भंडारण कर दिया गया।

उधर, इस साल गेहूं की रिकॉर्ड खरीद करने के बाद एफसीआई ने माल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि वो सिर्फ गोदाम में रखा माल ही उठा रहा है। खुले में रखे गेहूं को उसने हाथ भी नहीं लगाया। साथ ही एक महीने पहले खरीदा गया माल ही उठाया जा रहा है। दरअसल इस साल मप्र में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के बाद हुई बारिश के कारण खुले में रखा लाखों मीट्रिक टन गेहूं भीग गया है। शायद यही वजह है कि एफसीआई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हैरानी की बात तो यह है कि एफसीआई अधिकांश जगह से एक माह पुराने गेहूं को ही उठा रहा है। एफसीआई की मनमानी सरकार पर भारी पड़ सकती है।

वहीं इस व्यवस्था से वेयर हाउस संचालक बेहद परेशान हैं। उनका मानना है कि एक तो कर्ज लेकर वेयर हाउस बनवाया, 1 साल का अनाज का इंश्योरेंस भी करा लिया गया। इनकी परेशानी ये है कि एफसीआई एक महीने पहले रखा गया गेहूं ही उठा रहा है। ऐसे में पुराने अनाज का क्या होगा। वेयरहाउस संचालक इस पूरी प्रक्रिया में पहले भी बड़े घोटाले का अंदेशा जता चुके हैं और अब जब एफसीआई ने भी खुले में पड़े **गेहूं को अमानक बता दिया** है तो कहीं ना कहीं उनको इन आरोपों पर दम भरता दिख रहा है।

उधर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार इस मामले में जांच कराने की बात कह रही है। सरकार का कहना है कि एफसीआई अपने तय मापदंड के अनुसार ही माल उठाता है। लेकिन फिर भी इसी साल खरीदा गया गेहूं अगर एफसीआई के मानकों में फिट नहीं बैठ रहा है तो इसकी क्या वजह है। क्या गेहूं का भंडारण नहीं हुआ या अधिकारियों ने कोई गलती की है। बारिश अपनी आमद दे चुकी है और अभी भी माल ओपन कैप में रखा है। तो क्या जिम्मेदार अधिकारी इसके सड़ने के इंतजार में हैं जिसके बाद इसे कौड़ियों के दाम नीलाम किया जाएगा। जो भी हो लेकिन लापरवाही के चलते सरकार को करोड़ों की चपत जरूर लग सकती है।

उधर, अधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदामों में रखा अनाज यदि समय पर रिलीज नहीं हुआ तो खरीफ फसल के दौरान समस्या आ सकती है। वर्तमान में गेहूं के साथ वेयरहाउस के गोदामों में चना भी रखा हुआ है। इस साल बंपर पैदावार के कारण गोदामों की कमी आ गई है। इसके कारण लाखों क्विंटल गेहूं खुले मैदान में रखना पड़ा है। वर्तमान में हालात यह हैं कि जितने भी ओपन कैप बनाए गए थे सभी भर चुके है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट ओपन कैप भी किराए पर लेना पड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार जहां किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए संकल्पित रही, वहीं उसने किसानों से खरीदे गेहूं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की है, लेकिन एफसीआई ने ओपन कैप में रखे गेहूं उठाने से मना कर दिया है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में इस बार जितना गेहूं खरीदा गया वो पिछले साल के मुकाबले 75 फीसदी से भी ज्यादा है। मध्यप्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है जो पूरे देश का 33 प्रतिशत से ज्यादा है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई। इस मामले में मप्र ने पंजाब को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। पिछले साल की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल मध्यप्रदेश में 73.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। मध्यप्रदेश में इस बार 15 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी जो 5 जून को खत्म हुई। गेहूं का ज्यादा उत्पादन होने के कारण इस बार खरीदी केंद्र भी 3 हजार 545 से बढ़ाकर 4 हजार 529 कर दिए गए हैं।

● **अरविंद नारद**

एफसीआई गोदाम से उठाएगा गेहूं

अब जब एफसीआई मध्य प्रदेश भर में निरीक्षण कर रही है तो उसने इसी साल खरीदे गए 129 लाख मैट्रिक टन गेहूं में से गोदामों में रखा गेहूं खरीदना ही मुनासिब समझा है। आलम यह है कि एफसीआई ओपन कैप में रखे गेहूं को छोड़कर गोदामों में रखे गेहूं को ही मानक के अनुसार मान रही है। मध्यप्रदेश के मंदसौर में तो गोदामों से एफसीआई ने गेहूं उठाना शुरू भी कर दिया है और कई जगह सर्वे का काम चल रहा है। गौरतलब है कि ठीक मार्च महीने के पहले मध्यप्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने को मिल रही थी चिंता जायज भी थी जब अफवाहें अपने चरम पर थी कि इस बार मंडियों में गेहूं किस प्रकार तौला जाएगा। कोविड-19 की भयावह तस्वीरों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सचमुच चिंता में डाल दिया था कि गेहूं तौलना तो दूर खरीदेगा कौन? व्यापारी क्या बोली लगाने आएंगे? या इस परिस्थिति का फायदा उठाकर कहीं फसल के मूल्य से भी समझौता न करना पड़ जाए। लेकिन सरकार की सक्रियता और सुविधाओं के कारण इस साल प्रदेश ने देश में सबसे अधिक गेहूं खरीद का रिकार्ड बनाया है।

हाशिए पर शिक्षा

विश्वभर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसी परिस्थितियों में स्कूली छात्रों के अभिभावकों की चिंताओं ने भी विश्वव्यापी मुद्दे का रूप ले लिया है। यूनेस्को का अनुमान है कि कोरोना के कारण विश्व के करीब 190 देशों में किए गए लाकडॉउन के चलते शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने का करीब 154 करोड़ छात्रों पर गंभीर असर हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने से छात्रों की शिक्षा व कुशलता पर अभूतपूर्व असर देखा जा रहा है, विशेषतौर पर हाशिए पर रहने वाले तबकों के बच्चों पर जो कि अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यत: स्कूलों पर ही आश्रित हैं। इस समय सरकारों, शिक्षण संस्थान व अभिभावकों के बीच यह बहस जोरों पर है कि जब कोरोना का कोई कारगर उपचार नहीं है, तो ऐसे समय में बच्चों की पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूल कॉलेज कब खोले जाएं?

भारत में स्कूल कब खुलेंगे? इसे लेकर बराबर कयास लगाए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस मुद्दे पर राज्य के मंत्रियों व शिक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुका है। एक कयास यह भी लगाया गया कि भारत में जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं और अभिभावकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अभिभावकों ने किसी राज्य में मामले शून्य होने या टीका आने तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की मुहिम छेड़ दी है। पैरेंट्स एसोसिएशन के चेंज डॉट आर्ग पर शुरू ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान को कई लाख अभिभावकों का समर्थन मिला है। गौरतलब है कि **कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम** के लिए उठाए गए उपायों के तहत देशभर में 16 मार्च से 1.5 लाख स्कूल बंद हैं और करीब 25 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने से प्रभावित हैं। देश में स्कूल कब खुलेंगे? इसे लेकर बेशक अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। इसके चलते यह फैसला लेना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र में अब तक स्कूल नहीं खुल पाए। सितंबर से स्कूल खुलने की संभावना है। ऐसे में विभाग प्रारूप को अंतिम रूप देने में लगा है। अभी ऑनलाइन कक्षा लगाकर पढ़ाई कराई जा रही है। अब स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है। छह चरणों के प्रारूप के तहत इस साल स्कूल खुलने पर न तो प्रार्थना सभा होगी और ना ही वार्षिकोत्सव का आयोजन होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन तैयार कर शासन से अनुमति लेने के लिए प्रारूप तैयार कर भेज दिया है। कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विभाग ने अपनी गाइडलाइन का ड्राफ्ट शासन को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और विद्यार्थियों, अभिभावक व शिक्षकों के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। सम व विषम संख्या में विद्यार्थियों को बांटकर एक दिन छोड़कर बुलाया जाएगा।

विभाग ने प्रारूप में यह तय किया है कि कक्षा में विद्यार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 15 या 20 विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थियों को सम-विषम के आधार पर बुलाया जाएगा, लेकिन गृह कार्य प्रतिदिन देना होगा। कोई भी विद्यार्थी अपनी सीट न बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा। कक्षा को रोजाना सैनिटाइज करना होगा, यह सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने-पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। सभी को अपना पानी साथ लाना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सुरक्षित शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा।

देश में सरकारी स्कूलों में एक ही सेक्शन में इतने बच्चे होते हैं कि सामाजिक दूरी वाले नियम का पालन कैसे कराया जाएगा? यह बहुत अहम सवाल है। दरअसल सरकार भी इस मुद्दे पर पसोपेश में है। पैरेंट सर्कल के एक सर्वे में खुलासा किया गया कि अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। राधिका के दो बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। उनका मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल में जाकर पढ़ने से बच्चे का विकास कई तरह से होता है; लेकिन अगर हालात इस पक्ष में नहीं है। ऐसे में बच्चों के हित में हमें कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि बच्चों की उम्र यह सब सोचने-समझने और निर्णय लेने की नहीं है। 'नो वैक्सीन, नो स्कूल' मुहिम के बीच ही अमेरिका में शीर्ष वैज्ञानिकों की इस मुद्दे पर राय जानी गई, तो 70 फीसदी वैज्ञानिक सितंबर-अक्टूबर से पहले स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी राय में इससे पहले स्कूल-कॉलेज खोलना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सार्वजनिक संस्थानों को तो खोला जा सकता है; लेकिन बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता।

● **जितेन्द्र तिवारी**

सीबीएसई बोर्ड कम कर रहा 30 प्रतिशत सिलेबस

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव न रहे इसको लेकर शिक्षा सत्र 2020-21 में सीबीएसई ने 30 फीसदी सिलेबस कम करने का निर्णय लिया है। इधर, प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। उल्टे मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6वीं के सिलेबस में तीन नए टाइटल जोड़ दिए हैं। इसके चलते विद्यार्थियों को चालू शिक्षा सत्र में 6 की जगह पर 8 विषय की पढ़ाई करनी होगी। कक्षा 6वीं में पहले 6 विषय की पढ़ाई कराई जाती थी। अब विद्यार्थियों को 8 विषय पढ़ना होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बीच अचानक 6वीं कक्षा के बढ़े विषय को लेकर शिक्षक भी अचंभित हैं।

10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण करते हुए ऐलान किया कि मप्र सौर ऊर्जा का हब बनेगा। गौरतलब है कि मप्र के रीवा के गुढ़ में यह सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है।

सौर ऊर्जा का हब मप्र

सोलर एनर्जी 21वीं सदी में ऊर्जा का एक बड़ा माध्यम बनने जा रही है। ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। श्योर इसलिए कि जब सभी संसाधन खत्म हो जाएंगे, सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। प्योर इसलिए, क्योंकि इससे पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित और साफ-सुथरा बना रहेगा। सिक्योर इसलिए कि इससे बिजली की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। जैसे-जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं-आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट के लोकार्पण अवसर पर कही। यह मप्र के लिए गौरव की बात है कि यह प्लांट रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित है।

सौर परियोजना से उत्पादित बिजली की लागत ताप और जल विद्युत उत्पादन से जहां कम होती है वहीं इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। मध्यप्रदेश में भी नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता देने की रणनीति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व कार्यकाल में प्रारंभ हुई। मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में सिरमौर बन गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में रीवा सौर परियोजना शामिल है। लगभग 4 हजार करोड़ की लागत से 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना में पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा पांच हजार मेगावाट की 6 परियोजनाएं और निर्माणाधीन हैं। रीवा सौर परियोजना के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया। इस परियोजना को राज्य-स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में चयनित किया गया। इस परियोजना में उत्पादित विद्युत का न्यूनतम टैरिफ 2 रुपए 97 पैसे यूनिट था, जो समकालीन परियोजनाओं से प्राप्त टैरिफ साढ़े चार से पांच यूनिट की तुलना में डेढ़ से दो रुपए तक कम था।

रीवा सौर परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76 प्रतिशत अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यवसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की गई। आंतरिक ग्रिड समायोजन के लिए और वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की पहली परियोजना है। विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना और क्लीन टेक्नालॉजी फंड (सीटीएफ) के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। रीवा सौर ऊर्जा परियोजना न केवल प्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों एवं व्यवसायिक संस्थानों को बिजली प्रदान करने में अग्रणी रखेगी। मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा की 5 हजार मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। प्रदेश की पहली रीवा सौर परियोजना के लिए गठित कंपनी रम्स द्वारा आगर, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, ओंकारेश्वर तथा मुरैना में स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया है। आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, छतरपुर में 1500 मेगावाट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग ओंकारेश्वर बांध स्थल पर 600 मेगावाट और मुरैना में 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पार्कों की स्थापना की कार्यवाही चल रही है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में मप्र सौर ऊर्जा का हब बनेगा।

● **लोकेश शर्मा**

रूफ टॉप पर सौर ऊर्जा

प्रदेश में अब तक 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष प्रदेश के 700 शासकीय भवनों पर 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप लगाना प्रस्तावित है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों से उत्पादित बिजली की दरें एक रुपए 38 पैसे प्राप्त हुई। सरकार का प्रयास है कि रूफ टॉप संयंत्र घर-घर लगाए जाएं ताकि उपयोग के लिए बिजली सस्ती दरों पर मिले। शासकीय भवनों पर सौर संयंत्र ऐसे मॉडल पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हितग्राही को विभाग अथवा संस्था को कोई पैसा नहीं देना है। संयंत्र विकसित करने वाला सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल के निकट मंडीदीप में 400 औद्योगिक ईकाइयों के लिए 32 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे उद्योगों को सस्ती बिजली मिलने से औद्योगिक क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक लाख मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा और मध्यप्रदेश देश का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।

मनरेगा, जरूरी या मजबूरी

कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत। इन दिनों मनरेगा को हम तिनके का सहारा कह सकते हैं। सरकार के लिए भी और कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन में बेरोजगार होकर शहरों से अपने-अपने गांव लौट चुके मजदूरों के लिए भी। मप्र सरकार ने तो मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम बना लिया है। लेकिन मप्र में अभी हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 15,088 लोग ऐसे हैं जो 90 साल की उम्र में भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि अधिकारी-कर्मचारी मिलकर किस तरह इस योजना में घालमेल कर रहे हैं।

मप्र सहित देशभर में 14 साल पुरानी मनरेगा योजना एक बार फिर चर्चा में है। लगभग हर राज्य में मनरेगा के प्रति ग्रामीणों के साथ-साथ सरकारों का रूझान बढ़ा है। मनरेगा के तहत काम की मांग पिछले दो माह से लगातार तेजी से बढ़ रही है, जो यह साबित करता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मनरेगा कितना महत्व रखती है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार भी खूब होता है। इस योजना का भूतकाल भ्रष्टाचार की कालिख से पुता हुआ है। मप्र में तो मनरेगा में हर स्तर पर भ्रष्टाचार का अपना रिकॉर्ड है। लॉकडाउन के बाद दूसरे प्रदेशों और **शहरों से बेरोजगार होकर** गांव पहुंचे श्रमिकों के मनरेगा बड़ा संबल बना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 47,03,069 मजदूर कार्यरत हैं। इनमें 3,48,659 मजदूर 61 वर्ष से ऊपर के हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें 15,088 मजदूर 90 वर्ष के ऊपर के हैं। ये आंकड़े मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाते हैं। सवाल उठता है कि जिस उम्र में लोग अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ रहते हैं उस उम्र में 15,088 वयोवृद्ध मनरेगा में मजदूरी कैसे कर पाते होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व में स्वर्गवासी हो चुके लोगों को भी मनरेगा में काम करते दर्शाया जा चुका है।

लहार विधायक एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है। वह कहते हैं कि ग्वालियर-चंबल संभाग में मनरेगा के तहत कोई मजदूर नहीं है फिर भी करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। जहां उपचुनाव होने है, उन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के काम दिए गए हैं। पूर्व मंत्री कहते हैं कि मनरेगा योजना में कोरोना महामारी की आड़ में अप्रैल से जून तक 41 करोड़ 18 लाख 91 हजार फर्जी आईडी से बोगस संस्थाओं को भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में 75 करोड़ 55 लाख 17 हजार का भुगतान हुआ। जबकि अधिकांश स्थानों पर काम हुए ही नहीं। गोहद के ऐनों पंचायत सरपंच ने तो 2017 में जिपं सीईओ को शिकायत की थी कि जानकारी के बगैर मशीनों से मनरेगा के तहत दो रोड व तालाब का बोगस कार्य कराकर 6 लाख 65 हजार 200 रुपए का भुगतान कराया गया है। सुहास ग्राम पंचायत में सरपंच व प्रभारी सचिव ने मनरेगा में करोड़ों रुपए बिना काम कराए भुगतान कराया है। यहीं अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना के तहत सीसी रोड व नाली निर्माण का **दोबारा वर्तमान सरपंच व प्रभारी** द्वारा फर्जी भुगतान कराया गया। इसके अलावा स्व कराधान योजना व महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना में गड़बड़ी की गई। इसी प्रकार रायपुरा, इमलाहा, तैतपुरा गुढ़ा में मशीनों से कार्य कराए गए। वह कहते हैं कि इसी तरह पूरे प्रदेश में मनरेगा में मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है।

एक तरफ सरकार प्रदेश लौटे हर मजदूर को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ पंचायतों में कागजी मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं मनरेगा मस्टर्स ने इस आपदा को भी भ्रष्टाचार का अवसर बना लिया है। आलम यह है कि स्पॉट पर काम कर रहे हैं 40-50 मजदूर और मस्टर में दिखाया जा रहा है 70-90 का नाम। काम पर न आने वालों को गैरहाजिर दर्शाए बगैर मस्टर जारी कर बड़े-बड़े बयान दिए जा रहे हैं। काम कराने वालों की चांदी अलग से। इस तरह से मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल को इस आपदा में भी अवसर के रूप में तब्दील कर लिया गया है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश में मनरेगा का काम शुरू कराया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत पंचायतों में अलग ही गोरखधंधा चल रहा है।

● **विकास दुबे**

अधिकतम उम्र की सीमा नहीं

दरअसल, मनरेगा में अधिकतम उम्र की सीमा का जिक्र नहीं है। इसका फायदा उठाकर अधिकारी-कर्मचारी और सरपंच भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को 62 वर्ष की उम्र में वृद्ध मानकर सेवानिवृत्त कर देती है, लेकिन मनरेगा में मजदूरों की सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं है। श्रमिक का कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आयु के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं है। इसी का फायदा उठाकर उम्रदराज लोगों को भी मनरेगा का मजदूर दिखाया जा रहा है। ऐसे ही 15,088 मजदूर 90 साल की आयु में काम कर रहे हैं जबकि तीन लाख से ज्यादा मजदूर 61 से 80 साल के हैं। ये आंकड़े गले नहीं उतर रहे हैं परंतु मनरेगा की वेबसाइट और अधिकारियों का दावा है कि योजना में इतने उम्रदराज मजदूर भी कार्यरत हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले इन मजदूरों को सिर्फ पानी पिलाने और कार्यों की देखरेख करने की मजदूरी दी जाती है। विभागीय जानकारी के अनुसार, सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले और काम मांगने वालों की उम्र के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बना रखी हैं। इसकी शुरुआत 18 से लेकर 80 वर्ष व उससे अधिक तक मानी गई है। पहली श्रेणी 18 से 30 वर्ष तक, दूसरी श्रेणी 31 से 40 वर्ष तक, तीसरी श्रेणी 41 से 50 वर्ष तक, चौथी श्रेणी 51 से 60 वर्ष तक, पांचवीं श्रेणी 61 से 80 वर्ष तक और अंतिम श्रेणी 80 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों की है। प्रदेश में 80 से 90 साल के बीच के करीब 3 हजार मजदूर फिलहाल कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 190 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है।

11 लाख कुपोषित

सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे धार जिले में

केंद्र और प्रदेश सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए बड़े-बड़े फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। उसके बावजूद मप्र में कुपोषण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में 5 साल से छोटी उम्र के 42 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। प्रदेश में सबसे अधिक कुपोषण धार जिले में बढ़ा है। यहां 58 हजार 649 कुपोषित बच्चे मिले हैं। वहीं बड़वानी में 50 हजार 714, खरगोन-41 हजार 774, अलीराजपुर 32 हजार 641, मुरैना में 38 हजार 421 और गुना-26 हजार 229 बच्चे कम और अति कम वजन वाले पाए गए हैं। वहीं रीवा-सतना-सीधी, दमोह-सागर, रतलाम और उज्जैन जिले में भी 20 हजार से ज्यादा बच्चे कम और अति कम वजन वाले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में 92 हजार 343 आंगनवाड़ी संचालित हो रही हैं। 95 हजार 350 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन आंगनवाड़ी केंद्रों में किया गया है।

कुपोषण मुक्त होने के लाख दावे-वादे और घोषणाएं की जाएं परंतु विभागीय आंकड़े सबकी पोल खोलकर रख रहे हैं। साल 2019 दिसंबर में पूरे प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कम वजन और 1 लाख से ज्यादा अति कम वजन वाले सामने आए हैं। मतलब साफ है कि प्रदेश में कुपोषण थम नहीं रहा है। जनवरी 2020 में कम वजन वाले 12 हजार से ज्यादा तो 1573 बच्चे अति कम वजन वाले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण लगातार पैर पसार रहा है। साल 2017 से लेकर 2019 तक की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे कम और अति कम वजन वाले दर्ज किए गए हैं। 2020 में विभाग पोर्टल पर आंकड़ा दर्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने काम ही नहीं किया है।

मध्यप्रदेश कुपोषण और महिला अपराध में नंबर एक पर है फिर उसके हिस्से की राशि प्रदेश सरकार से खर्च नहीं हुई है। पिछले चार साल में करीब पौने तीन सौ करोड़ सरकार से खर्च ही नहीं हुए। पोषण अभियान के तहत साल 2017-18 से 2019-20 तक 378 करोड़ से ज्यादा का फंड प्रदेश को मिला लेकिन इस फंड का आधा हिस्सा भी बच्चों के पोषण के काम नहीं आया। इसके साथ ही महिला अपराध के तहत मिली राशि का एक चौथाई हिस्सा ही प्रदेश में खर्च हो पाया। निर्भया योजना के तहत आए फंड को खर्च करने में भी सरकार ने ज्यादा रूचि नहीं दिखाई है। इस स्थिति के चलते सरकार की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश सालों से महिला अपराध और कुपोषण के मामले में देशभर में कुख्यात रहा है।

कुपोषित बच्चों को पोषण देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में 378 करोड़ 44 लाख रुपए का फंड भेजा। साल 2017-18 में 40.67 करोड़ रुपए, साल 2018-19 में 158.94 करोड़ रुपए और इस साल यानी साल 2019-20 में 178.83 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को भेजे। इन तीन सालों में प्रदेश में सिर्फ 124.04 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इन सालों में 254 करोड़ रुपए का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। महिला सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर बनाने के लिए फंड मुहैया कराती है। इन सेंटर्स में पीड़ित महिलाओं को मदद दी जाती है ताकि उनका बेहतर पुनर्वास हो सके और वे समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल हो सकें। प्रदेश में इस काम में भी कोई विशेष रूचि नहीं ली गई। केंद्र सरकार ने प्रदेश को वन स्टॉप सेंटर्स के लिए साल 2016-17 में 7.33 करोड़ रुपए दिए जिसमें से 6.45 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। साल 2017-18 में 1.31 करोड़ रुपए दिए गए लेकिन खर्च महज 51 लाख रुपए का हो सका। साल 2018-19 में 11 करोड़ रुपए मुहैया कराए जिसमें से 1.17 करोड़ का खर्च दिखाया गया। साल 2019-20 में 12 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया गया। इस तरह कुल 31 करोड़ रुपए में से सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही इसमें खर्च किए गए।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को केंद्र ने पुरस्कृत भी किया है। साल 2017-18 में इस योजना का प्रदर्शन कमजोर था इस साल 123 करोड़ रुपए में से सिर्फ 57 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। लेकिन इसके बाद नई सरकार ने इस योजना पर भरपूर पैसा खर्च किया। साल 2018-19 में 185 करोड़ केंद्र से मिले जबकि प्रदेश सरकार ने 337 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। इसी तरह साल 2019-20 में 237 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए जबकि प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा मिलाकर इस योजना पर 557 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की।

मप्र में कुपोषण किसी आपदा से कम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां हर दिन करीब 92 बच्चे कुपोषण के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कुपोषण कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। अभी तक चुनावी सभाओं में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने कुपोषण का नाम तक नहीं लिया है। जबकि यथार्त तो यह है कि देशभर में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्यप्रदेश में ही है। वर्षों से प्रदेश इस मामले में अव्वल बना हुआ है। वहीं, मातृ मृत्यु दर के मामले में भी इसका देश में पांचवां स्थान है। यह दुर्भाग्य है कि प्रदेश में कुपोषण का इतना भयावह स्तर होने के बाद भी यह मुद्दा चुनावों में गायब है।

● **नवीन रघुवंशी**

टीका के लिए टकटकी

आज दुनिया के अधिकांश देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी से मुक्ति के स्थाई उपचार के लिए टीका (वैक्सीन) बनाने का काम कई देशों में चल रहा है। इसी बीच भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बॉयोटेक हैदराबाद द्वारा निर्मित टीके को मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। इस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। कोरोना के मरीजों पर इसका क्लीनिकल ट्रायल यानी परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। दूसरी तरफ पतंजलि संस्थान द्वारा निर्मित कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को भी आयुष मंत्रालय ने सही बताया है। हालांकि आयुर्वेद व अन्य उपचार पद्धतियों में एलोपैथी की तरह दवा का परीक्षण नहीं किया जाता। बहरहाल यह उम्मीद बढ़ी है कि देर-सवेर कोरोना का टीका एवं प्रभावी दवा को विकसित कर लिया जाएगा।

चूंकि दवा पहली बार मरीजों के मर्ज पर आजमाई जाती है, इस कारण इसके विपरीत असर की आशंका भी बनी रहती है। दवा जानलेवा भी साबित हो सकती है, यह बात दवा कंपनी और चिकित्सक बखूबी जानते हैं। इसलिए पहले ये प्रयोग चूहा, खरगोश, बंदर आदि के बाद इंसान पर किए जाते हैं। परीक्षण के बहाने गुमनामी के ये प्रयोग कई बार चिकित्सकों की नाजायज कमाई का भी बड़ा हिस्सा बनते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ड्रग ट्रायल का कारोबार सालाना तीन हजार करोड़ रुपए का है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की करीब दो हजार दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल भारत में पंजीकृत हैं।

नई दवा के विकास के बाद उसके असर की जानकारी एवं रोग निदान के दृष्टिगत दवा की कितनी मात्रा जरूरी है, इस प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्लीनिकल ड्रग ट्रायल कहते हैं। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में **दवा को जानवरों पर आजमाकर** देखते हैं। इसके बुरे असर का आंकलन किया जाता है। इसी दौरान यह पता लगाया जाता है कि दवा की कितनी मात्रा मनुष्य झेल पाएगा। यह असर 40 से 45 रोगियों पर परखा जाता है। दूसरे चरण में 100 से 150 मरीजों पर दवा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे चरण में नई दवा का एक चीनी की गोली से तुलनात्मक प्रयोग करते हैं। इसे प्लेसिबो ट्रायल कहा जाता है। यदा-कदा बीमारी विशेष की दवा जो बाजार में पहले से ही मौजूद है, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन-परीक्षण किया जाता है। यह प्रयोग 500 से 1000 मरीजों पर अमल में लाया जाता है। इन तीनों चरणों की कामयाबी तय होने पर इस नमूने को भारतीय दवा नियंत्रक के पास लाइसेंस के लिए भेजा जाता है। लाइसेंस हासिल हो जाने पर दवा का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है। फिर क्षेत्र विशेष के लोगों पर बड़ी संख्या में दवा का प्रयोग शुरू होता है। यह प्रक्रिया दवा परीक्षण के चौथे चरण का हिस्सा है। क्षेत्र विशेष में दवा का परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय जलवायु पर रोगी के प्रभाव के साथ दवा के असर की भी पड़ताल हो सके।

दवा निर्माता कंपनियां रोगियों पर ड्रग ट्रायल का जाल बेहद कुटिल चतुराई से फैलाती हैं। इसके लिए सरकार की नीतियां और कार्य प्रणालियां भी दोषी हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें आम आदमी को बेहतर चिकित्सकीय परामर्श और मुफ्त इलाज कराने में नाकाम रही हैं। ड्रग ट्रायल करने वाले डॉक्टर रोगी को मुफ्त दवा का लालच देकर उसे दवा परीक्षण-अध्ययन परियोजना का हिस्सा बना लेते हैं। अंग्रेजी में छपे दस्तावेजों पर मरीज या उसके अभिभावक से अंगूठा अथवा दस्तखत करा लिए जाते हैं। दस्तावेज अंग्रेजी में होने के कारण मरीज यह नहीं समझ पाता कि वह दवा परीक्षण के लिए मुफ्त इलाज का हिस्सा बन रहा है अथवा वास्तविक मर्ज के उपचार का? सहमति पर हस्ताक्षर होते ही ताबड़तोड़ एक फाइल बनाई जाती है, जिस पर मरीज के नाम के स्थान पर एक गुप्तनाम लिखा जाता है। यहीं से मरीज परीक्षण का विषय बन जाता है और दवा निर्माता कंपनी की नई विकसित की गई दवा से उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह एक ऐसी दवा होती है, जिसकी उपलब्धता सिर्फ प्रयोग कर रहे डॉक्टर के पास होती है। दवा दुकानों पर नहीं मिलती। यहां डॉक्टर मरीज को यह हिदायत भी देता है कि वह **खाली पत्ता यानी स्ट्रीप लौटाता रहे**, ताकि उसे दवा की अगली खुराक उपलब्ध कराई जाती रहे।

हालांकि दुनिया की दवा निर्माता कंपनियों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन नए रोगाणुओं की नई दवा या टीका बनाने की प्रक्रिया बेहद खर्चीली, अनिश्चितता से भरी और लंबी अवधि तक चलने वाली होती है। इसलिए दवा कंपनियों की इन कार्यों में अधिक रूचि नहीं होती है। 20वीं सदी का मध्य और उसके बाद का काल इस नाते स्वर्ण युग था, जब चेचक, पोलियो, टिटनेस, रेबिज और हैपिटाइटिस जैसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए टीकों को विकसित किया गया।

● **प्रवीण कुमार**

80 खरब से ऊपर का बाजार

दुनियाभर में दवाओं का बाजार 80 खरब रुपए से भी ज्यादा का है, पर इसमें टीकों की भागीदारी केवल तीन प्रतिशत है। विषाणुओं को समाप्त करने के लिए टीका बनाने की प्रक्रिया महंगी व लंबी होने के कारण दवा कंपनियां इसे बनाने की प्रक्रिया में हाथ नहीं डालती हैं। विकसित देशों के समूह ही इन कार्यक्रमों में धन खर्च कर सकते हैं। शायद इसीलिए कोरोना का टीका बनाने के दावे तो कई देश कर रहे हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है, फिलहाल इसमें संदेह है। ड्रग ट्रायल की अपनी अहमियत है, बशर्ते वह नैतिक शुचिता और पेशागत पवित्रता से जुड़ा हो, क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें नई दवा की खोज उपचार की तत्कालिक जरूरत से जुड़ी होती है। इसलिए इसमें लगातार नए-नए शोधों का हिस्सा बनाकर स्वास्थ्य लाभ के लिए कारगर बनाए रखने के उपाय जारी रहते हैं।

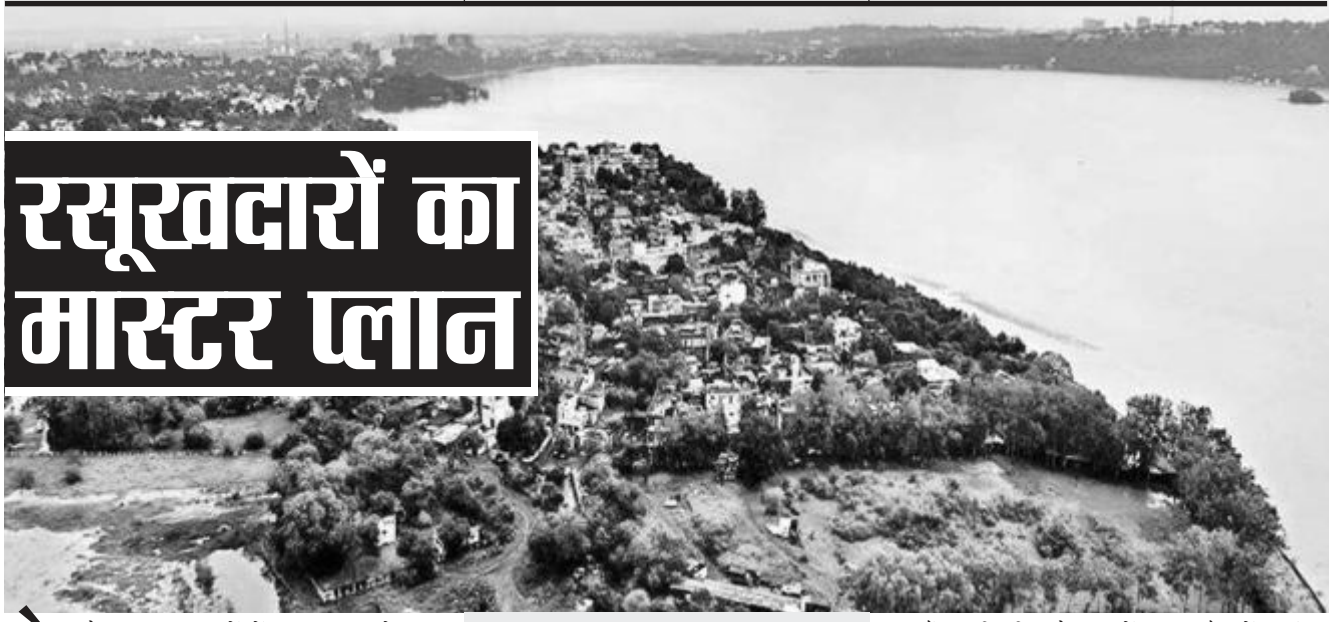

रसूखदारों का मास्टर प्लान

देश के खूबसूरत शहरों में शुमार मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को किसकी नजर लग गई है और वो मास्टर माइंड (रसूखदार) कौन लोग हैं, जो एशिया की बड़ी झील के साथ ही भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले प्राकृतिक स्रोतों, पहाड़ियों और कोई पांच हजार एकड़ सरकारी ग्रीन लैंड को बर्बाद करने पर आमादा हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (नगर तथा ग्राम निवेश) ने भोपाल का जो मास्टर प्लान 2031 तैयार किया है, बताते हैं वो शहर के कुछ बड़े रसूखदारों के इशारे पर तैयार किया गया है। जिसमें, बड़ी झील के हजारों एकड़ कैचमेंट एरिया और ग्रीन लैंड को आवासीय में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि मास्टर प्लान-2031 को लेकर सरकार ने पुन: दावे-आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दावे-आपत्तियां बुलाना सिर्फ दिखावा है, सच्चाई तो यह है कि राज्य सरकार ने इस नए मास्टर प्लान को लागू करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है।

दरअसल, पिछले पंद्रह सालों में मास्टर प्लान में 213 संशोधन किए जा चुके हैं और एक बार फिर व्यापक स्तर पर भोपाल के मास्टर प्लान में संशोधनों का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं पर्यावरण **विशेषज्ञों का कहना है** कि जिस तरह से भोपाल के नए मास्टर प्लान में तब्दीलियां की गई हैं, उसमें भोपाल की लाइफलाइन का गला घोंटा जाना लगभग तय हो गया है। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत मास्टर प्लान में सबसे ज्यादा बदलाव कृषि भूमि को आवासीय करने के लिए किए जा रहे हैं। टीएंडसीपी के आंकड़ों के अनुसार इसके पहले 2001 से 2016 तक लगभग 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि को आवासीय बना दिया गया। नतीजा राजधानी का 800 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र निर्जन हो गया। आगे नए मास्टर प्लान में बड़ी झील के हजारों एकड़ कैचमेंट एरिया और ग्रीन लैंड को आवासीय में तब्दील किए जाने से भोपाल का सौंदर्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और शहर की खूबसूरत वादियां कांक्रीट के जंगल में तब्दील हो जाएंगी।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बड़ी खामियां

लैंडयूज को पूरी तरह खत्म करने से रसूखदारों को कहीं भी, कैसा भी निर्माण करने का मौका मिल जाएगा। लैंडयूज संपत्ति की तरह बेचा जा सकेगा, जिससे कहीं भी, कैसे भी निर्माण किए जाएंगे। पुराने भोपाल में लोगों को लैंडयूज बेचकर कमाई का रास्ता खोला गया, जबकि नए शहर में रहने वाले लोगों को इसका खरीदार बनाया गया। ग्राम सेवनिया गौड़ की ओर से तालाब के अंदर ही 30 मीटर की रोड प्रस्तावित है। चंदनपुरा मेंडोरर-मेंडोरी जैसे शहर से लगे वन क्षेत्रों में निर्माण की राह खोलने वाले प्रावधान किए गए हैं।

मास्टर प्लान में कैचमेंट एरिया में लो-डेंसिटी का प्रावधान कर एक दर्जन हाउसिंग प्रोजेक्ट को बड़ा फायदा पहुंचाया गया। मास्टर प्लान में लो-डेंसिटी एरिया खत्म करने की सिफारिश की गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लो-डेंसिटी एरिया खत्म कर दिया जाता तो झील के कैचमेंट में आने वाले भौंरी बकानिया, मीरपुर व फंदा इलाकों में हाउसिंग, कमर्शियल और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर पलीता लगना तय था। लेकिन अब यहां रसूखदारों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी है। पब्लिक सेमी पब्लिक (पीएसपी) लैंडयूज को बदलने के लिए भी मास्टर प्लान में संशोधन कर दिए गए हैं। बड़ी झील के हजारों एकड़ कैचमेंट एरिया की कृषि भूमि को आवासीय में तब्दील किया जा चुका है। जहां कैचमेंट एरिया में साढ़े तीन हजार से ज्यादा निर्माण हो चुके हैं। दिलचस्प है कि इनमें एक हजार निर्माण वैध हो चुके हैं।

पीएसपी लैंडयूज के तहत स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण के साथ ही जनकल्याण केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसका फायदा उठाकर रसूखदारों ने केरवा, कलियासोत से लेकर आगे कोलार डैम तक की सतपुड़ा रेंज में भी निर्माण कर लिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों की आशंका है कि प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहा तो भविष्य में यहां हरियाली की जगह कांक्रीट के पहाड़ ही दिखेंगे। टीएंडसीपी के सूत्रों के अनुसार आने वाले मास्टर प्लान-2031 को प्रदेश के बड़े जमीन के सौदागरों यानी मास्टर माइंड **रसूखदारों के हिसाब और दिमाग** से तैयार किया गया है। ये वो रसूखदार हैं, जिनकी नजर बड़ी झील के कैचमेंट एरिया और हजारों एकड़ ग्रीन लैंड पर लगी हुई है। इन रसूखदारों में बड़े राजनेता, बिल्डर, भूमाफिया और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं।

बता दें कि आठ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन महापौर कृष्णा गौर की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति ने बड़े तालाब का मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नालॉजी यूनिवर्सिटी (सेप्ट) को सौंपी थी। सेप्ट को इसकी शुरुआती रिपोर्ट 25 जुलाई 2012 तक सौंपनी थी। लेकिन सेप्ट ने करीब एक साल देरी से रिपोर्ट 2013 में सौंपी थी। इसके बाद ड्राफ्ट पर 11 सरकारी महकमों से सुझाव भी मांगे गए थे, जो कि समिति को प्राप्त ही नहीं हुए। वहीं विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं।

● **कुमार विनोद**

बिना बिजली 3,329 करोड़ की चपत

लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे प्रदेश के साढ़े सात करोड़ लोगों पर एक और भार डालने की तैयारी चल रही है। मप्र पावर मैनेजमेंट व अन्य बिजली कंपनियों ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत दर का निर्धारण करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उस पर आयोग विचार कर रहा है। अगर उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो बिना बिजली खरीदे ही कंपनियों को 3329 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। इसका भार उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।

कंपनियों की इस प्रक्रिया पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने आपत्ति दर्ज कराई है। आंदोलन के संयोजक आलोक अग्रवाल ने बताया कि याचिका के अध्ययन से पता चलता है कि 8 बिजली कंपनियों से एक भी यूनिट बिजली खरीदे बिना 3,329 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही **महंगी बिजली** खरीदकर 3 कंपनियों को 2,055 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और न खरीदी गई बिजली के लिए भी 516 करोड़ रुपए पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन को फिक्स्ड चार्ज देना होगा। गैरवाजिब मांग को खारिज कर बचे 5,900 करोड़ रुपए से घरेलू उपभोक्ताओं को 3.80 रुपए यूनिट की कमी होना चाहिए।

प्रदेश में कुल 10,627 करोड़ यूनिट 2.5 रुपए यूनिट की बिजली उपलब्ध है। प्रदेश की कुल खपत 7,551 करोड़ यूनिट है। खपत के बाद भी 3,076 करोड़ यूनिट बिजली सरप्लस है। बिजली कंपनियों की 191 करोड़ यूनिट न खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंपनियों से बिजली खरीदी को मंजूरी नहीं देना चाहिए। बिजली कंपनियों की **गैरवाजिब मांगों** को न मानने से 5,900 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे घरेलू, व्यावसायिक एवं औद्योगिक बिजली की दरों में कमी की जा सकती है।

मप्र विद्युत नियामक आयोग में दायर याचिका में कहा गया है कि बिजली कंपनियों को राज्य सरकार बिना एक यूनिट खरीदे ही 2020-21 के दौरान बड़ी धनराशि का भुगतान करेगी। प्रदेश सरकार यदि राज्य की सरकारी बिजली कंपनियों को 2020-21 के दौरान दी जाने वाली समझौते की राशि (जिसके तहत एक भी यूनिट खरीदे बिना ही देनी पड़ती है) रद्द कर दे तो राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान बिजली दर के मुकाबले उसे 3.80 रुपए प्रति यूनिट कम देने पड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मप्र विद्युत नियामक आयोग में यह याचिका लॉकडाउन शुरू होने के पूर्व लगाई गई थी लेकिन पिछले तीन माह से इस पर सुनवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस याचिका पर इस माह के अंत में सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिका के अनुसार राज्य की आठ बिजली कंपनियों से एक भी यूनिट बिजली खरीदे बिना उन्हें 3,329 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन्हीं कंपनियों में से तीन कंपनियों से अत्यंत महंगी बिजली खरीदी जाएगी। इसकी राशि होगी 2,055 करोड़ रुपए और न खरीदी गई बिजली के भी 516 करोड़ रुपए पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन को फिक्स चार्ज देना होगा। याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दायर कर अपनी आपत्ति दर्ज कर मांग की है कि इस गैरवाजिब व बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ को अस्वीकार कर **राज्य के बिजली उपभोक्ताओं** को वर्तमान बिजली दर में कमी करने की स्थिति बनाई जाए। याचिका में अत्यंत महंगी बिजली खरीदी के संबंध में यह भी मांग की गई है कि एनटीपीसी मोदा दो, एनटीपीसी कवास और सिंगरौली कंपनियों से अत्यंत महंगी खरीदी जाएगी। इन तीन कंपनियों से कुल 191 करोड़ यूनिट बिजली का भुगतान 2,055 करोड़ रुपए होगा। ऐसे में जबकि वर्तमान में देश में उपलब्ध सरप्लस बिजली लगभग 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से आसानी से उपलब्ध है तो इतनी महंगी बिजली खरीदकर बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाला जाएगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

बिना एक यूनिट बिजली खरीदे कंपनियों की सूची

विद्युत कंपनी	राशि (करोड़ में)
एनटीपीसी मोदा यूनिट 1	189
एनटीपीसी मोदा गंधार	90
एनटीपीसी सोलापुर	314
एनटीपीसी गदरवाडा 1 व दो	1,180
एनटीपीसी खरगौन 1 व दो	974
टोरेंट पॉवर	62
जेपी बिना पॉवर	505
बीएलए पॉवर	15
कुल	3,329

5,900 करोड़ की होगी बचत

याचिका में बताया गया है कि राज्य के पास वर्तमान में 10,627 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है और प्रदेश की कुल खपत 7,551 करोड़ यूनिट है। इस प्रकार प्रदेश के पास संपूर्ण खपत के बाद भी 3,076 करोड़ यूनिट बिजली सरप्लस के रूप में बच रही है। अतः ऐसे में अत्यंत महंगी 191 करोड़ यूनिट बिजली नहीं खरीदने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याचिका में मांग की गई है कि आयोग इन कंपनियों से खरीदी जाने वाली बिजली की मंजूरी न दे। उपरोक्त बिजली नहीं खरीदने से राज्य सरकार के राजस्व में कुल 5,900 (3845+2055) करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के घरेलू उपभोक्ता 2020-21 के दौरान लगभग 15600.9 करोड़ यूनिट की खपत करेगा। यदि उपरोक्त राशि यानी 5,900 करोड़ रुपए कंपनियों को न दी जाए तो इस पैसे से उपभोक्ताओं की बिजली दर में 3.80 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी संभव है।

भ्रष्टाचार की एक और जड़ पर हमला

भारत के वित्तीय क्षेत्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि घोटाले ही सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है प्रतिभूति घोटाला। इस घोटाले के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का गठन हुआ। इसी तरह पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के बाद सहकारी बैंकों में सुधार की कवायद शुरू हुई। घोटाले के बाद गठित वित्त मंत्रालय की समिति ने सहकारी बैंकों पर से दोहरे नियंत्रण वाली मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर इन बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में रखने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया।

इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में बैंकिंग नियम (संशोधन) अध्यादेश लागू हो गया है। इसके जरिए अब सरकारी बैंकों की तरह देशभर के को-ऑपरेटिव बैंक भी रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाएंगे। इस अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित करके जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। अध्यादेश का यह दूरगामी उद्देश्य है कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया जाए ताकि वे व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली अपनाएं। इस संशोधन से राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों के मौजूदा अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी इसके दायरे में नहीं आएंगी।

अब तक सहकारी बैंकों को लाइसेंस तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ही देता है, लेकिन उनके प्रबंधन, चुनाव और दूसरी प्रशासनिक गतिविधियां राज्यों के रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास होती थीं। सहकारी बैंकों के नकद रिजर्व, तरलता जैसे वित्तीय मामलों को रिजर्व बैंक की को-ऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी टीम देखती थी। चूंकि सहकारी बैंक छोटे कर्ज बांटते हैं इसलिए यह टीम कम सक्रिय रहती है जिससे गड़बड़ियों का समय पर पता नहीं चल पाता था। नियामक के रूप में यही दोहरा नियंत्रण सहकारी बैंकों के लिए घातक साबित हुआ। चूंकि सहकारी बैंकों को स्थानीय राजनीति में सक्रिय लोगों के बीच से चुनकर आया एक संचालक मंडल प्रशासित करता है इसीलिए वहां भ्रष्टाचार के भरपूर मौके निकले। पिछले कुछ वर्षों से कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए। इसमें माधवपुरा मर्केंटाइल घोटाला, जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक घोटाला खूब चर्चित रहे।

हाल में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ जिससे उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी का माहौल बना। बाद में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से हालात सुधरे। देश के वित्तीय समावेश में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारी बैंकों का गठन लघु बचत और निवेश करने वालों की सुरक्षा देने के लिए किया गया था। देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं के 4.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है।

अध्यादेश लागू होने के बाद जनता में यह संदेश जाएगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। रिजर्व बैंक यह तय करेगा कि सहकारी बैंकों का पैसा किस क्षेत्र के लिए **आवंटित** किया जाए। इससे पहले मोदी सरकार ने सहकारी समितियों को सरकारी चंगुल से आजाद करने के लिए संविधान में 111वां संशोधन किया था। इससे सहकारी समितियां बनाना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी संस्थाओं में नियमित चुनाव और आरक्षण का प्रावधान होने से देशभर में कार्यरत तकरीबन 6 लाख सहकारी समितियों को राजनीति और नौकरशाही के दखल से मुक्त करने की कारगर पहल की गई थी।

आज भले ही सहकारी बैंक घोटालों का पर्याय बन गए हों, लेकिन देश के वित्तीय समावेश और कृषि क्रांति लाने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। देश के तकरीबन सभी गांवों तक सहकारी समितियां किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी हैं। डेयरी, चीनी, उर्वरक, हैंडलूम, गृह निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की मजबूत पकड़ है। सहकारी बैंकों की दुर्दशा की असली वजह यह है कि नेताओं ने इन्हें अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में सहकारी बैंक नेताओं के लिए उर्वर राजनीतिक जमीन मुहैया कराते रहे हैं। इसीलिए इन बैंकों के निदेशक मंडल में जगह बनाने के लिए मारामारी मची रहती है।

● **राजेश बोरकर**

सहकारी संस्थानों पर कब्जे की राजनीति

कमोबेश यही हालात अन्य कई राज्यों में हैं। चूंकि सहकारी बैंक राजनीति से जुड़ गए इसलिए देश की राजनीति में जैसे-जैसे मूल्यों का पतन हुआ उसका प्रभाव सहकारिता पर भी पड़ा। सहकारी संस्थानों पर कब्जे को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ और हिंसक संघर्ष शुरू हो गए। इससे सहकारिता में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसका असर आम जनता पर भी पड़ा। लोग अब सहकारी समितियों और बैंकों के कर्ज को दान मानने लगे। इससे इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति गिरी और वे पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर हो गईं। राज्य सरकारों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। वे सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के बजाय अपने लोगों और पसंदीदा नौकरशाहों को प्रशासक बनाकर उन्हें अपने कब्जे में करने लगीं। मोदी सरकार हर स्तर पर तकनीक रूपी चौकीदार बैठाने के बाद अब संस्थानों की ढांचागत कमजोरियों को दूर करने में जुटी है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार की हर जड़ पर हमला हो रहा है। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में लाकर सरकार ने इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की एक कारगर पहल की है। इससे भले ही नेताओं की राजनीति पर बट्टा लगे, लेकिन सहकारी बैंकों पर करोड़ों ग्राहकों के भरोसे में बढ़ोतरी होना तय है।

हरियाली हो रही गायब

50 प्रजातियों के पौधे लगाते हैं जंगल में

प्रदेशभर के जंगलों में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। ये वनक्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इंदौर वनमंडल में सागवान, अंजन, शीशम, नीम, जामुन, जाम, आम, बरगद (20 प्रजाति), गूलर, बांस, इमली, बबूल समेत कई पेड़ शामिल हैं। नवरत्नबाग, अहिल्या आश्रम, रेसीडेंसी, बड़ग़ोंदा और अनुसंधान केंद्र की नर्सरी में पौधे तैयार होते हैं। जंगल में पौधों की कई प्रजातियां अब खतरे में आ चुकी हैं। इनमें मेदा, कर्कट, शल्यकर्णी, दहिमन, सोनपाठा, गरुड़, सलाई, धावड़ा, मोखा, कुंभी, गवड़ी, केंकड़, बीजा, पाडर, रोहना प्रजातियां शामिल हैं। इन्हें बचाने के प्रयास में वन विभाग जुटा है।

मप्र में बीते कई वर्षों से प्रत्येक सीजन (मानसून) में 8 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपने का दावा किया जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार 10 वर्ष में 80 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए हैं। तल्ख सच्चाई यह है कि इनमें से 10 फीसदी पौधे भी जमीन पर नजर नहीं आते। जानकार कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह पौधरोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति है। अभियान चलाकर आनन-फानन में पौधे लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन रोपने से पहले न जमीन देखी जाती है, न उनकी सही देखभाल की जाती है।

राजधानी भोपाल में पांच साल में 15 लाख पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे भोपाल लोकल व आसपास के जंगल में रोपे गए हैं। इनमें से 70 फीसदी पौधे यानी 10 लाख 50 हजार पौधों के जिंदा होने के दावे किए जा रहे हैं। यह दावा भोपाल जिले का वन विभाग कर रहा है, लेकिन इतने पौधे जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं तो वहीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि भोपाल का जंगल 25 वर्ग किलोमीटर घट गया है। हालांकि पूर्व के सालों की तुलना में हरियाली ज्यादा नजर आ रही है।

दरअसल, भोपाल सामान्य वन मंडल का जंगल 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह बात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है। इसके पहले साल 2017 की रिपोर्ट में भोपाल के जंगल का दायरा 379 वर्ग किलोमीटर था। कुल मिलाकर पौधे लगाने के आंकड़े जो भी कह रहे हों, लेकिन वन विभाग की ही अधिकृत रिपोर्ट बताती है कि **जंगल बढ़ने की बजाय कम हुआ है।** यही वजह है कि गर्मी में धूप हर साल अधिक चुभ रही है तो ठंड के दिनों में प्रदूषण हावी हो जाता है। जनवरी से फरवरी 2020 के बीच ही वायु की गुणवत्ता बताने वाला सूचकांक 300 से ऊपर चला गया था जो कि 50 तक या उससे नीचे होना चाहिए।

भोपाल सामान्य वन मंडल के अधिकारियों का कहना है कि हर साल जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें से 70 फीसदी पौधे जिंदा रहते हैं, बाकी के सूख जाते हैं या अन्य कारणों से मर जाते हैं। भोपाल सामान्य वन मंडल के डीएफओ एचएस मिश्रा का कहना है कि 70 फीसदी पौधे जिंदा रहते हैं, यही वजह है कि भोपाल के जंगल में हरियाली का ग्राफ पूर्व की तुलना में बढ़ा है।

शासन के निर्देश पर जबलपुर जिले का वनक्षेत्र बढ़ाने की मंशा से वन विभाग ने बीते दो साल के दौरान करीब 14 लाख पौधे लगाए। वर्तमान में इनमें से 4 लाख से ज्यादा पौधे दम तोड़ चुके हैं। बावजूद इसके वन विभाग इस वर्ष सवा 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखकर पौधारोपण कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में 80 हजार विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने का काम पूरा हो चुका है। वन विभाग कार्यालय से बताया गया है कि सरकार के निर्देश व नीति के अनुसार वन विभाग ने जिले की जमीन का चयन करके पौधारोपण किया है। इसमें खास यह कि जिले की मिट्टी, जलवायु की जांच के बाद वन विभाग कार्ययोजना ने पौधारोपण के लिए पौधों की विभिन्न प्रजातियों का चयन किया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वन विभाग ने पौधों की प्रजाति के आधार पर 4-4, 7-7 फीट की दूरी रखकर पौधे लगाए।

वर्ष-2018 में जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र जबलपुर, शहपुरा, बरगी, कुंडम, सिहोरा, पाटन, पनागर के कुल एक हजार 143 हैक्टेयर जमीन पर कुल 9 लाख 58 हजार 459 पौधों का रोपण किया गया। वहीं वर्ष-2019 में जबलपुर वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्र की 527 हैक्टेयर जमीन पर 4 लाख 32 हजार 225 पौधे लगाए गए। वन विभाग ने इस वर्ष 322 हैक्टेयर में करीब सवा 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग ने वर्ष-2018 और 2019 में अभियान चलाकर 14 लाख पौधों का रोपण किया। इसमें से 10 फीसदी पौधों ने एक सप्ताह में दम तोड़ दिया। वन विभाग ने यह पौधे बदलकर दूसरे पौधे लगाए। वनकर्मी पहाड़ी, बंजर जमीन पर लगाए गए पौधों का उचित रखरखाव करने में नाकाम रहे।

बीते तीन वर्ष में अकेले इंदौर वनमंडल में करीब 35 लाख से ज्यादा पौधे जंगल में लगाए हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधे जंगलों में वन विभाग और पर्यावरण से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं की मदद से लगाते हैं। कई बार पानी कम होने या अत्यधिक छोटे पौधे होने से ये मुरझा जाते हैं या फिर पनप नहीं पाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 10 लाख पौधे नष्ट हुए हैं। 2019 में बजट की कमी से पौधे कम लगाए गए जबकि इस साल कोरोना संक्रमण के चलते विभाग ने नष्ट पौधों को बदलने की योजना बनाई है। लगभग ढाई लाख पौधे अलग-अलग वनक्षेत्र में लगाए जाएंगे। लाखों पौधे विभाग की लापरवाही के चलते नष्ट हो गए। जानकारों के अनुसार पौधारोपण के लिए महज एक दिन रखा था। इसके लिए स्टाफ को लक्ष्य दे रखा था। इससे न तो गड्ढे ठीक से खुदवाए गए और न मिट्टी और खाद पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिली। साथ ही पौधे भी इतने छोटे थे कि तेज बारिश में बह गए।

● **राकेश ग्रोवर**

पैकेज की बंदरबांट

बुंदेलखंड पैकेज के तहत छतरपुर जिले में 918.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जल संसाधन, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि विभाग, पशुपालन, ग्रामीण विकास विभाग के जरिए योजना पर ये राशि खर्च की गई। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इन विभागों द्वारा कराए गए कार्य की न केवल गुणवत्ता खराब है, बल्कि बहुत सारी योजनाओं से लोगों को लाभ ही नहीं मिल सका है। बुंदेलखंड पैकेज के तहत मिली राशि को खपाने और बंदरबाट करने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने न केवल घटिया निर्माण कराया, बल्कि फर्जी बिल लगाकर भी राशि निकाल ली। सबसे ज्यादा गड़बड़ी वन विभाग के कार्यों में पाई गई, जहां स्कूटर व जीप के आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ट्रक से कार्य कराने की राशि निकाल ली गई। हाईकोर्ट में दायर याचिका के तारतम्य में हाईकोर्ट ने मुख्य तकनीकी परीक्षक मध्यप्रदेश से जांच कराई तो छतरपुर जिले में जमकर धांधली किए जाने की बात सामने आई।

वन विभाग ने 180.37 करोड़ रुपए की राशि से पैकेज के तहत 6 जिलों में कार्य किए गए। छतरपुर जिले में बड़ामलहरा एवं बक्स्वाहा विकासखण्ड में बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत कराए गए कार्यों में नवीन तालाब निर्माण में किए गए पिचिंग कार्य में निधारित गुणवत्ता का पत्थर नहीं लगाया गया, सामग्री क्रय की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही। कक्ष पी-82 में भुगतान किए गए वाउचर्स क्रमांक एम-179 20 फरवरी 2012 में मजदूरों के हस्ताक्षर तो हैं, लेकिन बिना राशि इन्द्राज किए श्रमिकों के हस्ताक्षर कराए गए, जिसकी लागत 4,79,981 रुपए हैं। इसी कक्ष में जेसीबी द्वारा कराए गए कार्यों का भुगतान बिना जेसीबी नंबर दर्शाए किया गया है। वहीं, कक्ष पी-202 में निर्मित नवीन तालाब निर्माण में परिवहन के लिए ट्रक नंबर एमपी-15 जी-1732 का उपयोग कर भुगतान किया गया। आरटीओ की वेबसाइट से इस वाहन का प्रकार जीप के नाम पर दर्ज होना पाया गया, जिस पर कुल व्यय 31,149 खर्च किया गया। कक्ष पी-50 में नवीन तालाब के निर्माण कार्य में ट्रक एमपी 08 ई-2799 का उपयोग किया जाना दर्शाया गया हैं। जबकि आरटीओ की वेबसाइट पर उक्त वाहन नंबर स्कूटर का है।

छतरपुर जिले में दिदौनिया जलाशय से 375.90 लाख रुपए की लागत से नहरों का निमार्ण किया गया। जांच में पाया गया कि पुलियों में पाइप के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में सिल्ट जमा होने से नहर में डिजाइन डिस्चार्ज के अनुसार पानी प्रवाहित करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। वहीं, 3136.10 लाख रुपए से रनगुंवा बांध की नहरों का लाइनिंग कार्य में नहर के सर्विस रोड के टॉप लेवल को मेंटेन कर लिए जाने के बाद सर्विस रोड पर डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण के दौरान पुन: मिट्टी डालना दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। इसी तरह से बरियापुर बायी तट में 545.90 करोड़ रुपए से मुख्य नहर का 49 किलोमीटर तक सीसी लाइनिंग निर्माण कार्य की जांच चलित प्रयोग शाला द्वारा की जाने पर सीसी लाइनिंग की स्ट्रेंग्थ निर्धारित मापदंड से कम पाई गई और लाइनिंग कार्य में दरारें भी पाई गई। इसी तरह सिंहपुर बैराज योजना में 260.63 करोड़ रुपए से मध्यम योजना की जांच में पाया कि शासन की बिना अनुमति के 1.15 करोड़ का भुगतान किया गया। वहीं, 802.03 लाख रुपए की खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना तहसील बक्स्वाहा की जांच में वास्तविक सिंचाई न होने की शिकायत सही पाई गई।

299.51 करोड़ रुपए की राशि से 6 जिलों में कराए गए कार्यों की जांच में पाया गया कि छतरपुर जिले में रेण्डम आधार पर प्रत्येक विकासखण्ड की दो योजनाओं का परीक्षण किया गया। छतरपुर जिले में 10 ग्रामों में नलजल योजना के तहत पाइपलाइन निर्धारित गुणवत्ता की नहीं डाली गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर मुख्य तकनीकी परीक्षक मध्यप्रदेश की जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि **अफसरों ने बुंदेलखंड पैकेज** के तहत योजनाएं तैयार करने में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया। यही कारण है कि 1287 में से 997 नलजल योजनाएं पूर्णत: व्यर्थ रहीं। जिसमें से छतरपुर जिले में 150 योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जांच में पाया गया कि अफसरों ने न तो सामान की गुणवत्ता परखी, न भौतिक सत्यापन किया, न साइट विजिट की, न ही पाइपलाइन बिजली पंपों की गुणवत्ता परखी।

कृषि विभाग को बुंदेलखंड पैकेज से 614.36 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसमें वेयर हाउस, मंडी निर्माण, उद्यानिकी, डीजल पंप वितरण, आदि कार्य कराए जाने थे। उक्त संबंध में मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा आंशिक जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि नौगांव में कार्यालय भवन, मैनेजर आवास गृह, चौकीदार भवन, वाटर पोर्श और बड़ामलहरा में केंटीन, कृषक सूचना केंद्र, पम्प हाउस का हस्तांतरण नहीं किए जाने से संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पशुपालन व उद्यानिकी में भी मिली गड़बड़ी

पैकेज के तहत 151.27 करोड़ रुपए की राशि से 6 जिलों में बकरी पालन, मुर्रा सांड और डेयरियों के विकास के लिए कार्य किया गया। डबल संख्या बकरी इकाई में कमजोर बकरियां प्रदाय के कारण भारी संख्या में बकरियों की मृत्यु होना पाया गया। छतरपुर जिले में 15.44 प्रतिशत मृत्यु दर पाई गई। इसके साथ ही मुर्रा वितरण में छतरपुर जिले में 15.88 प्रतिशत मृत्यु दर पाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित प्रतिशत से अधिक मृत्यु होना इस बात का प्रमाण है कि ठेकेदारों द्वारा हितग्रहियों को स्वस्थ मुर्रा एवं बकरियां प्रदान नहीं की गई। योजना के अनुसार राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा किया जाना था, लेकिन छतरपुर जिले में अनुदान राशि 83,71,665 रुपए उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं छतरपुर द्वारा हितग्राहियों के खाते में जमा न करते हुए पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के निजी खातों में जमा की गई, जो कि एक गंभीर आर्थिक अनियमितता है।

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2018-20

मध्यप्रदेश में बिछी चुनावी बिसात

किसी भी सरकार का आईना होता है उसका मंत्रिमंडल। शिवराज मंत्रिमंडल का स्वरूप देखकर हर कोई कह सकता है कि यह चुनावी बिसात है। कांग्रेस इस मंत्रिमंडल को विडंबना, अवसरवाद और अंदरूनी खींचतान का पुतला मान रही है। वहीं भाजपा इसे संतुलित जमावट बता रही है। असल में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का बंटवारा कुछ नए समीकरण और संदेश लेकर आया है। अब देखना यह है कि यह नया समीकरण क्या गुल खिलाता है।

● राजेंद्र आगाल

मंथन पर मंथन और फिर महामंथन के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह दो विचारधाराओं के संगम का अनूठा उदाहरण है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी कैबिनेट का गठन हुआ है जिसके लगभग 42 फीसदी मंत्री पूर्व में कांग्रेसी विचारधारा के थे, और 58 फीसदी भाजपा के। प्रारंभिक तौर पर तो दोनों दूध और पानी की तरह मिल गए हैं। इस मिलन के कारण स्वाद थोड़ा फीका हुआ है, लेकिन रंग जैसा का तैसा है। इसकी वजह यह है कि इनका मकसद उपचुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह धूल चटाना है। यानी कैबिनेट की इस जमावट (मंत्रिमंडल गठन और विभागों का बंटवारा) चुनावी है। इनका एक ही मकसद है कि 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 100 फीसदी जीत हासिल की जाए। इसलिए 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो वर्तमान में

विधायक नहीं हैं।

मंत्रिमंडल की पूरी गणित देखें तो कांग्रेस से आए 22 में से 14 यानी आधे से भी अधिक बाजी मार ले गए। वहीं भाजपा के 107 विधायकों में से केवल 19 ही मंत्री बन पाए। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस से आए 60 प्रतिशत विधायक मंत्री बने। वहीं भाजपा के 18 प्रतिशत विधायक ही मंत्री बने हैं। ऐसे में यह कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि मध्यप्रदेश भाजपा में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा रुतबा जम चुका है। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता पर नजर डालें तो 33 में से 7 मंत्री पांचवीं और बारहवीं पास हैं, जबकि 25 मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा हैं। दो मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता सिर्फ साक्षर घोषित की है। मंत्रिमंडल में शामिल इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाह और महेंद्र सिंह सिसोदिया 12वीं पास हैं। बृजेंद्र सिंह यादव पांचवीं और ऐंदल सिंह कंसाना आठवीं पास हैं। अटेर के अरविंद सिंह भदौरिया और उज्जैन के मोहन यादव पीएचडी हैं। वहीं, 9 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उम्र के मामले में भी जो रिपोर्ट आई है, उसमें 12 मंत्रियों की आयु 41 से 50 साल के बीच घोषित है। जबकि 22 मंत्रियों की उम्र 51 से लेकर 70 साल तक है। शिवराज मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिशत 12 फीसदी है, यानी मंत्रिमंडल में कुल 4 महिला मंत्री हैं।

असंतुलित या मजबूरी का मंत्रिमंडल

राजनीतिक जानकार इसे पूरी तरह असंतुलित फॉर्मूला बता रहे हैं। वो भी तब, जब मध्यप्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा में घमासान होना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल से वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार किया गया है। शिवराज सिंह द्वारा सुझाए गए नामों को केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिए गए सभी नामों पर मुहर लगा दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या गजब बात कही। मंथन से अमृत निकलता है, विष तो शिव पीते हैं। मध्यप्रदेश के सियासी खेल को जमाकर उसी में उलझी भाजपा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। यहां दो सवाल खड़े हैं। अगर मंथन से अमृत के रूप में मंत्रिमंडल निकला है तो विष कौन है। या ये समझा जाए कि कहीं मंत्रिमंडल ही तो विष नहीं। जिस तरह मंथन में शिवराज सिंह चौहान पर ज्योतिरादित्य भारी पड़े हैं, उसे देखते हुए तो कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में सिंधिया का दबदबा शिवराज से ज्यादा हो गया है।

अगर ऐसा नहीं होता तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां नहीं किया होता। शिवराज ने ट्वीट में कहा था, 'आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। पल-पल राहजनी की इस कदर आपने, कि आपकी यादें रह गईं दिलों में जख्म बनकर।' क्या शेर के रूप में व्यक्त किया गया यह दर्द ही शिवराज सिंह के लिए जख्म है। राजनीतिक हलकों से जुड़े लोग इसे सिंधिया से जोड़कर देख रहे हैं।

मंथन से क्या-क्या निकला

28 मंत्रियों के कैबिनेट विस्तार के लिए हुए मंथन में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान की अधिकतर पसंद को दरकिनार कर दिया। वहीं सिंधिया द्वारा दिए गए सभी नामों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। मंत्रिमंडल में सिंधिया के 12 विश्वासपात्र शामिल हो गए। शिवराज सरकार के पुराने मंत्रिमंडल में भी सिंधिया खेमे के दो लोगों को पहले ही मंत्री बनाया हुआ है। ऐसे में अगर सारे कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं की संख्या देखें तो शिवराज मंत्रिमंडल में

सिंधिया समर्थकों को मिले पसंदीदा विभाग

शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के बंटवारे में एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है। उनके समर्थक कई मंत्रियों को पुराने विभाग मिले हैं तो कई मंत्रियों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, भाजपा के सीनियर नेताओं को भी कई बड़े पद मिले हैं। बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक नेताओं को उनके पसंद के विभाग दिए गए हैं। शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे की मंत्री इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ सरकार में भी इमरती देवी के पास यही विभाग था। वहीं, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग दिया गया है। कमलनाथ सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत के पास यही विभाग था। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के डॉ. प्रभुराम चौधरी को शिवराज सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। कमलनाथ सरकार में डॉ. प्रभुराम चौधरी स्कूली शिक्षा मंत्री थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कमलनाथ सरकार में भी सिंधिया खेमे के पास था। कमलनाथ सरकार में तुलसी सिलावट प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। शिवराज सरकार में तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ सरकार में तोमर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। महेन्द्र सिंह सिसौदिया को ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का मंत्री बनाया गया है। सिसौदिया कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री थे। सिंधिया खेमे के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं, बृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज दंडोतिया, सुरेंद्र धाकड़ और ओपीएस भदौरिया पहली बार मंत्री बने हैं। इन्हें अलग-अलग विभागों का राज्यमंत्री बनाया गया है।

मंत्री और उनके विभाग

- शिवराज सिंह चौहान-सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन
- नरोत्तम मिश्रा-गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि
- गोपाल भार्गव-लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग
- तुलसी सिलावट-जल संसाधन, मत्स्य विभाग
- विजय शाह-वन
- जगदीश देवड़ा-वाणिज्य कर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
- बिसाहूलाल सिंह-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
- यशोधरा राजे सिंधिया-खेल एवं युवक कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार
- भूपेन्द्र सिंह-नगरीय विकास एवं आवास
- कुमारी मीना सिंह- अजा-जजा कल्याण
- कमल पटेल-किसान कल्याण एवं कृषि विकास
- ऐंदल सिंह कंसाना-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- गोविन्द सिंह राजपूत-राजस्व, परिवहन
- बृजेन्द्र सिंह राजपूत-खनिज साधन, श्रम
- विश्वास सारंग-चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
- इमरती देवी-महिला एवं बाल विकास
- डॉ. प्रभुराम चौधरी-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- महेन्द्र सिंह सिसोदिया-पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- प्रद्युम्न सिंह तोमर-ऊर्जा
- प्रेमसिंह पटेल-पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
- ओमप्रकाश सकलेचा-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
- ऊषा ठाकुर-पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म
- अरविंद भदौरिया-सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन
- डॉ. मोहन यादव-उच्च शिक्षा
- हरदीप सिंह डंग-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण
- राजवर्धन सिंह-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

राज्य मंत्री

- भारत सिंह कुशवाह-उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार),नर्मदा घाटी विकास
- इंदरसिंह परमार-स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन
- रामखेलावन पटेल-पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- रामकिशोर कांवरे-आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन
- बृजेन्द्र सिंह यादव-लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी
- गिरिराज दंडोतिया-किसान कल्याण एवं कृषि विकास

14 ऐसे मंत्री होंगे जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं जबकि भाजपा से 16 मंत्री बनाए गए। वहीं पुराने मंत्रिमंडल में भाजपा से 3 मंत्री बनाए गए थे। इस तरह शिवराज मंत्रिमंडल में भाजपा के कुल 19 विधायक मंत्री हैं।

एक बार फिर मानना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान को। विभागों के बंटवारे में गजब का संतुलन दिखाया। हर किसी को खुश रखने का बंदोबस्त। कोई भी नाराजगी वाला स्वर नहीं। भाजपाइयों को अचानक विभागों के लिए मलाईदार शब्द से शिकायत होने लगी है। इसलिए चाहे तो उसकी जगह 'मालदार' का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो मालदार भी छोड़ दें, लेकिन कम से कम दिलदार का प्रयोग तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान ने जमकर दिलदारी दिखाई। आज की सियासी **पंगत में बैठे अपने हर वजीर** के लिए यह फिक्र रखीं कि उसकी प्लेट में कम से कम एक स्वीट डिश जरूर चली जाए। यानी हर मंत्री को कम से कम एक दमदार या कह सकते हैं काम करने वाला महकमा भी जरूर दिया गया है।

युवा तुर्क विश्वास सारंग को यदि सहकारिता की सेवा करने का फिर मौका नहीं मिला तो उन्हें चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया। कोरोना काल में सारंग के लिए इस विभाग के जरिए काम कर अपनी छवि चमकाने का पूरा अवसर रहेगा। नरोत्तम मिश्रा से यदि स्वास्थ्य विभाग लिया गया तो उसके बदले उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुरूप ही गृह के साथ जेल और संसदीय कार्य और विधि विभाग फिर सौंप कर उनका दर्जा नंबर दो का रखा गया है। जगदीश देवड़ा के ग्रह भी बदले हैं और वित्त के साथ वाणिज्यिकर और योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी जैसा एक तगड़ा विभाग उनकी झोली में गिरा है।

राजपूत का बढ़ा कद

गोविन्द राजपूत को आज महाराजा के अनुसरण वाले अपने निर्णय पर यकीनन और गर्व हुआ होगा, जब **परिवहन जैसा कुबेरनुमा महकमा** उनके पास आ गया। यह विभाग किसी भी सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम महत्व वाला नहीं होता है। हां, इसे दुहने के अपने-अपने तरीके होते हैं। इस काम में भाजपा और कांग्रेस की पद्धति के बीच जमीन-आसमान का अंतर है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से आए राजपूत किस तरह भाजपाई मंत्री की हैसियत से विभाग का अपने और सरकार के पक्ष में संचालन कर सकेंगे। भाजपा के एक डॉक्टर की सियासी तबीयत खराब कर देने वाले प्रभुराम चौधरी अब स्वास्थ्य विभाग भी देखेंगे। सांची में शेजवार परिवार का **सियासी बंटाधार कर देने वाले** प्रभुराम को परिवार कल्याण का भी काम मिला है। इन तरीकों से चौधरी का वजन बढ़ाया तो गया, लेकिन उसमें से कुछ तोला निकालकर रामकिशोर कांवरे को राज्यमंत्री के हैसियत से आयुष का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है।

तुलसी सिलावट मछुआरे और मछलियों की चिंता तो चलते-फिरते कर ही लेंगे, लेकिन जल संसाधन जैसा विभाग उनके पास बरकरार रखकर उन्हें भी पर्याप्त काम और मौका उपलब्ध करा दिया गया है। कुटीर और ग्रामोद्योग जैसी शाकाहारी सब्जी के साथ ही गोपाल भार्गव को लोक निर्माण विभाग वाला बड़ा विभाग थमाकर शिवराज ने उनका महत्व बरकरार रखा है। इमरती देवी तो यूं ही महज मंत्री बनाए जाने की संभावनाओं से ही चहक उठी थीं, तिस पर उन्हें पिछली सरकार की ही तरह अपनी क्षमताओं के अनुरूप महिला और बाल विकास का काम मिल गया है। राज्य में भाजपा की सियासी संभावनाओं को उजाला बनाए रखने में अरविंद भदौरिया की अहम भूमिका रही है। अब वे सहकारिता जैसे दमदार महकमे को भी संभालेंगे।

वीवीआईपी विभाग सीएम के पास

तो शिवराज ने जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन जैसे वीवीआईपी विभाग अपने पास ही रखे हैं।

यह सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का उनका महत्वपूर्ण जतन माना जा सकता है। शिवराज के सामने अपार चुनौतियां हैं। 25 सीटों के उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। फिर अगले विधानसभा चुनाव की तेजी से नजदीक आती घड़ी भी उनसे बहुत अधिक और बहुत ही उत्कृष्ट काम की अपेक्षा बढ़ा देती है। इसलिए सरकार के मुखिया के तौर पर खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी ही दम पर तैयार करने का प्रयास किया है। यह वह विभाग वितरण है, जिससे किसी के भी नाखुश होने की कोई संभावना नहीं रह गई है। ऐसा संतुलन कायम करना आसान नहीं था। शायद यही वजह रही कि महकमों के आवंटन की यह प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई। अब अंत भला तो सब भला जैसी स्थिति दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश और शिवराज भी संतुष्ट। एक साथ दो ध्रुवों को लाकर उनके बीच ऐसा सामंजस्य कायम करना कठिन प्रक्रिया थी। इसकी सफलता के लिए निश्चित ही शिवराज बधाई के पात्र हैं।

सिंधिया की ताकत बढ़ी

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो कमाल किया है, जो उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पूरी ताकत लगाकर भी कभी नहीं कर पाए। सफल केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे माधवराव की हसरत मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की थी या फिर सुपर सीएम। यह हो न सका जयविलास पैलेस इस बात पर गर्व कर सकता है कि माधव महाराज के पुत्र ज्योतिरादित्य ने वह रसूख अर्जित कर लिया, जिसकी तमन्ना उनके पिता को थी और जो सुख उनकी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया आज से 53 साल पहले भोग चुकी हैं। कमलनाथ सरकार का तख्तापलट कर महाराज मुख्यमंत्री न बन सके तो कोई गम नहीं वे किंगमेकर बन गए हैं और अपनी इस नई पारी में वे उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसा खेल पांच दशक पहले उनकी दादी ने खेला था। महाराज की महिमा से फिर सत्ता में आई भाजपा और मुख्यमंत्री पर महाराज की मर्जी का चाबुक कुछ इस तरह चल रहा है कि 15 साल तक लगातार मंत्री रहे गोपाल भार्गव अथवा अपने खास सखा भूपेंद्र सिंह को उनके अनुभव और योग्यता के मुताबित विभाग देना मुश्किल हो रहा है। महाराज की महिमा ही है कि भाजपा को दूसरी, तीसरी और चौथी बार के अनुभवी विधायकों की जगह फर्स्ट टाइमर को भी मंत्री बनाना पड़ा है। महाराज के पराक्रम के संकेत हाल ही में **अपनी वर्चुअल रैली में** भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह कह कर दे दिए थे कि सिंधिया की हर बात को पूरा किया जाएगा। वचनपत्र वाली पार्टी से संकल्प वाली भाजपा में आए ज्योतिरादित्य के वचन और पसंद का मान रखना अब भाजपा और शिवराज के लिए कमलनाथ सरकार के वचन से भी वजनदार काम हो गया है।

राजमाता की दिलाई याद

यानी मुख्यमंत्री भले ही उनकी पसंद का हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपनी पसंद से कुछ काम न कर सके। संविद सरकार में राजमाता द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए गोविंद नारायण सिंह ने भी महल के इतने दबाव झेले कि एक दिन उन्होंने संविद सरकार से ही किनारा कर लिया था। 1969 वाला वापसी का वह रास्ता भाजपा या शिवराज के पास फिलहाल नहीं है।

सिंधिया ने समन्वय बनाए रखा

ज्योतिरादित्य के जुझारू तेवर रंग लाए लेकिन समन्वय उन्होंने टूटने नहीं दिया। लंबी

14 मंत्री लड़ेंगे उपचुनाव!

मध्यप्रदेश में जिन 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 14 सीटों पर प्रदेश की मौजूदा सरकार के मंत्री चुनावी मैदान में होंगे। जाहिर है मंत्री के चुनावी मैदान में होने से भाजपा फ्रंटफुट पर रहेगी और चुनाव में उसे इसका फायदा भी हो सकता है। मंत्रियों के उपचुनाव में चुनाव लड़ने की बात इसलिए भी साफ है क्योंकि ये सभी 14 मंत्री पूर्व विधायक हैं। ऐसे में उन्हें एक बार फिर विधायक बनना होगा और तभी वो मंत्री बने रहेंगे। जिन 14 मंत्रियों को उपचुनाव लड़ना है उनमें सुमावली विधानसभा सीट से ऐंदल सिंह कंसाना पूर्व विधायक हैं। वहीं ग्वालियर सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर पूर्व विधायक हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवराज कैबिनेट में भी मंत्री बनाया गया है। शिवराज सरकार में मंत्री बनीं इमरती देवी डबरा से पूर्व विधायक हैं। सिंधिया समर्थक इमरती देवी कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थीं और सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद वो भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं। गुना जिले की बामोरी सीट से उपचुनाव में शिवराज सरकार के मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया मैदान में उतर सकते हैं। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के सत्ता से जाने और शिवराज सरकार के आने पर सरकार में मंत्री बनाए गए गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सीट सुरखी पर भी उपचुनाव होना है। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रभुराम चौधरी को भी शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है। इससे पहले कमलनाथ सरकार में भी प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री थे। सिंधिया के करीबी तुलसीराम सिलावट सांवेर से पूर्व विधायक हैं। तुलसी सिलावट शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गिर्राज दंडौतिया शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं। भिंड जिले की मेहगांव सीट पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। शिवराज कैबिनेट में मंत्री बने सुरेश धाकड़ पोहरी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं। अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से पूर्व विधायक बृजेन्द्र सिंह यादव शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाए गए पूर्व विधायक बिसाहूलाल साहू अनूपपुर सीट से हैं। बदनावर सीट से पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सुवासरा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग को भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है।

एक्सरसाइज कई दौर के विचार मंथन के बीच कंप्रोमाइज उन्होंने भी किया तो भाजपा ने उन्हें यह भी संदेश दे दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा संगठन को विश्वास में लेकर ही उन्हें आगे बढ़ना होगा। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य-शिवराज की केमिस्ट्री कमजोर साबित नहीं हो पाई। जो उन्होंने सामूहिक इस्तीफे के साथ ऑपरेशन लोटस के दौरान बनाई थी। केंद्र का महाराज प्रेम रंग लाया। सिंधिया ने खुद को मजबूत साबित किया और संकेत दिया कि भविष्य की भाजपा में यदि उनकी दिलचस्पी मध्यप्रदेश में बनी रहेगी। तो केंद्रीय राजनीति में वह बड़ा किरदार निभाने की सामर्थ रखते हैं। जिस तरह प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं ने सिंधिया को सम्मान के साथ सरकार बनाने का श्रेय दिया। इससे उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सिंधिया का दबदबा इसलिए और गौर करने लायक है कि सिर्फ शिवराज ही नहीं बल्कि कई दूसरे नेताओं चाहे फिर वह नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय हों, उनके लिए इस कैबिनेट विस्तार में ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आई।

चुनौतियों का समाधान

मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लगातार चौतरफा चुनौतियों से जूझ रहे शिवराज ने भी विभाग वितरण के बाद बड़ा सकारात्मक संदेश दिया कि उन्हें या उनकी पसंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चौहान का धैर्य और संयम बेकार नहीं गया। अपने समर्थक और पसंद के कुछ नेताओं को कैबिनेट में वह शामिल नहीं करा पाए। लेकिन विभाग वितरण के बाद समर्थकों को कमजोर भी साबित नहीं होने दिया। चाहे फिर वह नंबर दो सरकार में माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा जिन्हें गृहमंत्री बनाए रखा गया या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जिन्हें लोक निर्माण विभाग का जिम्मा सौंपा, तो साथ में कुटीर और ग्राम उद्योग भी दे दिया। यदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया के खाते में गया तो अपने सबसे भरोसेमंद भूपेंद्र सिंह के हवाले नगरीय विकास एवं आवास कर दिया। सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य का भाजपा में दबदबा है लेकिन शिवराज ने अपने सिंधिया यानी यशोधरा के पुराने सम्मान को बरकरार रखा। आदिवासी चेहरा विजय शाह को निराश नहीं होना पड़ा जिन्हें वन विभाग तो प्रोटेम स्पीकर रह चुके जगदीश देवड़ा को वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कमल पटेल को यथावत किसान कल्याण एवं कृषि विकास बिना काट-छांट के बरकरार रखा। बुंदेलखंड के बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी खनिज साधन और श्रम जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। जो नरेंद्र सिंह से लेकर विष्णु दत्त शर्मा की पसंद माने जाते हैं। गोपाल, भूपेंद्र, बृजेंद्र के साथ गोविंद ने उस बुंदेलखंड का पलड़ा भारी साबित किया, जहां प्रद्युम्न के साथ भाजपा नई संभावनाओं पर नजर लगाए हुए है। राजधानी का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वास सारंग नई जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा के साथ भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास संभालेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा के पुत्र ओमप्रकाश सकलेचा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया। इंदौर मालवा की राजनीति में संघ की पसंद बनकर उभरी उषा ठाकुर को पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म तो संघ की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाने की जिम्मेदारी मोहन यादव को सौंपी जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया। ऑपरेशन लोटस के फाइटर अरविंद भदौरिया को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति में पार्टी का एक नया कैडर खड़ा करने की लाइन खोल दी। अरविंद की गिनती संगठन के प्रति शत-प्रतिशत समर्पित नेताओं में होती है। शिवराज और ज्योतिरादित्य खेमे से अलग ऑपरेशन लोटस के पहले चरण से जुड़े ऐंदल सिंह कंसाना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर बड़ा संदेश दिया गया। भाजपा जिनका उपयोग उनके प्रभाव वाले क्षेत्र जहां उपचुनाव होना है वहां अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की मंशा रखती है। ऐंदल जो कांग्रेस से भले ही भाजपा में शामिल हुए। लेकिन इससे पहले ग्वालियर-चंबल की राजनीति में तीसरा बड़ा फैक्टर निभाने वाली बीएसपी से जुड़े रहे। कुछ इसी तरह कांग्रेस से पहला इस्तीफा देने वाले हरदीप सिंह डंग को महत्वपूर्ण पर्यावरण विभाग के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी संदेश उन नेताओं के लिए जिनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और भविष्य में हो सकता हैं उनके लिए कि भाजपा जो वादा करती है वह निभाती है।

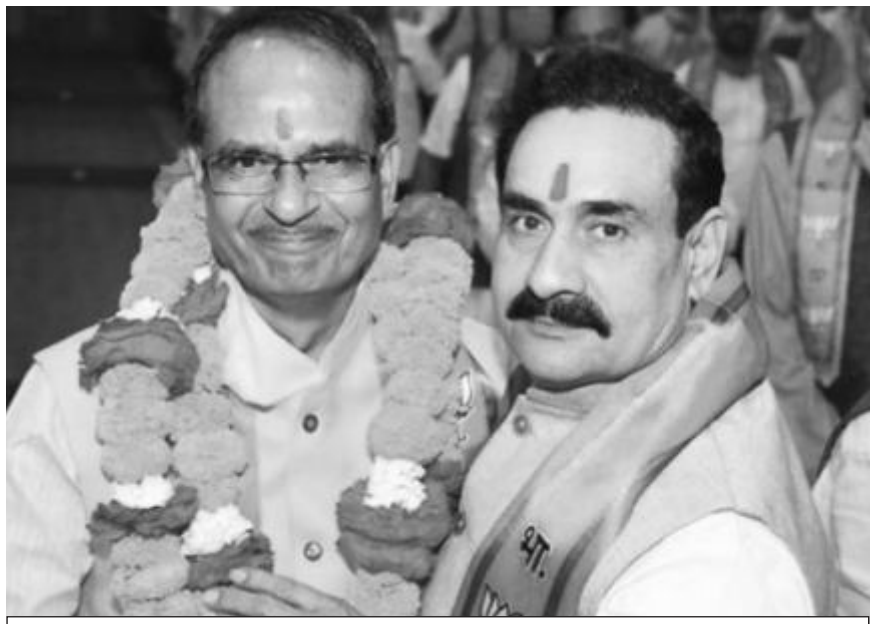

जायसवाल और लोधी को भी मिला सम्मान

कैबिनेट विस्तार के साथ निगम मंडल में एडजस्ट किए गए मंत्री रह चुके निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले प्रद्युम्न सिंह लोधी को कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जिन सपा, बसपा और निर्दलीय ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाकर ज्योतिरादित्य और डॉ. सुमेर सिंह का समर्थन किया। आखिर उनके साथ बे-इंसाफी क्यों की गई। सिंधिया फैक्टर के पहले नरोत्तम मिश्रा के इर्द-गिर्द नजर आने वाली संजू-बबलू की जोड़ी हो या फिर रामबाई के साथ दूसरे निर्दलीय विधायकों की नाराजगी कहीं भाजपा को भविष्य में महंगी तो नहीं पड़ जाएगी। यह वह विधायक है जिनकी शर्त, समझौते और सौदे को लेकर भाजपा में अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इनकी पीड़ा किसी से छुपी भी नहीं है। चाहे फिर वह बसपा विधायक संजू के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बदलती भाजपा हो या फिर प्रद्युम्न लोधी की धमाकेदार एंट्री के साथ सपा से निष्कासित किए जा चुके बबलू भैया राजेश शुक्ला का बुंदेलखंड। यहां भाजपा को कांग्रेस की गलतियों से सीख लेकर इन विधायकों के लिए समय रहते कोई सम्मान का रास्ता निकालना ही होगा। चाहे फिर वह निगम मंडल हो या फिर और दूसरे विकल्प। फिलहाल उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी भाजपा मंत्रियों को विभाग वितरण के बाद राहत महसूस कर सकती है।

उलटी दिशा में दौड़

लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोल ब्लॉक को निजी निवेश के लिए खोलने का ऐलान कर भारत को क्लीन एनर्जी से उल्टी दिशा में दौड़ा दिया है। जो देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगुआ हो और जिस देश का प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति में पर्यावरण रक्षा के तत्वों को दुनिया के तमाम मंचों पर विश्लेषित करता हो, वहां भारी प्रदूषण फैलाने वाले कोयले से बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ावा देने का उसका फैसला चौंकाता है। भारत में कोयला खनन में निजी कंपनियों को उतारने का फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है, जब विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में क्लीन एनर्जी में भारी निवेश किया जा रहा है।

5 साल पहले पेरिस के जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांक्वा ओलांद और यूएन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बान की मून की अगुवाई में इंटरनेशनल सोलर एलांयस का ऐलान किया गया था। दुनियाभर के 122 देश अब इसके सदस्य हैं और इसके जरिए 2030 तक सोलर एनर्जी के लिए 1000 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। खुद भारत ने 2022 तक इसमें अपनी स्थापित क्षमता 100 गीगावाट तक ले जाने की ठानी है। हाल में प्रधानमंत्री ने सोलर अलायंस को दुनिया के लिए एक गिफ्ट बताया था। माना जाता है कि इस अलांयस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक केंद्रीय भूमिका में भी रखने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दिनों देश की कोयला खदानों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के ऐलान के बाद क्लीन एनर्जी, खासकर सौर ऊर्जा पर भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं।

2010 में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। माना जा रहा था कि भारत का तेज **आर्थिक विकास** इसकी ऊर्जा जरूरतों को काफी बढ़ा देगा और कोयला और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती जरूरत के साथ मेल नहीं खाएंगे। इसलिए क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका होगी क्योंकि भारत के बड़े हिस्से में धूप भरपूर रहती है। 2010 में भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सिर्फ 10 गीगावाट की थी लेकिन 2019 में यह बढ़कर 30 गीगावाट तक पहुंच गई। इन 10 वर्षों में भारत में सोलर इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती एनर्जी हो गई। 2015 में सोलर एलायंस के ऐलान के बाद तो देश के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में जबर्दस्त इजाफा हुआ। सिर्फ तीन साल में ही यानी 2016 से 2019 के बीच सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता पांच गुना बढ़ गई। लेकिन इस गति को ब्रेक लग गई। अब पिछले दो-तीन साल से देश सौर ऊर्जा के विकास में बेहद धीमा चल रहा है। लिहाजा यह सवाल लाजिमी है कि आखिर इस धीमेपन की वजह क्या है?

दरअसल, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेज दौड़ने के लिए बनाई गई नीतियां ही अब इसके लिए स्पीड ब्रेकर बन गई हैं। ऊर्जा पर बनी संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में ही क्लीन एनर्जी का टारगेट पूरा न कर पाने के कारण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की खिंचाई की है। इसमें सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश में पिछड़ने का साफ तौर पर जिक्र है। देश में पिछले दो-तीन साल में सोलर एनर्जी पैदा करने की क्षमता में काफी कमी आई है। 2017-18 में यह क्षमता 9.4 गीगावाट की थी। 2018-19 में यह घटकर 6.5 गीगावाट पर आ गई और 2019-20 में तो यह गिरकर और नीचे यानी 2.9 गीगावाट पर पहुंच गई। 2022 तक भारत को 100 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करना है लेकिन अब तक कुल 31 गीगावाट की स्थापित क्षमता ही हासिल हो सकी है। अहम सवाल यह है कि क्या दो साल में हम 69 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल कर लेंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत में अच्छी रफ्तार पकड़ने के बावजूद सोलर एनर्जी में अपनी स्थापित क्षमता बढ़ाने में हम किन वजहों से चूक रहे हैं? इसकी तीन-चार मोटी वजह है, जिन्हें समझना जरूरी है।

सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 के तहत री-न्यूबल परचेज एग्रीमेंट की व्यवस्था की है। इसके तहत राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों और बिजली की बड़ी उपभोक्ता कंपनियों के लिए अपनी खपत की 17 फीसदी बिजली सोलर एनर्जी के तौर पर खरीदना जरूरी कर दिया गया। लेकिन नियामक एजेंसियां इस नियम को सख्ती से लागू नहीं कर पाईं। दूसरे, सोलर एनर्जी खरीदने वाली राज्य की बिजली वितरण कंपनियां, सोलर पावर सप्लायर्स के पैसे देने में देरी करने लगीं। पिछले साल जुलाई तक राज्य बिजली वितरण कंपनियों पर सोलर पावर सप्लायर्स कंपनियों का 9736 करोड़ रुपए बकाया था। जिन राज्यों ने सोलर एनर्जी खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, वही सबसे बड़े बकायेदार बनकर उभरे। सोलर पावर सप्लायर कंपनियों का राज्यों पर जितना बकाया है, उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की 75 फीसदी हिस्सेदारी है।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

आम उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश भी नाकाम

भारत ने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 2022 तक 40 हजार मेगावाट की क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए शुरू में सरकार ने सारे रूफ-टॉप सोलर प्रोजेक्ट पर 30 फीसदी तक सब्सिडी देनी शुरू की। लेकिन जल्दी ही यह सब्सिडी सिर्फ गैर लाभकारी संस्थानों और सरकारी भवनों की छतों पर लगने वाले सोलर पैनलों तक सीमित कर दी गई। इसके अलावा बाहर से आने वाले फोटो वोल्टिक मॉड्यूल पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से भी ये महंगे हो गए। सरकार जिन उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, वे अब इस एनर्जी से दूर होने लगे। इस तरह आम उपभोक्ताओं के बीच सोलर एनर्जी को लोकप्रिय बनाने की सरकार की योजना भी धराशायी हो गई। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार फिर कोयला खनन के दोहन की नीति पर उतर आई है। यानी क्लीन ऊर्जा की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षा सीधे पलटी खाती दिख रही है।

भारत इस समय चीन के साथ मोर्चा लड़ा रहा है। साथ ही अन्य पड़ोसी देशों से भी जूझ रहा है। ऐसे समय में पूरा देश एक सूत्र में बंधा नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रनीति के समय में राजनीति कर रही हैं। चाहे वह सत्तारूढ़ भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी। सबकी यही कोशिश है कि वे किस तरह एक-दूसरे को नीचा दिखाए। इससे पूरे विश्व समुदाय में यह संदेश जा रहा है कि भारत अपनी एकता और अखंडता को लेकर एक मत नहीं है। इसलिए पार्टियां इस समय राष्ट्रनीति पर अपना फोकस करें।

राष्ट्रनीति का समय

मोदी-शाह भी 'बांटो और राज करो' की कांग्रेसी नीति पर

भाजपा ने अपने राजनीतिक और चुनावी प्रतिद्वंद्वी को जिस तरह पीछे छोड़ दिया है और जनमत पर हावी होने की होड़ में भी उसे जिस तरह मात दे दी है, उसके बाद उसे कांग्रेस से, खासकर उसके मौजूदा अवतार में, शायद ही कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस से एक बड़ा सबक जरूर सीखा है- 'बांटो और राज करो' वाला सबक। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और असम तक भाजपा की कई प्रादेशिक इकाइयों में दबी-खुली गुटबाजी और अंदरूनी झगड़े बेकाबू जारी हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी के ये दो सर्वेसर्वा इन झगड़ों को जारी रखने की खुशी-खुशी छूट दिए हुए हैं। यह कांग्रेस की पुरानी चाल रही है, उसका आलाकमान यानी गांधी परिवार अपने मातहत नेताओं में आपसी टक्कर से खुश होता रहा है ताकि वे परिवार की मेहरबानी के मोहताज बने रहें, कोई भी उनके लिए खतरा बनकर न उभरे और उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे। मोदी-शाह ने भी यही रणनीति अपना ली है। वे इतने ताकतवर तो हैं ही और पार्टी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत तो है ही कि वे आपस में भिड़ रहे गुटों पर लगाम कस सकें और अंदरूनी टकरावों को शांत कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लेह यात्रा की अलग-अलग नजरिए से व्याख्या संभव है, लेकिन सच यही है कि अपनी चौंकाने वाली कार्यशैली के इस नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण कदम से उन्होंने एक साथ कई निशाने साधे हैं, कई संदेश दिए हैं। यह संदेश बिना संवेदनशीलता महसूस किए हर मुद्दे पर राजनीति करने के आदी राजनीतिक दलों से लेकर भारत की शांतिप्रियता को कमजोरी समझने वाले चीन और भारत के अहसान भुलाकर चीन के पिट्ठू बनने को उतावले कुछ देशों तक सभी के लिए है। अब चाहे इसे मोदी का 'मास्टर स्ट्रोक' कहें या फिर 'सरप्राइज स्ट्राइक' मोदी ने अपनी शैली में सभी को जवाब दे दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की त्वरित टिप्पणी बताती है कि संदेश सही जगह, सही रूप में पहुंच भी गया है। बाकी की प्रतिक्रियाएं आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा।

गत 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक भिड़ंत और उसमें 20 भारतीय सैनिकों की **शहादत के बाद बने माहौल में** बढ़ता तनाव हर कोई महसूस कर रहा है। जाहिर है, चीन ने एक बार फिर अपने विश्वासघाती चरित्र का ही परिचय दिया था, लेकिन अतीत से सबक सीखे बिना बार-बार विश्वासघाती पर विश्वास करना भी काबिले तारीफ तो नहीं माना जा सकता। अभूतपूर्व कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में गोपनीयता समेत तमाम कारणों से सरकार की अपनी सीमाएं रही होंगी। फिर भी सभी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता का ही संदेश दिया था, लेकिन उसके बाद अलग-अलग राजनीतिक राग अलापने में भी देर नहीं लगी।

राजनीति बुरी बात नहीं है। सवाल पूछना तो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, लेकिन हर चीज का समय और सीमा होती है। अगर कोरोना से लेकर गलवान घाटी तक हर मुद्दे पर आलोचना का मकसद सिर्फ केंद्र सरकार या और स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री मोदी को कठघरे में खड़ा करना रह जाएगा, तब वह प्रासंगिकता खोकर खीझ से उपजा अनर्गल प्रलाप भर रह जाएगा, जबकि यह समय राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का है। मोदी सरकार और भाजपा भले कहे कि लॉकडाउन समेत समय पर उठाए गए कदमों से कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने में मदद मिली, पर संक्रमितों के आंकड़ों में आए दिन की उछाल का सच तो नहीं छिप सकता। जाहिर है, संभावित परिस्थितियों के आंकलन और उनसे निपटने की रणनीति बनाने में सरकार से चूक हुई है, पर यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक से कब क्या चूक हुई, उसकी जिम्मेदारी-जवाबदेही की बहस बाद में भी हो सकती है। फिलहाल तो देश के कुछ हिस्सों में बेकाबू नजर आ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण तथा संभावित परिस्थितियों के अनुरूप हर मोर्चे पर तैयारियां ही हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

कोरोना से संक्रमित भारत अकेला देश नहीं है। अन्य देशों की सरकारों से भी स्थिति के आंकलन और तैयारियों में चूक हुई होगी, पर क्या वहां कहीं भी **दलगत राजनीति** से प्रेरित आरोप-प्रत्यारोप का शर्मनाक खेल दिखा? कोरोना किसी भी सरकार की विफलता का परिणाम नहीं है। हां, उससे निपटने की रणनीतियों में विफलता की जिम्मेदारी-जवाबदेही अवश्य सरकारों पर आयद होती है। यह भी कि ऐसी महामारी से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार

के भरोसे भी नहीं छोड़ी जा सकती। दरअसल ऐसे किसी भी संकट से बिना सामाजिक भागीदारी और सामूहिक प्रयास के पार पाई ही नहीं जा सकती। अब यह बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि राजनीतिक दल भी समाज का ही हिस्सा हैं, जो कोरोना संक्रमण रोकने और उसके लिए सामाजिक जागरूकता फैलाने में कहीं प्रयासरत नहीं दिखे। हां, वे चिकित्सा विशेषज्ञों से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक द्वारा बार-बार की जा रही मास्क, सामाजिक दूरी और बार-बार **हाथ धोने की अनिवार्यता सावधानी** की अपील की धज्जियां उड़ाते अवश्य दिखे। खुद भाजपा सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान ही सोनीपत में बिना मास्क क्रिकेट खेलने आए तो हाल ही में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार के समय अनेक मंत्री-विधायक बिना मास्क ही सामाजिक दूरी की अवधारणा की धज्जियां उड़ाते टीवी न्यूज चैनलों पर नजर आए।

अब दूसरे बड़े संकट की ओर लौटते हैं। वैसे विडंबना यह है कि कोरोना हो या गलवान, दोनों ही संकट चीन के धूर्त और विश्वासघाती चरित्र की ही देन हैं। सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ही यह आरोप नहीं है कि न सिर्फ चीन की लैब से कोरोना वायरस फैला, बल्कि उसने विश्व समुदाय को समय रहते इसके प्रति आगाह भी नहीं किया। चीन जिस तरह इस संक्रमण को वुहान शहर या हद से हद एक प्रांत तक सीमित रखने में सफल रहा, और इस बीच कोरोना संकट में जरूरी चिकित्सा उपकरणों समेत तमाम चीजों का भारी स्टॉक भी कर लिया, उससे तो किसी सुनियोजित बड़ी साजिश का संदेह और भी गहराता है। उसी कोरोना संकटकाल में चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा में जमीनी वास्तविकताएं बदलने की भी साजिश रची। कारणों पर बहस हो सकती है, पर यही सच है कि दशकों से भारत की सुरक्षा चिंताएं और सामरिक तैयारियां पाकिस्तान केंद्रित ही रही हैं। खासकर समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनेता और विचारक समय-समय पर केंद्र सरकार को चीन के नापाक मंसूबों के प्रति आगाह भी करते रहे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद टास्क फोर्स और विशेष प्रतिनिधि स्तर पर शुरू हुई सीमा वार्ता वजह रही हो या फिर चीन द्वारा बनाई गई अपनी विश्व महाशक्ति की छवि केंद्र सरकार भारतीय सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की हरकतों को नजरअंदाज कर तूल देने से परहेज करती रही।

ध्यान रहे कि तीन दशक से भी ज्यादा समय तक दोनों देशों के रिश्तों में जमी रही बर्फ 1988 में तब पिघली थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। तत्कालीन चीनी नेतृत्व देंग शियाओ पिंग ने भी भारत के युवा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की उम्मीद जताई थी। उसके बाद ही सीमा विवाद निपटारे के लिए टास्क फोर्स बनी, जिनमें बाद में अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में विशेष प्रतिनिधि शामिल करने का भी फैसला हुआ।

गलवान अचानक नहीं हो गया। अरुणाचल, सिक्किम और यहां तक कि उत्तराखंड में भी पिछले कई दशकों में चीनी सेना की नापाक हरकतें जारी रही हैं। बेशक दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं में इस तनाव को कम किया जाता रहा, लेकिन उस प्रक्रिया, जिसे अब दिखावा कहना ज्यादा सही लगता है, के बीच भी चीन का धूर्त और विश्वासघाती चरित्र नहीं बदला। गलवान घाटी में 15 जून की भिड़ंत इसका सबसे ताजा प्रमाण है। जब अन्य देशों की तरह भारत भी कोरोना के भयावह संकट से अपने नागरिकों का जीवन बचाने के लिए जूझ रहा है, चीनी सेना ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। हमारे 20 सैनिकों की शहादत का सच सबके सामने है, पर मारे तो चीनी सैनिक भी गए हैं, जिनकी संख्या न तो चीन बता रहा है, न ही वहां कोई पूछ भी रहा है। तर्क दिया जा सकता है कि चीन में तानाशाही है, जबकि भारत में लोकतंत्र। बेशक यह बड़ा और बुनियादी फर्क है, जो दोनों देशों के चरित्र में भी साफ नजर आता है, लेकिन कम से कम संकटकाल में तो राष्ट्रहित में राजनीति पर कुछ समय के लिए विराम लगा देना चाहिए।

कुछ लोग मोदी की एलएसी यात्रा को संभावित युद्ध का संकेत मान रहे हैं। निश्चय ही इस यात्रा से उन सैनिकों को बड़ा हौसला मिला होगा, जो बेहद प्रतिकूल और जटिल परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दुर्गम स्थानों पर दिन-रात डटे रहते हैं। 2020 में हम जैसी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसमें किसी भी स्थिति की संभावना-आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हर समझदार इंसान जानता है कि युद्ध अक्सर अंतिम विकल्प तो माने जाते हैं, पर समस्या हल करने के बजाय नई समस्याएं ही पैदा करते हैं। इसलिए चीनी ऐप, निवेश और कारोबार पर हर संभव लगाम कसते हुए कूटनीति के जरिए अलग-थलग कर चीन पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह 21वीं शताब्दी में विस्तारवादी मानसिकता को त्याग कर विकासवाद के रास्ते पर चले। वही सभी के हित में है।

● **इन्द्र कुमार**

चीन के खिलाफ मंत्रियों के ऊंचे बोल

अब गौर करें जून 2020 की स्थिति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पाकिस्तान को दंडित करने के लिए 2016 और 2019 में क्रमशः 'सर्जिकल स्ट्राइक' और हवाई हमले किए थे। वहीं उनके मंत्री अब चीन पर एक के बाद एक जुबानी हमले करने में उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। संचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने 'डिजिटल स्ट्राइक' कर दिया है। गरजते हुए उन्होंने कहा, 'हम भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।' अगले दिन ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की 'थर्मल और सोलर हमले' करने की बारी थी और उन्होंने घोषणा की कि भारत अब चीन से बिजली उपकरणों का आयात नहीं करेगा। उसके बाद राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहते हुए चीन पर रोड रोलर चढ़ा दिया कि भारत की राजमार्ग परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। गडकरी के जूनियर मंत्री जनरल (सेवानिवृत) वीके सिंह पहले ही आह्वान कर चुके हैं, 'पहले उन पर आर्थिक चोट करते हैं। बाकी चीजें बाद में होंगी।' टीवी स्टूडियो में जुटने वाले भाजपा के योद्धा सबको 1962 की पराजय की याद दिलाने और यह बताने से नहीं चूकते हैं कि कैसे मोदी जवाहरलाल नेहरू से अलग हैं।

विरासत की वक्रदृष्टि

गांधी परिवार पर विरासत की कैसी वक्रदृष्टि पड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से शुरु हुई कहानी अब गांधी परिवार से जुड़े तीन और संस्थानों - इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच चुकी है।

करीब 70 वर्षों तक देश की सत्ता पर आसीन रहा नेहरू-गांधी परिवार आज भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों से घिरा हुआ है। इस परिवार की देखरेख में चल रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के इतने नए और बड़े मामले सामने आए कि 2014 में जनता ने इस गठबंधन से किनारा कर लिया और अब तो लगता है कि जनता में खासकर गांधी परिवार के प्रति विशेष नाराजगी है। शायद यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार राहुल गांधी विरासत में मिली उप्र की अमेठी सीट से चुनाव हार गए।

दरअसल, ताजा घटनाक्रमों को देखेंगे तो लगेगा कि गांधी परिवार पर विरासत की ही वक्रदृष्टि पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहर लाल नेहरू की नीतियों पर बार-बार प्रहार किया तो राजीव गांधी के 'एक रुपए भेजता हूं तो 10 पैसे ही मिलते हैं' वाले बयान को यह कहकर भुनाया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी, खासकर गांधी परिवार की अगुवाई में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। बहरहाल, गांधी परिवार पर विरासत की कैसी वक्रदृष्टि पड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से शुरू हुई कहानी अब गांधी परिवार से जुड़े तीन और संस्थानों- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच चुकी है।

गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े इन तीन ट्रस्टों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। इन पर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी के आरोप हैं। तीनों ट्रस्ट पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप है। अब एक इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी इन तीनों ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की जांच करेगी।

चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस के लिए भाजपा के इस आरोप का जवाब देना कठिन हो सकता है कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से आर्थिक सहायता लेने की क्या जरूरत थी? यह महज राजीव गांधी के नाम पर बना फाउंडेशन नहीं है। यह वह फाउंडेशन है जिसकी मुखिया कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और जिसके बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य अनेक कांग्रेसी नेता शामिल हैं। इस तरह की किसी संस्था की ओर से किसी भी विदेशी दूतावास से धन लेना कई सवालों को जन्म देता है और तब तो और भी जब वह विदेशी दूतावास चीन का हो। पता नहीं राजीव गांधी

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट

एक रजिस्टर्ड, नॉट-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के रूप में ट्रस्ट की स्थापना 2002 में हुई। इसका मकसद देश के गरीबों की मदद करना था, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। इसकी दो योजनाएं हैं- राजीव गांधी महिला विकास परियोजना और इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दावा है कि उप्र में महिला सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी महिला विकास परियोजना सबसे बड़ा मोबलाइजेशन प्रोग्राम चला रही है। वहीं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 12 जिलों में आई केयर की सुविधा देती है। वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन की नींव 21 जून, 1991 को रखी गई। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा पर फोकस करने का फैसला किया। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। ट्रस्टीज में डॉ. मनमोहन सिंह, पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन लेना जरूरी क्यों समझा? यदि यह आवश्यक ही था तो फिर इस बारे में तभी पूरी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। अब तो आम धारणा तो यही बनेगी कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने गुपचुप रूप से चीन से धन लिया। ध्यान रहे कि यह धन तब लिया गया जब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही थी। इस बारे में कांग्रेस अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन उससे संतुष्ट होना कठिन है। हैरत नहीं कि भाजपा के आरोप से तिलमिलाई कांग्रेस मोदी सरकार पर कुछ और तीखे हमले करने के लिए आगे आए। वैसे भी कांग्रेस और खासकर उसके नेता राहुल गांधी यह साबित करने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन के **आगे हथियार डाल दिए हैं।** वह यह भी सिद्ध करने में तुले हैं कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है। इस बारे में वह न तो प्रधानमंत्री के बयान को महत्व देने के लिए तैयार हैं और न ही उनके स्पष्टीकरण को।

पता नहीं वह सरकार पर अनावश्यक राजनीतिक हमले कर क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस का आचरण जाने-अनजाने चीन का दुस्साहस बढ़ाने वाला है। एक ऐसे समय जब देश चीन की खतरनाक आक्रामकता से दो-चार है तब जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत चीनी सत्ता की गुंडागर्दी के समक्ष एकजुट है।

संकट के समय राजनीतिक कलह ठीक नहीं। कम से कम कांग्रेस सरीखे सबसे पुराने राजनीतिक दल को तो राजनीतिक परिपक्वता दिखानी ही चाहिए। यह हैरत की बात है कि अन्य दल गंभीरता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने से इंकार कर रही है। नि:संदेह भाजपा को कांग्रेस के राजनीतिक हमलों का जवाब देना ही होगा, लेकिन उसे इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि चीन को लेकर देश में राजनीतिक एका का माहौल बने।

आइए पहले समझते हैं एजेएल मामले को: जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2008 में एजेएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई अव्यवसायिक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76 फीसदी शेयर थे जबकि बाकी के 24 फीसदी शेयर अन्य निदेशकों के पास थे।

सवालों के घेरे में ट्रस्ट और फाउंडेशन को मिले दान

हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पी. चिदंबरम ट्रस्टी हैं। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गलत इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किया गया। कई सरकारी उपक्रमों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किया था। इनमें गृह मंत्रालय समेत 7 मंत्रालय और 11 बड़े सार्वजानिक उपक्रम भी शामिल थे। यह सब दान तब किए गए जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थीं। राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत स्थित चीनी दूतावास, चीन सरकार, जाकिर हुसैन के साथ-साथ करोड़ों रुपए के घोटाले में फरार मेहुल चोकसी ने भी दान दिया था।

अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई और पंचकूला स्थित एजेएल की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार के बिल्कुल करीबी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा भी फंसे हैं। आरोप है कि इन्होंने एजेएल को हरियाणा के पंचकूला में एक प्लॉट के आवंटन में कानूनों का उल्लंघन किया। यह मामला उस समय का है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे। इस मामले में हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सहायक कंपनी एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया था। इस मामले में सीबीआई ने भी पंचकूला की एक अदालत में दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने भी इस मामले में कथित अनियमितता बरतने को लेकर वोरा और हुड्डा को आरोपी बनाया है।

ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसकी शुरुआत 2001 में ऑर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की शुरुआत से हुई। बाद में ट्रस्ट के तहत डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज भी खोले गए। वेबसाइट के अनुसार, आईजीएमटी की अध्यक्षता केएम पारीख करते हैं। इसके अलावा, डॉ. केपी शियास महासचिव हैं, डॉ. केपी सियाद सीईओ और केपी शिबु मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह नई दिल्ली में 1 अकबर रोड पर तुलग रोड इलाके में हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेसी सरकारों के दौरान खजाने की लूट के लिए कई तरीके इजाद किए गए थे। इसी के तहत ये फाउंडेशन और ट्रस्ट गठित किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने इनकी गतिविधियों और फंड की जांच शुरू करा दी है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

पार्टी विथ डिफरेंस वाली भाजपा को सत्ता से दूर होते ही न जाने किसकी नजर लग गई है। अपनी एकता और अखंडता के बड़े-बड़े दावे करने वाली इस पार्टी में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। गुटबाजी का आलम यह है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी अटक गई है। सभी नेता अपने-अपने गुट के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं।

वर्चस्व की महाभारत

छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की नियुक्ति गुटबाजी में फंस गई है। जानकारी के मुताबिक अलग-अलग खेमा प्रदेश कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शामिल कराने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं मोर्चा प्रकोष्ठ में भी अपने खास लोगों को महत्वपूर्ण पद दिलाने की होड़ लगी हुई है। इतना ही नहीं गुटबाजी की वजह से जिन 11 जिलों में जिला अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो पाया था वो अब तक खेमेबाजी में ही उलझा है। मनोनयन नहीं हो पा रहा है, हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में प्रदेश भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पसंद को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की चर्चा है। यही वजह है कि दूसरे गुट भी सक्रिय हो गए हैं और कई पदों पर सिर फुटौवल के हालात होने लगे हैं।

ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदों के प्रमुख दावेदार दोनों गुटों में तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं। बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष बनाए जाने हैं। इनमें महत्वपूर्ण पदों के लिए तीन पूर्व मंत्रियों के नाम तय माने जा रहे हैं। चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद संगठन के सबसे प्रभावशाली **महामंत्री पद पर पूर्व मंत्री** राजेश मूणत की ताजपोशी तय है। इसी तरह पूर्व मंत्री महेश गागड़ा या केदार कश्यप में से किसी एक को भी महामंत्री बनाया जा सकता है। एक महामंत्री का पद वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा को दिया जा सकता है। इसी तरह कुछ पूर्व विधायकों को उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और मोर्चा-प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर बैठाने की चर्चा है। ये भी तय मानकर चला जा रहा है कि युवा और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे।

राजधानी रायपुर में जिला अध्यक्ष के दावेदारों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर से लेकर वॉट्सएप ग्रुप में बड़े नेताओं पर जोरदार टिप्पणी की जा रही है। भाजपा के आला नेताओं के एक वॉट्सएप ग्रुप महाभारत-चक्रव्यूह में पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारियों को निशाने पर ले रहे हैं। इसमें विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हार का ठीकरा जिन नेताओं के सिर फोड़ा जा रहा है, उसमें से अधिकांश जिलाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। आला नेताओं वाले ग्रुप में गंदे और भद्दे कमेंट को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई है कि सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी का अनुशासन तार-तार हो गया है।

ग्रुप में एक कार्यकर्ता तो जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल के लिए अपशब्द के साथ-साथ गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। एक पदाधिकारी ने कमेंट किया- 'कार्यकर्ता जब तक चापलूसी करेगा, तब तक शोषित होगा। सेनापति वही जो हमेशा चौकन्ना रहे।' सोशल मीडिया पर अनूप मसंद और राजीव अग्रवाल का संवाद भी वायरल हो रहा है। इसमें राजीव अग्रवाल कह रहे हैं, हार कर देखो, बहुत आनंद आता है, लेकिन यह भी सभी के भाग्य में नहीं होता है। दरअसल, भाजपा में नए जिलाध्यक्ष की दौड़ में तीन प्रमुख नेताओं के नाम आ रहे हैं। ये सभी पिछले पांच साल से जिलाध्यक्ष रहे राजीव अग्रवाल को हटाकर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्यकर्ता राजीव को निशाने पर ले रहे हैं।

नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से पहले कई मंडलों में कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है। पहले तेलीबांधा मंडल की कार्यकारिणी को लेकर विवाद हुआ था। अब जवाहर नगर मंडल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि एकात्म परिसर में ही दो पदाधिकारियों का गुट आपस में भिड़ गया। एक पदाधिकारी का कहना था कि कार्यकारिणी की घोषणा नए जिलाध्यक्ष के आने के बाद की जाए। इसको लेकर तू-तू, मैं-मैं तक हो गई।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

विकास की चिड़िया खोज रही भाजपा

छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विकास की चिड़िया खोजने का कैंपेन चलाया था। अब डेढ़ साल बाद उस कैंपेन को भाजपा शुरू करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट किया, विकास की चिड़िया पता नहीं छत्तीसगढ़ में डेढ़ साल से कहां उड़ रही है? न सड़क, न अस्पताल, न स्कूल, न कॉलेज, न रोजगार, न शराबबंदी, न समर्थन मूल्य, न रोजगार भत्ता। वो चश्मा और आईना कहां गया, जिसमें यह सब दिखता था। डॉ. रमन ने भूपेश बघेल द्वारा 18 अप्रैल 2018 को किए गए एक ट्वीट पर यह तंज कसा है। डॉ. रमन राज्य सरकार पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रमन मुख्यमंत्री बघेल पर ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं। भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए 2018 में गुमशुदा विकास की चिड़िया पर तंज कसते हुए आईना दिखाने की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई वीडियो जारी कर चश्मा और आईना के जरिए प्रदेश में विकास के दावों को झूठा बताते हुए दिखाया था। अब रमन ने एक बार फिर भूपेश सरकार को उनके वादों की याद दिलाई है, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

खतरा टला... लेकिन कब तक?

राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। यानी पायलट की कांग्रेस से विदाई हो गई है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायक दल की बैठक में अपना संख्या बल साबित करने के बाद सचिन पायलट के मंसूबों का जहाज क्रैश कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल सचिन पायलट पर भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस ने पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं उनके दो समर्थक मंत्रियों की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। अब सचिन पायलट राजनीति के तिराहे पर आकर खड़े हो गए हैं यानी उनके सामने तीन सियासी विकल्प हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस दिशा में वे अपना कदम बढ़ाते हैं।

सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में सुलह समझौते के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि पार्टी से उन्हें बाहर निकाला नहीं गया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा हैं और पार्टी के कई युवा उनके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मान-सम्मान के लिए दबाव डाल सकते हैं। पायलट अगर कांग्रेस आलाकमान से संवाद करेंगे तो सुलह का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। पायलट ने बगावत का **झंडा उठाकर अपना सियासी नुकसान** जरूर किया है। अब वे न तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और न ही उपमुख्यमंत्री। इतना ही नहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच अपना विश्वास भी खो दिया है। अगर पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो आगे के सियासी राह के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो उनका कद है वो किसी दूसरी पार्टी में भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में रहते हुए अपने लोगों को मजबूत करने के साथ-साथ अपने काम से कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस पा सकते हैं। पायलट की उम्र भी कोई खास नहीं है और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। सचिन पायलट के पास दूसरा विकल्प है कि अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर कांग्रेस से इस्तीफा दें और भाजपा में शामिल हो जाएं। इसके लिए पायलट को अपने समर्थकों को भाजपा में शामिल होने और विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा। वहीं, भाजपा ने पायलट और उनके समर्थकों के स्वागत के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं।

सचिन पायलट अगर भाजपा में जाकर कांग्रेस की सरकार गिराने में सफल रहते हैं तो गहलोत से अपना सियासी बदला ले लेंगे। इतना ही नहीं अपने समर्थकों को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी भी दिलाने में सफल हो जाएंगे। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए यह बहुत मुश्किल है। गहलोत को सत्ता से हटाने के लिए पहले तो उन्हें करीब 30 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा और उनसे इस्तीफा दिलाना होगा। यह काफी अहम और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, अगर भाजपा में जाकर भी गहलोत सरकार को गिराने में सफल नहीं रहते हैं तो उनकी राजनीतिक साख को तगड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं भाजपा में भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की क्या अहमियत है वो जगजाहिर है।

सचिन पायलट के सामने तीसरा रास्ता भाजपा-कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाने का है। इसके लिए कांग्रेस के एक तिहाई विधायक चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर उसकी अगुवाई करें और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सीधे चुनौती दें। पायलट के इस विकल्प पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है कि क्योंकि उनके समर्थक भी इस पर मंथन कर रहे हैं। सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो उनके लिए अपनी क्षमता को दिखाने का पूरा मौका होगा। उपचुनाव में अपने समर्थकों के साथ उतरना होगा, जो काफी चुनौती भरा है। हालांकि, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि दो पार्टी सिस्टम ही चलता है। अगर पायलट तीसरा मोर्चा बनाने का रास्ता चुनते हैं, तो यह जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है।

क्षेत्रीय पार्टी के लिए बहुत अच्छा स्कोप राजस्थान में नहीं है। प्रदेश में किरोड़ीलाल मीणा, कर्नल बैसला, दिग्विजय सिंह, हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेता क्षेत्रीय पार्टी बनाकर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सभी फेल रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी का फैसला काफी **चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है।** अशोक गहलोत ने नंबर गेम के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन किया है, वो तत्कालिक ही लगता है। वो कोई स्थायी भाव नहीं है। ये सब सत्ता की बयार के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के चलते सिर्फ वे ही विधायक बैठक से दूर रहे जो सचिन पायलट के प्रति निष्ठावान हैं। जरूरी नहीं कि अशोक गहलोत की आंखों के सामने बैठे सभी विधायक उनके प्रति निष्ठावान ही हों। अगर उनको ये भनक होती कि अशोक गहलोत के कुर्सी पर बैठने का टाइम खत्म हो गया है तो वैसा मजमा नहीं लगता। न तो अशोक गहलोत जादू दिखा पाते और न ही कुर्सी बचा पाते।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

चूक तो गए ही हैं सचिन पायलट... अब तो सचिन पायलट भी उस हकीकत से वाकिफ हो चुके होंगे कि देश में उपमुख्यमंत्री होने का मतलब क्या होता है। उपमुख्यमंत्री होने का कोई मतलब तभी है जब तेजस्वी यादव के पीछे लालू प्रसाद यादव बैकअप सपोर्ट सिस्टम बने हुए हों और सुशील मोदी के साथ अमित शाह और पूरा भाजपा अमला। सचिन पायलट खून का घूंट पीकर खामोश तो तभी हो गए थे जब अशोक गहलोत को उनके ऊपर मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया गया। जाहिर है मौके की ताक में तो हमेशा ही रहते होंगे। ये तो सचिन पायलट भी जानते ही थे कि उनको दरकिनार करने की होने वाली कोशिशों में ये भी एक और कड़ी है।

आपराधिक साठगांठ

मुकदमों के निस्तारण में बहुत समय लगता है

अदालतों में मुकदमों के लंबा खिंचने की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में 2018 में विभिन्न न्यायालयों में कुल 10,27,583 मुकदमे विचाराधीन थे। इसमें केवल 65,130 को ही सजा हो पाई और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का प्रतिशत 90.8 रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुकदमों के निस्तारण में बहुत समय लगता है और सजा भी कम ही अपराधियों को होती है। विकास दुबे को ही देखा जाए तो 60 आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के बावजूद वह छुट्टा बाहर घूम रहा था। एक मंत्री की हत्या तक में उसे सजा नहीं हो सकी। यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है? समग्र स्थिति पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सिविल एवं पुलिस सेवा और राजनीति सभी में दीमक लग गया है। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है। न्याय व्यवस्था आम आदमी को तो दंड दिला देती है, परंतु जो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली है, उनके विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं और पुलिस में कानून के प्रति प्रतिबद्धता गिरती जा रही है। अधिकांश अधिकारी अपने हितों की आपूर्ति में ही लगे हैं। राजनीति का स्तर और गिरता जा रहा है। देशद्रोह की बात करने में भी लोग अपनी शान समझने लगे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। पुलिस सुधार की बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। यदि इन हालातों में सुधार नहीं लाया गया तो एक दिन देश से लोकतंत्र का जनाजा उठ जाएगा। आवश्यकता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन की- सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक ढांचे में, न्याय व्यवस्था में, सिविल सेवा और पुलिस की कार्यप्रणाली में और सबसे अधिक राजनीतिक परिवेश में।

अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकाल की शरण में पहुंचने के बाद भी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे बच नहीं पाया और उप्र पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। उप्र पुलिस से बचने के लिए विकास दुबे ने तीन राज्यों का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले उप्र पुलिस पिछले 8 दिनों में उसके 5 साथियों का एनकाउंटर कर चुकी थी। दुबे के गांव स्थित मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर चुकी थी। आखिरकार वही हुआ, जिसका गैंगस्टर विकास दुबे को डर था। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े जिस तरह के संदेह पिछले 8 दिनों से चर्चा में थे, आखिरकार हुआ भी वही। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि **न्यायपालिका से पहले भी पुलिस न्याय कर सकती है।** खासतौर से ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर, जिनके पकड़े जाने के बाद पुलिस, राजनीति और अपराध के बीच के गठजोड़ के कई खुलासे हो सकते हैं।

हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय-समय पर वीरगति को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु जैसी घटना कानपुर में हुई वैसी सामान्यत: हमें कश्मीर, पूर्वोत्तर से या नक्सल प्रभावित इलाकों से ही सुनने को मिलती रही हैं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के बलिदान की घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और यहां न तो जंगल हैं और न ही आतंकवादियों की पैठ। एक कुख्यात अपराधी द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस भीषण वारदात को लेकर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह घटना हुई कैसे? आरोपित विकास दुबे कहां है, इसकी पूरी जानकारी थी। तीन थानों की पुलिस उसे पकड़ने जाती है, परंतु उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस दल तैयारी के साथ नहीं गया। कई पुलिसकर्मियों के पास कोई हथियार नहीं था। न तो किसी के पास बुलेटप्रूफ जैकेट थी और न किसी ने हेलमेट पहन रखा था। फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीति के जो नियम होते हैं उन सबकी अवहेलना करते हुए दबिश दी गई।

दूसरी बड़ी विचित्र बात यह कि पुलिस का अभिसूचना तंत्र लगभग शून्य था, जबकि विकास दुबे को पुलिस की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि किसी ने तो विकास दुबे के लिए मुखबिरी की। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी ने ही उसे आगाह किया था। यह और शर्म की बात हो जाती है। इससे तो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। पुलिस बल को अपनी असावधानी और तैयारी से न जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा।

कानपुर की घटना को और गहराई में भी देखने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आज नेता, सरकारी तंत्र और अपराधियों के बीच साठगांठ की बड़ी भयंकर समस्या है। इस समस्या की जानकारी सभी को है, परंतु उस पर प्रहार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि विधानमंडलों और संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 143 विधायक यानी कुल संख्या के 36 फीसदी विधायकों के खिलाफ कोई न कोई मुकदमा दर्ज था। इनमें 107 यानी 26 प्रतिशत ऐसे थे जिनके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हमारी विधानसभा में होंगे तो उनसे किस रामराज्य की आशा की जा सकती है? इनका न केवल अपराधियों से मेलजोल होगा, बल्कि उनके ऊपर इनका वरदहस्त भी होगा। ऐसी स्थिति में कानपुर जैसी घटना का होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आप बबूल का बीज डालेंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि विकास दुबे को अलग-अलग समय पर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता रहा। नि:संदेह नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, जनता को भी अपना चेहरा शीशे में देखना होगा। आखिर उन्हीं के वोट से तो ये लोग चुने जाते हैं और प्रदेश एवं केंद्र में विधानसभा-लोकसभा को सुशोभित करते हैं। अपने देश में नाजायज असलहा की समस्या भी काफी गंभीर है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बागी से शासक बनी शिवसेना

शिवसेना को सड़कों उतरने के लिए जाना जाता है। कभी जनता के सहयोग के लिए तो कभी सरकार के खिलाफ शिवसैनिक सड़क पर उतरते रहे हैं। लेकिन जबसे महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनी है, शिवसैनिक सड़कों से नदारद हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में भी शिवसैनिक नदारद हैं। शिवसैनिक अपने व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए हर बार संकट का सामना करता है, लेकिन इस महासंकट में वह गायब हैं। हालांकि जून महीने की शुरुआत में, उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निजी डॉक्टरों के सहयोग से चलाए जा रहे शाखा को क्लीनिक में बदलने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ ही लोग दिखाई दिए।

व्यक्तिगत रूप से, शिवसेना के कई नेता अपने स्वयं के नामों पर राहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के रूप में ठाकरे सरकार के साथ काम करने के लिए पार्टी मशीनरी को सक्रिय करने में विफल रहे। जानकार कहते हैं कि 7 महीने में अगर हम पूछें कि शिवसेना ने सरकार में होने से एक पार्टी के रूप में क्या हासिल किया है, तो इसका जवाब है शून्य।

पिछले साल जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन से सत्ता में लौटने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टकराव हुआ था, तब शिवसेना के 53वें स्थापना दिवस पर पार्टी के मुखपत्र सामना ने एक संपादकीय में कहा था कि अगले साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। एक साल बाद जैसा कि पार्टी 19 जून को 54 साल की हो गई है, **सामना के शब्द** रिंग प्रोपेटिक हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे राज्य के शीर्ष पर हैं और शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन है। लेकिन, पार्टी बागी से शासक के रूप में बदल गई है और भाजपा के साथ टकराव से लेकर त्रिपक्षीय गठबंधन का नेतृत्व करने तक, इस प्रक्रिया ने शिवसेना को कोई ठोस राजनीतिक लाभ नहीं दिया है।

पार्टी के नेताओं का कहना है कि शिवसेना को वास्तव में अभी तक सरकार का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि राज्य में सरकार आते ही कोविड-19 संकट आ गया। हालांकि, राजनीतिक नजर रखने वालों का कहना है कि सरकार के भीतर ठाकरे परिवार का वर्चस्व है। संकट के समय में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति और तीन-पार्टी गठबंधन में शुरुआती झड़पों ने पार्टी की सत्ता में होने से लाभ प्राप्त करने की पार्टी की क्षमता को सीमित कर दिया है। देसाई ने कहा कि पहली शिवसेना सरकार में 1995-1999 तक पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे मनोहर जोशी और नारायण राणे (जो तब पार्टी के साथ थे) दिखाई देते थे। हालांकि, सरकार को पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा नियंत्रित किया गया था। अब एकनाथ शिंदे के अपवाद के साथ, जिन्हें अपने जिले ठाणे से संबंधित मुद्दों पर ज्यादातर देखा और सुना जाता है, केवल आदित्य और उद्धव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में शिवसेना के किसी अन्य मंत्री को बहुत ज्यादा देखा या सुना नहीं गया है। शिवसेना के एक वरिष्ठ विधायक प्रताप सरनाईक ने आलोचना से इंकार किया। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए लग रहा है कि पार्टी ऐसे बनी है। उद्धव साहब और आदित्य शिवसेना हैं। उद्धव साहब पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और वे अपने अंतिम निर्णय पर पार्टी के लोगों से बात करते हैं। अन्य दलों में, एक मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेने से पहले दस लोगों से पूछना पड़ता है।

जबसे उद्धव ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तबसे वे ज्यादातर अपने उपनगरीय मुंबई आवास मातोश्री से काम कर रहे हैं। उनके विश्वासपात्रों की छोटी सूची के साथ जिसमें पुत्र आदित्य, पत्नी रश्मि ठाकरे और कई बार व्यक्तिगत सहायक और पार्टी के सदस्य मिलिंद नार्वेकर और शिवसेना नेता अनिल परब होते हैं। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता जो नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि 'पार्टी के सदस्यों को सरकार के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते हुए उनके शब्दों को देखना होगा। हम आलाकमान से परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं।' फडणवीस, जो अब विपक्ष के नेता हैं, ने कोविड-19 मामलों में बढ़ते मामलों के बीच सिविल सेवकों पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए उद्धव की आलोचना की है। इस समय पूरे देश में सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव मामले महाराष्ट्र में हैं।

● **मुंबई से बिन्दु माथुर**

पिता-पुत्र चमक रहे हैं, लेकिन पार्टी छाया में है

56 सीटों के साथ 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ और ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाने के लिए विपक्षी कांग्रेस और राकांपा से हाथ मिला लिया, ठाकरे ने एनसीपी के अजित पवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हालांकि, उन्हें पवार या यहां तक कि शिवसेना के किसी अन्य मंत्री की तुलना में सरकारी आयोजनों में बेटे आदित्य ठाकरे के साथ ज्यादा देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई ने कहा, 'शिवसेना भाजपा के साथ सरकार में होने के बावजूद हमेशा सत्ता विरोधी थी और जबकि सभी को उम्मीद थी कि यह कहानी अंततः शिवसेना को चोट पहुंचाएगी। लेकिन यह 2019 के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुई।' उन्होंने कहा, 'शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार होने के बावजूद पार्टी के रूप में शिवसेना कमजोर होती जा रही है, हालांकि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने एक मजबूत छवि विकसित की है।' 30 वर्षीय आदित्य उद्धव के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जो पर्यटन और पर्यावरण जैसे विभागों को संभालते हैं। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पहली बार विधायक और सबसे कम उम्र के मंत्री होने के बावजूद आदित्य राज्य विधानसभा में अपने पिता के ठीक पीछे बैठते हैं और कई महत्वपूर्ण बैठकों और आधिकारिक यात्राओं में भाग लेते हैं।

भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर स्थिति में है। जिन राज्यों में कभी उसका एक क्षत्र राज हुआ करता था, आज उन्हीं राज्यों में कांग्रेस अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार में तो पार्टी पिछले लगभग 30 साल से सत्ता से दूर है। अभी भी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वह सत्ता में आ सके।

30 साल का सूखा

वो 1990 का दशक था, उसके बाद कांग्रेस कभी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। राजद के लालू प्रसाद यादव और उसके बाद जदयू के नीतीश कुमार का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस चाहकर भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। यह दोनों नेता जेपी आंदोलन से निकले हुए वो नेता रहे, जिन्होंने बिहार की राजनीति को नए सिरे से जन्म दिया। इन दोनों की राजनीति ने न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया बल्कि कांग्रेस को उनके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में राजनीतिक वातावरण गरमा गया है। एक बार फिर लालू यादव की पार्टी राजद और नीतीश की जदयू के बीच सीधा-सीधा मुकाबला होना है। खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश की जदयू ने लालू की राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन दोनों के बीच का गठबंधन ज्यादा नहीं चल सका और नीतीश ने लालू से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बना ली। अब चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपना सियासी समीकरण बनाने में लगी हैं।

बिहार में अब तक 33 मुख्यमंत्री रहे जिनमें जगन्नाथ मिश्र, भोला पासवान, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी सबसे ज्यादा तीन बार मुख्यमंत्री रहे। बिहार में 7 बार राष्ट्रपति शासन भी रहा। 1990 में कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र के बाद लालू यादव पहली बार जनता दल से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में हुए चुनाव से पहले लालू यादव अपनी पार्टी राजद को मजबूती के साथ खड़ी कर चुके थे। 1995 के चुनाव में लालू यादव को बहुमत मिला और वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने लेकिन चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के बीच लालू यादव को दो साल बाद ही 1997 में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी 2000 तक मुख्यमंत्री रहीं। 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन 7 ही दिनों में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। राबड़ी देवी 2005 तक मुख्यमंत्री रहीं।

बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय हुए नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से लगातार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री है। इस बीच मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश कुमार के प्रभाव के चलते उनकी समय से पहले ही सत्ता से विदाई हो गई। बिहारी बाबू नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए।

लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच चले सत्ता के संघर्ष में भाजपा ने बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारे। 2005 में भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। यह गठबंधन 2014 में टूटा। नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार की जदयू और लालू प्रसाद यादव की राजद ने आपस में हाथ मिला लिया। 2015 का चुनाव दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि इस **चुनाव में राजद को नीतीश कुमार** की जदयू को मिली 71 सीटों के मुकाबले 80 सीटें मिली थी लेकिन नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। गठबंधन में कड़वाहट आई और दोनों के बीच दरार पड़ गई। नीतीश ने अपनी सरकार बचाए रखने के लिए एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला लिया।

चूंकि लालू यादव चारा घोटाला मामले में जेल में है, इसलिए **राजद के पास नेतृत्व** कमजोर हो गया। लेकिन पिछले 5 सालों में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव ने विपक्ष के तौर पर नीतीश सरकार पर समय-समय पर कई सधे हुए राजनीतिक हमले किए। यहीं नहीं, कई सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की पहली पसंद भी बताया जा रहा है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने साफ कर दिया है कि अगर जदयू और भाजपा गठबंधन सत्ता में आया तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे।

● **विनोद बक्सरी**

कांग्रेस भी बढ़ाना चाहती है अपना प्रभाव

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजद और जदयू के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार होने वाले चुनाव में महागठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी हट चुकी है। ऐसे में महागठबंधन में मुख्य रूप से राजद और कांग्रेस ही बड़ी पार्टी के रूप में है। बदली राजनीतिक स्थितियों में कांग्रेस अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए 80 सीटों की मांग की है। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।

अपने ही जाल में चीन

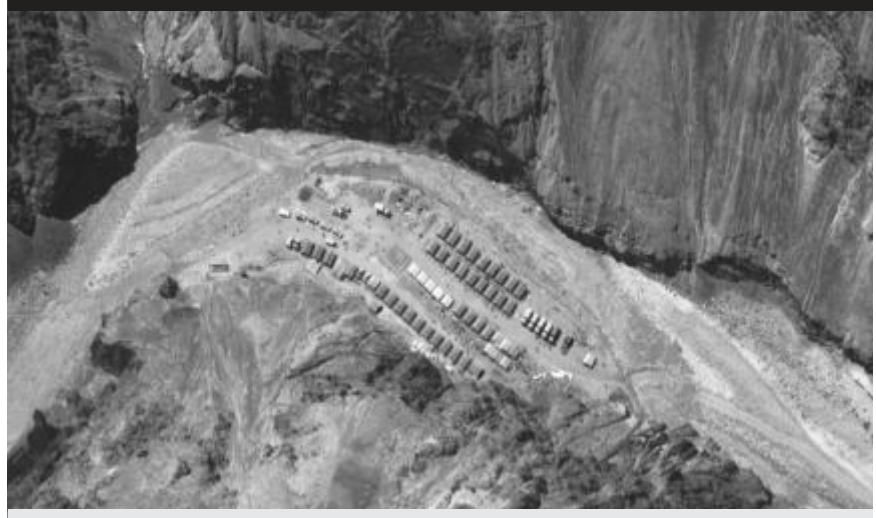

चीन की आक्रामकता का कूटनीतिक तौर पर मुकाबला

मोदी सरकार ने चीन की आक्रामकता का सामरिक और कूटनीतिक तौर पर जोरदार मुकाबला किया। शायद चीन को इसकी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई महत्वपूर्ण देशों ने इस संकट की घड़ी में चट्टान की तरह भारत का साथ दिया। एक तरह से चीन अपने ही बुने जाल में फंस गया और वह भी उस समय जब कोरोना के कारण वह सारी दुनिया में बदनाम है। वैश्विक जनमानस ने स्पष्ट तौर पर देखा कि चीन किस तरह विस्तारवाद में विश्वास करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा पर कुठाराघात किया है। अब यह साफ है कि भारत को उन सब देशों का कहीं अधिक समर्थन मिलेगा जो चीन के विस्तारवादी रवैए से त्रस्त हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन के प्रति अमेरिका का हमलावर रुख बढ़ता जा रहा है।

भारत और चीन की सीमा रेखा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है। यह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिम जिसमें लद्दाख है, मध्य जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है एवं पूर्व जिसमें सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं। मौजूदा तनाव मई 2020 के पहले सप्ताह से वैसे तो सिक्किम में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह लद्दाख तक पहुंच गया। 15 जून की रात्रि में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच बगैर घातक हथियारों के हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें भारतीय सेना के 20 और चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए।

1975 के बाद से भारत और चीनी सेना के बीच यह पहला हिंसक सीमाई संघर्ष था। 2017 में 73 दिनों तक डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना आमने-सामने खड़ी रही थी। तब चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी चीन के आमंत्रण पर वहां के शहर वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता के लिए गए थे। उसमें कई दौर की वार्ता हुई थी जिसमें मूलत: आपसी विश्वास को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति दूसरे शिखर वार्ता के लिए चेन्नई के पास महाबलीपुरम आए। इसमें भी आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग पिछले छह वर्षों में ब्रिक्स, एससीओ सहित कई मंचों पर 18 बार मिल चुके हैं। 1988 में दशकों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से आपसी संबंध बढ़ाने के लिए अब तक सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास किए।

दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कारोनावायरस का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसके चलते विश्वभर में अब तक पांच लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। आखिर इस पृष्ठभूमि में सीमा पर तनातनी पैदा करने के पीछे **आखिर चीन के क्या उद्देश्य** हो सकते हैं? इसके कई कारण नजर आते हैं। एक तो यह साफ है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जिस निर्बाध गति से सीमा पर सड़क, पुल, वायुपट्टी का निर्माण करना प्रारंभ किया गया उससे चीन सशंकित हो गया। 2014 से पहले भारत ने सीमा पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नाम मात्र का किया था। संप्रग सरकार के समय रक्षा मंत्री एके एंटनी इस तथ्य को लोकसभा में स्वीकार कर चुके हैं।

कश्मीर का मामला और पाकिस्तान-चीन संबंध भी तनातनी का एक और कारण लगता है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 को हटा दिया। पाकिस्तान दुनिया के तमाम मंचों पर इसके खिलाफ अपनी छाती पीटता रहा, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। यहां तक कि इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया। हालांकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की दाल नहीं गली। 1999 में करगिल युद्ध हुआ था। उसमें पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ कराई थी और पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर आतंकियों की मदद कर रही थी। हालांकि कारगिल संघर्ष के दौरान प्रारंभ में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बाद में पीछे हट गया। इसके बावजूद पाक-चीन गठजोड़ मजबूत होता गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक पाकिस्तान-चीन संबंध हिमालय से ऊंचे, शहद से मीठे और सागर से गहरे हैं। हैरत नहीं कि कश्मीर पर पाकिस्तान की बेबसी को समाप्त करने के लिए भी चीन ने लद्दाख में आक्रामक रुख अपनाया हो।

चीन-पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा लद्दाख के करीब से ही गुजरता है। चीन ने 2013 से अपने पश्चिमी शहर काशगर को पाकिस्तान के पश्चिमी शहर ग्वादर से जोड़ने का काम शुरू किया है। इसमें दूसरी गंभीर व्यावहारिक अड़चनें आ रही हैं, ऊपर से कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाकर भारत ने उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग-अलग संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। अनुच्छेद-370 को हटाते वक्त हुए संसदीय बहस में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि भारत अक्साई चिन समेत संयुक्त कश्मीर की एक-एक इंच जमीन वापस लेगा। चीन-पाकिस्तान गलियारा संयुक्त कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। गिलगित-बाल्टिस्तान भारत की वैध भूमि है। अब भारत इसे भी वापस लेने की बात लगातार दोहरा रहा है। दरअसल चीन ने लद्दाख में जो आक्रामकता दिखाई उसके जरिए वह पाकिस्तान की **सुरक्षा को आश्वस्त** करना चाहता था। गिलगित का क्षेत्र सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। अगर यह भारत के कब्जे में आ जाता है तो मध्य एशिया के देशों अफगानिस्तान और यूरोप तक भारत भूमि मार्ग से भी जुड़ जाएगा, लेकिन इससे चीन की सारी महत्वाकांक्षाएं ध्वस्त हो जाएंगी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

ले डूबेंगे ट्रंप के तेवर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ढीठ और जिद्दी रवैए को जहां एक ओर अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बुरी तरह फैलने और लाखों अमेरिकी नागरिकों की जान जाने का जिम्मेदार माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रम्प और उनकी पुलिस की रंगभेदी व नस्लभेदी, दक्षिणपंथी सोच और व्यवहार की दुनियाभर में आलोचना हो रही है। ट्रम्प प्रशासन का रंगभेदी और नस्लभेदी चेहरा उस समय खुलकर सामने आ गया, जब एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को सरेआम जमीन पर गिराकर पुलिस के एक गोरे जवान ने अपने घुटनों के नीचे उस की गर्दन तब तक दबाए रखी, जब तक कि उस की सांस नहीं टूट गई। जॉर्ज फ्लॉयड चीखते रहे कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन श्वेत जवान के मन में अश्वेतों के प्रति इतनी नफरत भरी थी कि उस ने फ्लॉयड की गर्दन तब तक नहीं छोड़ी, जब तक वो मर नहीं गया।

खुद को विश्व का संरक्षक समझने वाले अमेरिका की सड़क पर खुलेआम इस नरसंहार की घटना ने पूरे देश और दुनियाभर में हाहाकार मचा दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भी लोग ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ घरों से निकलकर जगह-जगह बैनर-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का डंका पीटने वाला अमेरिका अपने ही आंगन में श्वेत पुलिसकर्मी के घुटने तले दम घुटने से अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद समता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा में नाकामी के कारण कठघरे में खड़ा हो गया। **डोनाल्ड ट्रम्प की खूब लानत-मलामत हुई,** मगर इस अमानवीय कृत्य के लिए शर्मसार होने और देश व दुनिया से माफी मांगने की बात तो दूर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को 'ठग' कहा और उन्हें गोली मारने व उनके खिलाफ सेना को इस्तेमाल करने तक की धमकी दे डाली। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रम्प का अमानवीय, अड़ियल, अहंकारी, दक्षिणपंथी, नस्लभेदी और रंगभेदी सोच से भरा दिलो-दिमाग उनके देश और दुनिया के आगे पूरी तरह खुल गया। उनकी संकीर्ण मानसिकता और दंभ तब और मुखर हुआ, जब प्रदर्शनकारियों पर सेना तैनात करने की धमकी के बीच उन्होंने कहा, 'मैं आपकी कानून एवं व्यवस्था का राष्ट्रपति हूं।'

गौरतलब है कि देश को चलाने वाला पिता के समान होता है। उसकी भाषा में सौम्यता, व्यवहार कुशलता और समझदारी की अपेक्षा होती है, लेकिन इस भाव के विपरीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भड़काऊ भाषा ने प्रदर्शनों को हिंसक रूप दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश की, वह तीव्र प्रतिक्रिया सैन्यवादी थी, जिसने प्रदर्शनकारियों को और ज्यादा उकसाया और अमेरिकी समाज में गोरे व काले, अमीर और गरीब के विभाजन को गहरा किया। हालात यहां तक खराब हुए कि प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस तक पहुंच गए और राष्ट्रपति ट्रम्प को बंकर में छिपना पड़ा। क्षेत्रफल के हिसाब से महादेश कहलाने वाले तमाम जनसंस्कृतियों से युक्त अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्य आज **नस्लीय नफरत** के विरोध की आग में जल रहे हैं। ट्रम्प के शासनकाल में उभरे ये विरोध प्रदर्शन अप्रैल, 1968 में डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों की याद दिलाते हैं। ये विरोध-प्रदर्शन सिर्फ अश्वेत नागरिक की हत्या के कारण ही पैदा नहीं हुए, बल्कि ट्रम्प प्रशासन के दौरान हुए अनेक 'दंगों' के कारण अमेरिका में जो विभाजनकारी हालात बन गए हैं, उनको लेकर भी ये ट्रम्प के खिलाफ अमेरिकियों के गुस्से का इजहार था। फ्लॉयड की मौत ने तो बस अमेरिकी जनता के गुस्से के लिए एक चिंगारी का काम किया था।

अमेरिकी मीडिया का मानना है कि देश का लीडर होने के नाते देश और उसकी जनता को सुरक्षित रखने में डोनाल्ड ट्रम्प बुरी तरह फेल हुए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण अब तक अमेरिका में एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस की मार ने अमेरिका के लोगों को तोड़कर रख दिया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जगह-जगह खुले फूड बैंक पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान के चलते 4 करोड़ लोगों का बेरोजगार हो जाना और अफ्रीकी-अमेरिकी मूल के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हुई भीषण हिंसा जैसे कई ज्वलंत मुद्दे आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को मुंह की खाने को मजबूर कर सकते हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

ट्रम्प और बिडेन में कड़ा मुकाबला

अमेरिका में इस साल 3 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति चुनाव होना है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कड़ा मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और बराक ओबामा के शासन में उपराष्ट्रपति रहे जो बिडेन से होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी से अपनी दावेदारी का ऐलान करते हुए जो बिडेन ने कहा कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फिर से चुनाव जीतते हैं तो यह देश की आत्मा को दांव पर लगाने जैसा होगा, इसलिए वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कोरोनावायरस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रति देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तरीके को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। यही नहीं, उन्होंने अपने समर्थकों से राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन करने की अपील की है। उनका मानना है कि जो बिडेन राष्ट्रपति ट्रम्प के मुकाबले ज्यादा काबिल, सधे हुए और एक गंभीर व्यक्ति हैं। इस बीच जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बड़ा बयान दिया है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक जिद्दी और उद्दंड व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति चुनावों में धांधली कर सकते हैं।

अमेरिका में महक रही एक तुलसी

इस अस्त-व्यस्त दौर से मुकाबले की ऊर्जा श्रीमद्भगवद्गीता में है। इससे ही व्यक्ति को निश्चितता, शक्ति और शांति मिल सकती है। यह हम भगवान श्रीकृष्ण के सिखाए कर्मयोग व भक्तियोग के मार्ग के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये उद्गार अमेरिकी कांग्रेस की हिंदू सदस्य तुलसी गेबार्ड ने हाल ही में एक ऑनलाइन संबोधन में कहे, जबकि अमेरिका एक अफ्रीकी अमेरिकी फ्लॉयड की हत्या से उपजे आंदोलन से जूझ रहा है।

तुलसी गेबार्ड अमेरिकी कांग्रेस में एकमात्र हिंदू सांसद हैं। वे तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में अपने पद की शपथ गीता को हाथ में रखकर ली थी। वह न भारतीय मूल की हैं और न ही जन्म से हिंदू हैं। मां से मिले संस्कारों के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। उनके पिता कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी जता रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाती तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल, अमेरिका में यहूदियों के बाद दूसरे नंबर पर समृद्ध भारतीयों में वे खासी लोकप्रिय हैं। उन्हें हिंदू समाज की आवाज के रूप में देखा जाता है।

तुलसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुखर विरोधी रही हैं। यहां तक कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में भाग लेने आए, तो वह उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। हालांकि, तुलसी प्रधानमंत्री मोदी की मुखर समर्थक रही हैं। बाद में सॉरी कहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पद की दावेदारी से जुड़े कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। हवाई राज्य से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली तुलसी राजनीति में आने से पहले सेना में रही हैं और मेजर के पद पर कार्य किया है। वे बारह महीने के लिए इराक में भी तैनात रह चुकी हैं। वह वर्ष 2013 से लगातार अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक सांसद हैं।

तुलसी के भारतीय मूल के होने के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन वह अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वह नरेंद्र मोदी की बड़ी समर्थक हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने खुले तौर पर कई मंचों से मोदी का समर्थन किया। उन्हें अपनी एक गीता भी भेंट की। उन्होंने वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न दिए जाने का विरोध किया था। साथ ही भारतीय देवयानी खोबरागड़ की गिरफ्तारी का भी मुखर विरोध किया। यहां तक कि उड़ी हमलों के बाद अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने पर जोर दिया था।

हिंदू मान्यताओं से गहरी जुड़ी तुलसी पूर्णत: शाकाहारी हैं। वह चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक आंदोलन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अनुकरण करती हैं। यहां तक कि उनके भाई-बहन भी हिंदू हैं, जिनके नाम भक्ति, जय, नारायण और वृदांवन हैं। उनका मानना है कि श्रीमद्भगवद्गीता **उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन** करती है। वह कर्मयोग में गहरी आस्था रखती हैं। तुलसी भारत आने को लेकर उत्साहित हैं और खासकर वृंदावन जाना चाहती है। तुलसी ने वर्ष 2015 में अब्राहम विलियम से वैदिक रीति-रिवाज से विवाह किया था। अमेरिका के समाओ द्वीप समूह के लेलोआ लोआ में एक संभ्रांत राजनीतिक परिवार में 12 अप्रैल, 1981 में जन्मी तुलसी गेबार्ड के पिता माइक गेबार्ड हवाई द्वीप समूह की राजनीति में अपनी खास पहचान रखते हैं। कालांतर तुलसी की मां कैरोल पोर्टर ने हिंदू धर्म अपना लिया। जब तुलसी एक साल की थीं तो उनका परिवार अमेरिका आकर बस गया।

तुलसी की परवरिश मिले-जुले धार्मिक परिवेश में हुई क्योंकि जहां पिता कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, वहीं माता हिंदू धर्म को मानने वाली। लेकिन उनके पिता ने हिंदू पूजा-पद्धति का विरोध नहीं किया। तुलसी ने किशोर अवस्था में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तुलसी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही की। कालांतर वर्ष 2009 में उन्होंने हवाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी से बिजनेस प्रबंधन में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में 16 साल तक सेना में सेवाएं दी। वर्ष 2006 में अशांत इराक में तैनात रहीं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

विदेशों में कई भारतीय महिलाओं का जलवा

अमेरिका, इंग्लैंड सहित कई ऐसे देश हैं जहां की राजनीति या सेना में भारतीय महिलाएं छाई हुई हैं। तुलसी 6 नवंबर, 2012 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेट सांसद के रूप में चुनी गईं। वे अपने इलाके में रिकॉर्ड मतों से जीतती रही हैं। तुलसी भारत के साथ मजबूत अमेरिकी संबंधों की पक्षधर रही हैं। लेकिन आजकल राष्ट्रपति चुनाव में उनकी दावेदारी के खिलाफ अमेरिका में अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी बताया जा रहा है, लेकिन वे बेबाक होकर इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर-हिंदू नेताओं से कुछ न पूछना और अमेरिका के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना दोहरे मापदंडों का परिचायक है। उन्होंने उनके समर्थकों व दानदाताओं के खिलाफ अभियान चलाने की आलोचना की। वह कहती हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए पहली हिंदू अमेरिकी दावेदार होने पर मुझे गर्व है। गौरतलब है कि भारत में महिलाओं के लिए संसद से लेकर शासकीय कार्यालयों तक में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन न तो सरकारें और न ही प्रशासन महिलाओं के उत्थान के प्रति जागरूक है। इसका परिणाम यह होता है कि भारत में सशक्त होने के बाद भी महिलाएं उच्च स्थान पाने में असफल रहती हैं। जबकि इसी मिट्टी में जन्मीं कोई भारतीय महिला विदेश जाती है तो वहां अपनी योग्यता और साहस से अपनी सफलता के झंडे गाड़ देती है।

महाभारत में व्यूह रचना

महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रौंच व्यूह है, तो आसमान से देखने पर क्रौंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है।

गरुड़ व्यूहः गरुड़ पक्षी का चित्र तो देखा ही होगा आपने। यह विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी।

क्रौंच व्यूहः क्रौंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी।

मकरव्यूहः प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता है। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग होते थे, मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए भी होते थे। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ-साथ जिक्र होता है। लेकिन संभवतः यहां व्यूह रचना से तात्पर्य मगर से होगा मकर से नहीं। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरवों ने की थी।

कछुआ व्यूहः इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है।

अर्धचंद्राकार व्यूहः अर्ध चंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्ध चंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी।

मंडलाकार व्यूहः मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था।

चक्रव्यूहः चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आपने स्पाइरल देखा होगा बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी।

चक्रशकट व्यूहः महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया।

वज्र व्यूहः वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये दो प्रकार का होता था- कुलिश और अशानि। इसके ऊपर के तीन भाग तिरछे-टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है। पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी।

औरमी व्यूहः पांडवों के व्रज व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने औरमी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था।

श्रीन्गातका व्यूहः कौरवों के औरमी व्यूह के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने श्रीन्गातका व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवतः इसे ही तीन शिखरों वाला व्यूह कहते होंगे। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है।

महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के विशालकाय मैदान में कौरव और पांडवों की सेना के शिविर कहां-कहां लगे थे यह शोध का विषय हो सकता है। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी (सरस्वती नदी की सहायक नदी) के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र-शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन (1 योजन= 8 किमी की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस या कोश= 1 योजन= 13 किमी से 16 किमी)= 40 किमी का घेरा छोड़ दिया गया था।

● ओम

विरोध

पापाजी, मेरे स्कूल से नोटिस आया है।

'उसमें क्या लिखा है।

उसमें लिखा है कि यदि आपने तीन दिन में अप्रैल, मई, जून माह की फीस जमा नहीं की, तो आपका नाम काट दिया जाएगा।

अंश ने अपने पिता से कहा। पर, तीन माह से तो स्कूल बंद है। पिता ने कहा।

पर, उससे क्या? स्कूल की बात तो माननी ही पड़ेगी बेटे ने कहा। पर पिता जायसवाल को स्कूल की यह मनमानी स्वीकार नहीं थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने जैसे पीड़ित अन्य अभिभावकों को इकट्ठा किया और लेकर कमिश्नर महोदय के पास पहुंच गए। कमिश्नर साहब ने उनके निवेदन पर गौर किया और पाया कि चूंकि बच्चों ने स्कूल की बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया है, केवल ऑनलाइन टीचिंग का उपयोग किया है, इसलिए उन्होंने स्कूल द्वारा पूरी फीस वसूलने को अनुचित माना और स्कूल को फीस का केवल आधा हिस्सा ही वसूलने की अनुमति दी।

इस प्रकार जायसवाल की जागरूकता से सारे अभिभावक स्कूल-प्रशासन की मनमानी का शिकार होने से बच गए। बेटे अंश ने पिता से कहा- पापा, आपके इस कदम से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि जीवन में अन्याय व शोषण को कभी सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें गलत बात का न केवल विरोध करना चाहिए, बल्कि गलत निर्णय रद्द करने के लिए हर हाल में अड़ जाना चाहिए।

– प्रो. शरद नारायण खरे

प्रीत का व्याकरण

घूमते शब्द कानन में उन्मुक्त से,
जान पाए नहीं प्रीत का व्याकरण।
बस दिशाहीन सी चल रही लेखिनी
कण्टकाकीर्ण पथ नापते हैं चरण।।
ताल बनती नहीं, राग कैसे सजे,
बेसुरे हो गए, साज-संगीत हैं।
ढाई-आखर बिना है अधूरी गजल,
प्यार के बिन अधूरे प्रणयगीत हैं
नेह के स्रोत सूखे हुए हैं सभी,
खो गए हैं सभी आजकल आचरण।
कण्टकाकीर्ण पथ नापते हैं चरण।।
सूदखोरों की आबाद हैं बस्तियां,
आज गिरवी पड़ा है तिजोरी में दिल।
बिक रहा बोतलों में जहां पेयजल,
आचमन के लिए है कहां अब सलिल।
खोखले छंद बोलेंगे कैसे व्यथा,
स्वार्थ के वास्ते आज पोषण-भरण।
कण्टकाकीर्ण पथ नापते हैं चरण।।
चारणों के नगर में, सुखनवर कहां,
जिन्दगी चल रही भेड़ की चाल से।
कौन तूती के सुर को सुनेगा यहां,
मढ़ रहे ढपलियां, बाल की खाल से।
लाज कैसे बचे द्रोपदी की यहां
कंस ओढ़े हुए हैं कृष्ण का आवरण
कण्टकाकीर्ण पथ नापते हैं चरण।।

- (डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक')

आत्महत्या का कारण

बातुक और राजकुमार की दोस्ती प्रगाढ़ हो चली थी। ऐसा लगता था, मानो दो जिस्म एक जान हों। कोई भी समस्या होती तो राजकुमार बातुक से अवश्य पूछते।एक दिन राजकुमार ने बातुक से पूछा- बातुक! लोग आत्महत्या क्यों इतनी ज्यादा करने लगे हैं?

बातुक कुछ समय तो सोच में पड़ गया जवाब तो देना था, वो भी राजकुमार के मन के अनुरूप तो वह सोचकर बोला-

कई कारण हैं आत्महत्या के... कहीं गरीबी तो कही अमीरी... कोई किसान तो कोई सेलेब्रिटी...लेकिन सभी कारण नस ढीली।

राजकुमार झुंझला गए अर्थात् उन्होंने कहा- ये क्या बोला हमें तो तुम्हारी भाषा कभी सरल नहीं लगती। सरल भाषा में समझाकर कहो।

हुजूर! आत्महत्या करने वाले कोई भी हो सकते हैं। पर वे दो ही तरह के होते है गरीब या अमीर। गरीबी से तंग आकर तो कोई अमीरी से लेकिन आत्महत्या की वजह एक ही होती है वो है मानसिक कमजोरी जिसे डिप्रेशन, पागलपन, अवसाद जो भी कहें। ऐसी स्थिति किसी भी इंसान के साथ हो सकती है ज्यादा खुशी होने पर या ज्यादा दुखी होने पर।

इससे बचने का उपाय क्या है बातुक?

बातुक बोला!

वृहत की चाहत छोड़िए... संतोष की आदत डालिए... धन-मन त्रिया चरित्र...से दूर ही भागिए।

अर्थात् ज्यादा बनाने का आदत त्यागना ही होगा जितना मिल जाए उसमें संतोष करना परम आवश्यक है। धन की जिज्ञासा छोड़कर कर्म में मन लगाना होगा। जिससे आपके मन पवित्र रहेंगे और मन स्वस्थ रहेंगे। चरित्रहीन से प्रेम प्यार चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन लोगों से बचना होगा। तभी इस डिप्रेशन रूपी अवसाद से बचा जा सकता है वरना ऐसे ही नित आत्महत्या की रस्सी पीछा कर निगलती जाएगी जीवन को।

राजकुमार बोले- वाह बातुक... हम तुम्हारी बातें सुनकर अति प्रसन्न हुए।

– आशुतोष झा

बॉलीवुड में होती है डर्टी पॉलिटिक्सः रवीना टंडन

यहां प्लान बनता है कैसे तबाह करना है करियर

रवीना टंडन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कुछ बातें कही हैं। रवीना ने सुशांत की मौत के बाद वॉट्सऐप पर चल रहे मैसेज को लेकर हैरानी जताई है और कहा है- करण जौहर ने जानबूझकर सुशांत के लिए खराब फिल्म बनाई ताकि वह उनके करियर को बर्बाद कर सके। अब कोई प्रड्यूसर किसी ऐक्टर को करोड़ों रुपए एक बकवास फिल्म करने के लिए क्यों देगा? कोई अपनी ही फिल्म को खराब करने के पीछे इतने पैसे, समय और सारी व्यवस्था के पीछे क्यों खर्च करेगा? ये बहुत हास्यास्पद है। हालांकि, रवीना बॉलीवुड में कैम्प और मीन गर्ल गैंग की मौजूदगी से इंकार नहीं करती हैं, जिसे लेकर उन्होंने सुशांत की मौत के बाद ट्वीट भी किया था। इसके साथ ही ऐसे तमाम सिलेब्रिटीज भी सामने आ गए, जिनका आरोप है कि बॉलीवुड में कैम्प और नेपोटिजम की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। रवीना टंडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, लोगों को तर्क के साथ सोचने की जरूरत है। यह दुनिया से गुजर चुके लड़के के अपमान किए जाने जैसा है।

मैंने भी इसे झेला है

रवीना ने इस बातचीत में कहा, मानती हूं कि यहां पॉलिटिक्स है और यहां अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। यही बातें मैंने अपने ट्वीट में भी लिखी थी। जो बुरे लोग हैं वे आपकी असफलता को लेकर प्लान करते हैं, मैंने भी इसे झेला है। वे ऐसे होते हैं जो आपको पहले नीचा दिखाएंगे और फिर फिल्मों से आउट कर देंगे। यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे क्लासरूम के अंदर का पॉलिटिक्स होता है। ये लोग गंदा गेम खेलते हैं।

अगर नेपोटिजम होता तो अपनी 10वीं फिल्म कर रहा होताः सूरज

बॉलीवुड के टैलेंटेड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिजम की बहस ने एक बार फिर सामने आ गई है। इस बहस में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ ही सुशांत के फैन्स ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को भी जमकर ट्रोल किया है। इस बारे में बात करते हुए सूरज पंचोली ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर यहां सब कुछ नेपोटिजम से ही होता तो मैं अभी अपनी 10वीं फिल्म कर रहा होता। अभी जो भी कुछ हुआ है उसका नेपोटिजम से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू कर दिया था। पहले 2010 में फिल्म गुजारिश में फिर 2012 में एक था टाइगर में। यहीं मैं सलमान सर से मिला था और उन्होंने मुझे वादा किया कि वह किसी फिल्म में मुझे कास्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझमें पोटेंशल देखा। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि क्या में ऐक्टर बनना चाहता हूं और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आगे बात करते हुए सूरज ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बस मुंह उठाकर फिल्म के सेट पर आ गया। मैंने पहली बार साल 2013 में फिल्म काई पो छे के लिए ऑडिशन दिया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था।

राम लीला के लिए फाइनल था सुशांत का नाम : भंसाली

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही ऐसे आरोप लगने लगे थे कि उनके साथ भेदभाव किया गया जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत मुंबई पुलिस को सुशांत की आत्महत्या के मामले की जांच करने का आदेश दिया था। इस मामले में मुंबई पुलिस हर संभव ऐंगल से जांच कर रही है और सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने गत दिनों जाने-माने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से 2 घंटे तक पूछताछ की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय लीला भंसाली ने अपनी कुछ फिल्मों के लिए सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। खबर के मुताबिक कुछ सूत्रों ने बताया है संजय लीला भंसाली ने अपने सुशांत के बीच हुई बातचीत का ब्योरा पुलिस को बताया है। सूत्र ने कहा कि संजय ने बताया कि उन्होंने गोलियों की रासलीला- रामलीला में सुशांत का नाम लगभग फाइनल कर ही दिया था। मगर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि सुशांत दूसरे प्रॉडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे। बताया जाता है कि सुशांत इस बात से काफी दुखी भी थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण वह संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं कर सके। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, भंसाली से पूछताछ केवल उनकी सुशांत से हुई बातचीत तक सीमित थी जो उन्होंने तब की थी जबकि सुशांत अपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट के कारण संजय की फिल्म नहीं कर पाए थे। बांद्रा पुलिस स्टेशन में संजय लीला भंसाली से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई।

जोश और जुनून भर देने वाला कप्तान!

जुलाई माह में भारतीय क्रिकेट के दो बड़े सितारे सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी जन्मे थे। अस्सी और नब्बे के दशक में पैदा होने वाली पीढ़ी ने अपनी बचपन से जवानी तक क्रिकेट को असल में इन्हीं दोनों की कप्तानी में देखा, समझा और ऐसा जिया कि बस मजा आ गया। भारत में क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले की कहानी नहीं है। यह एक्शन, इमोशन, ट्रैजडी और ड्रामा यानी सब का कॉकटेल है। कुछ अतिउत्साही क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो यह धर्म भी है। सन् 1983 में भारत क्रिकेट के एक दिवसीय विश्वकप का पहला खिताब जीता चुका था। इसके बाद क्रिकेट को लेकर लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही थीं। सन् 1991 के बाद पूरी दुनिया के साथ क्रिकेट का दौर भी फटाफट बदल रहा था। सफेद कपड़ों में खेलते खिलाड़ी अब रंग-बिरंगे कपड़ों में खेलते नजर आने लगे। सैटेलाइट चैनलों के दौर ने क्रिकेट को देखना और भी सुलभ बना दिया। विदेशी दौरों के भी लाइव टेलीकास्ट आने लगे। दर्शकों के दिल ने जितना भी 'मोर' मांगा उतना 'मोर' मिलने लगा। सन् 1996 के विश्वकप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों हुई भारत की शर्मनाक हार के बाद तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी के दिन लदने के संकेत दे रहे थे। बाद में **मैच फिक्सिंग के आरोपों** ने उनके कैरियर के सूरज को डुबो ही दिया। सन् 1999-2000 तक सौरव गांगुली के कप्तान बनने तक 1983 के क्रिकेट के विश्वकप का विजेता भारत सचिन, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और अनिल कुंबले सरीखे तमाम प्रतिभावान खिलाड़ियों से तो संपन्न था पर एक ऊर्जावान नेतृत्व की कमी बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। ऐसे समय में बंगाल के बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरव गांगुली को भारत का कप्तान बनाया गया। सचिन तेंदुलकर के साथ पारी के शुरुआत से ही उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की शैली के लोग भारी प्रशंसक थे। दादा की बल्लेबाजी जिसने भी देखी होगी उसे दादा की फास्ट गेंदबाजों को उम्दा और बेमिसाल टाइमिंग के साथ लगने वाले कवर ड्राइव आज भी याद होंगे।

इसी के साथ गेंदबाजों की आंखों में आंखे डालकर फ्रंट फुट पर तीन कदम आगे आकर मैदान के बाहर जाने वाला छक्का दादा के बैटिंग की विशिष्ट पहचान बन गया था। एक प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में दादा को पहचान घरेलू स्पर्धाओं के प्रदर्शन से मिलने लगी थी। बंगाल की तरफ से खेलते हुए सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी आदि में कई यादगार और प्रभावशाली प्रदर्शन किए। जिसके आधार पर सौरव को वर्ष 1992 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। इस दौरे में 11 जनवरी 1992 को उन्होंने गाबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। लेकिन कैरियर के लिहाज से यह दौरा उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ और दौरे के दौरान उनके खराब बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस दौरे के बाद चार साल तक उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं लिया गया। फिर वर्ष 1996 में सौरव गांगुली का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए किया गया। इस दौरे में टेस्ट और वन-डे मैच दोनों खेले गए। यहां भी तीन वन-डे मैच में से सौरव गांगुली को सिर्फ एक वन-डे मैच में खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने कुल 46 रन बनाए। लेकिन क्रिकेट के इस शूरवीर को अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर का आरंभ अपने प्रकृति के अनुरूप शाही अंदाज में करना था और वह मौका टेस्ट मैच ने दिया 20 जून सन् 1996 को सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया। इस मैच में सौरव ने 131 रनों की शानदार पारी खेली।

आत्मविश्वास से भरे सौरव ने इसी दौरे के अगले मैच में भी शतकीय पारी खेलकर अपनी योग्यता को साबित किया। इस दौरे में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अपने पहले दो टेस्ट मैचों में दो सेंचुरी बनाने वाले वह दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। इसके बाद फिर सौरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996-97 के दौरान सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में चार में मैन ऑफ मैच पाना हो या 1999 के वर्ल्ड कप में द्रविड़ के साथ 318 रनों की मैराथन पार्टनरशिप हो।

सौरव की कप्तानी में भारतीय टीम के जुझारूपन का अप्रतिम उदाहरण 2001 के भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचों में अपराजेयता को खंडित करने वाली टेस्ट सीरीज में 2-1 से भारत की जीत हुई। इसी भांति 2003 के विश्वकप के फाइनल तक भारत ने जिस आत्मविश्वास से खेला वह स्मृति आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में जीवित है। सन् 2000 से सन् 2005 तक का भारतीय क्रिकेट सौरव गांगुली के खेल और कप्तानी में निखरता रहा। 2006 के बाद सौरव गांगुली के कैरियर में उतार आना शुरू हो गया और सन् 2008 में दादा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा बोल दिया। दादा को सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों को तराशने का भी श्रेय है।

दादा के खेल और कप्तानी का सबसे सकारात्मक पक्ष यही था कि उनमें एक टाइगर की भांति जीतने की जिद, जोश और जुनून के हद तक लड़ने की क्षमता थी। यह संयोग नहीं नियति का आशीर्वाद है कि आज जब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम विश्व क्रिकेट की सिरमौर है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं।

बैटिंग में सिद्धस्त और ख्यातिप्राप्त सौरव गांगुली को लोग भारतीय क्रिकेट के उस दौर के रूप में ज्यादा याद करते है जिस दौर में भारत ने वैश्विक क्रिकेट में महाशक्ति बनने के आत्मविश्वास को अर्जित किया। अंतिम बॉल तक जूझने के उस जज्बे को पाया जिसने आज भारतीय क्रिकेट टीम को सुपर पावर टीम के ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया है।

● **आशीष नेमा**

मौसम शुरू हो गया है

पौधा तो एक ही लगता है, पर पोज बदल-बदल कर अनगिनत फोटो की एलबम तैयार हो जाती है। तब कहीं जाकर एक पौधा लगाने के लिए वे गड्ढे की ओर झुकते हैं। यद्यपि झुकना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, लेकिन यहां उन्हें विवश होकर झुकना ही पड़ता है। देते समय देने वाले का झुकना प्राकृतिक ही है।

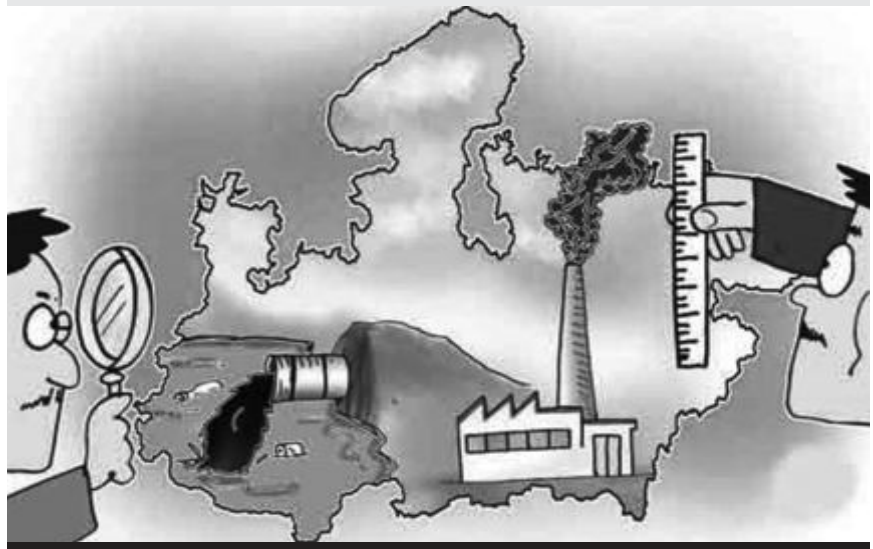

सबका अपना एक मौसम होता है। बिना मौसम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज पर्यावरण दिवस से पर्यावरण मित्रों का भी मौसम शुरू हो गया है। बाकायदा हवन में खुशबूदार समिधा की गिनी हुई आहुतियां देने के बाद श्रीगणेश हो गया। वैसे साल भर गाहे-ब-गाहे कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पांच जून का आगमन होता है, पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ इस मौसम का उद्घाटन हो जाता है। सबसे पहले कवि, शायर, बुद्धिजीवी और विचारकों के माध्यम से पर्यावरण पर कविताएं, शायरी और बड़े-बड़े लेख प्रकाशित किए जाते हैं। स्वयं को छोड़कर दूसरों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे अधिक से अधिक पौधरोपण करें, ताकि वर्षा अधिक हो। धरती की प्यास बुझे। ज्यादा अन्न, फल, सब्जी, दुग्ध का उत्पादन हो। क्या अखबार, क्या टीवी, क्या सोशल मीडिया सब पर मानो बाढ़ ही आ जाती है। सोए हुए भी खड़े हो जाते हैं। जिनकी अस्थियां जकड़ गई हैं, उनमें भी नए-नए कल्ले प्रस्फुटित होने लगते हैं।

फिर क्या! कार्यक्रमों पर कार्यक्रम चलने लगते हैं। गड्ढे खोदने वाले गड्ढे खोदते हैं। पौधे लाने वाले पौधे लाते हैं और माननीय महोदय अपने सफेद चमचमाते सूट में एक पौधा ऐसे पकड़ते हैं कि हाथ से मिट्टी न छू जाए। वे झुक कर उस पौधे को उठाने का कष्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनकी कमर को बल खाने का खतरा है। जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं उठाना चाहते। इसलिए पहले से ही तैनात एक स्फूर्तिवान युवक चटपट उनके कर कमलों में पॉलीथिन आवृत पौधे को थमा देता है। उन्हें तो इसकी पॉलीथिन को हटाने का कष्ट गवारा नहीं होता, इसलिए इशारा होता है कि इसकी पॉलीथिन हटाई जाए। तुरंत पॉलीथिन हटाई जाती है। इसके बाद मोबाइलों और कैमरों की फ्लैश पर फ्लैश चमकने लगती हैं। माननीय मुस्कराते हुए फोटो खिंचवाते हैं। पौधा तो एक ही लगता है, पर पोज बदल-बदल कर अनगिनत फोटो की एलबम तैयार हो जाती है। तब कहीं जाकर एक पौधा लगाने के लिए वे गड्ढे की ओर झुकते हैं। यद्यपि झुकना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, लेकिन यहां उन्हें विवश होकर झुकना ही पड़ता है। देते समय देने वाले का झुकना प्राकृतिक ही है। जब तक आप किसी को कुछ देते हैं, तो झुकना ही पड़ेगा। एक नन्हा सा पौधा माननीय को आखिर झुका ही लेता है। तने हुए खड़े रहने पर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते और लेने वाला ले नहीं सकता, क्योंकि लेने की प्रक्रिया में झुकना एक अनिवार्य कृत्य है। लेने वाले के हाथ सदैव नीचे ही रहते हैं। यहां पर जो देने वाला दिखता है, वह मांगने वाला है। उसे यश चाहिए एक पौधा लगाकर, खुशी चाहिए एक पौधा लगाकर, सराहना चाहिए एक नवांकुर सजाकर।

सबको देने वाली धरती को कोई क्या देगा? वह तो जननी है। जीवन, अन्न, जल, फल, दुग्ध, ईंधन, वसन, घर, सोना, चांदी, धन धान्य सब कुछ वही तो देती है। और मूढ़ समझता है कि वह एक पेड़ रोपकर धरती को दे रहा है। भिखारी अपने को दाता मान बैठा है।

तो माननीयजी पौधा लगा रहे थे। उन्होंने पौधे को पूर्वनिर्मित गड्ढे में रख दिया है। पुन: फोटोबाजी और वीडियोबाजी की होड़ लग गई है। वे कैमरे की ओर मुंह उठाए हुए दंत दर्शन कराते हुए से फोटो खिंचवा रहे हैं। पौधे के तने को हाथ से स्पर्श किया हुआ है। बस इतने जागरूक अवश्य हैं कि कहीं हाथों से मिट्टी न छू जाए! फोटो बराबर खिंच रहे हैं। और चेला गण गड्ढे में मिट्टी डाल रहे हैं। माननीय कमर पर हाथ टेककर उठकर खड़े हो रहे हैं। पौधारोपण का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। उधर देखें वह एक चेला बाल्टी में पानी लेकर हाथ में मग थामे हुए तेज कदमों से चला आ रहा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका क्या होना है। इतना तो तय है कि पहले माननीय के हाथ धुलवाए जाएंगे। उन्हें नहलाया नहीं जाएगा। यदि बच गया तो पौधे के हवाले कर दिया जाएगा। लो जी, हो गया पौधारोपण: एक राष्ट्रीय कार्यक्रम।

अगले दिन अखबार में मुस्कराते हुए माननीय के साथ एक लंबा चौड़ा समाचार छापा गया कि उनके द्वारा 501 पौधे लगाए गए। साथ में किसी बुद्धिजीवी द्वारा लिखा गया भाषण भी सुर्खियां बटोर रहा था। यदि देश में सभी माननीयों के द्वारा पौधे लगाने की यही गति रही तो वह दिन दूर नहीं जब देश का हर गांव, खेत, शहर, ऊसर, बंजर, वन, उपवन सब जगह पेड़ों के झुरमुट होंगे। हरित क्रांति ही हो जाएगी। सारा प्रदूषण दूर होगा। नदियां कलकल निनाद से सागर की ओर अवगाहन करेंगीं। खूब वर्षा होगी। आंकड़े सच साबित होंगे। फिर ऊपर से नीचे तक सबके आंकड़ों में कोई भेद नहीं होगा। जो ऊपर वाला कहेगा, उसे ही नीचे वाला भी दोहराएगा। सर्वत्र समानता का बोलबाला होगा। एक सच्ची हरित क्रांति होगी। हरित का अर्थ चोरी की हुई नहीं, हरी-हरी क्रांति।

देश के कर्णधारों के कर कमलों से कृत पर्यावरण मित्र बनाने और उसे अंगीकृत कराने करने का काम एक अनिवार्य महत्वाकांक्षी आयोजन है। जो जेठ-जून की पांच तारीख से आगाज करते हुए शरद के शुभारंभ तक चलता है। यह माननीयों का वसंत है। वे संत और इधर ये वसंत। वैसे होता है यह अनन्त। परन्तु इसका भी है कुछ किन्तु परंतु। पावस की बहार। धरती को उपहार।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

भोपाल विकास प्राधिकरण

की सम्पत्ति क्रय करने का सुनहरा अवसर

ऑफर खुलने का दिनांक 05 अगस्त 2020

आवेदन प्राप्ति दि. 18 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक

आवासीय एवं व्यवसायिक

ऑफर के माध्यम से विक्रय की जाने वाली सम्पतियां

योजना का नाम	प्रकोष्ठ/दुकान/भवन	रिक्त संपतियों की संख्या	कारपेट एरिया वर्गमीटर/वर्गफिट में	श्रेणी अनारक्षित	प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत रुपये प्रति संपत्ति मूल्य	रजिस्ट्रीकरण प्रभार (पंजीयन राशि) रुपये	वार्षिक भू-भाटक
कटारा हिल्स सेक्टर -ए एवं सेक्टर-सी	दुकाने	27	9.45 वर्गमीटर 101.68 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	8,57,034/- से प्रारंभ	85,710/-	1543/-
	दुकान क्र. 1,3,5,11	04	18.92 वर्गमीटर 203.57 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	12,73,446/- से प्रारंभ	1,27,344/-	2292/-
विजय स्तंभ योजना एम.पी.नगर, जोन - 1	दुकान क्र. 14 (एस.एफ.)	01	35.50 वर्गमीटर 381.98 वर्गफिट	अनारक्षित	38,38,800/-	3,83,880/-	3152/-
आई.एस.बी.टी.योजना (प्लेटफार्म)	दुकान क्रमांक 27	01	8.47 वर्गमीटर 91.13 वर्गफिट	अनारक्षित	22,09,201/- से प्रारंभ	2,20,920/-	1370/-
गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर परिसर साकेत नगर, भोपाल	रिक्त दुकान संख्या 3	28	263.94 वर्गफिट	अनारक्षित	37,20,000/-	3,16,200/-	545/-
		29	263.94 वर्गफिट	अनारक्षित	37,20,000/-	3,16,200/-	545/-
		33	200.99 वर्गफिट	अनारक्षित	28,33,000/-	2,40,805/-	415/-
अन्नपूर्णा काम्पलेक्स	दुकान क्रमांक 23	01	26.99 वर्गमीटर 290.41 वर्गफिट	अनारक्षित	26,31,525/-	2,63,153/-	505/-
पंचशील नगर योजना	दु.क्र. 3,5,7,9, एवं के. 07	05	63.00 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	4,78,000/- से प्रारंभ	47,800/-	54/-
महर्षि पतंजलि गोदरमऊ	दुकाने	35	98.13 वर्गफिट 9.12 वर्गमीटर	अनारक्षित	4,78,800/- से प्रारंभ	4,7880/-	1119/-
पंडित भीमसेन जोशी परिसर साकेत नगर	दुकान क्रमांक 05, 10, 12	03	282.66 वर्गफिट	अनारक्षित	22,07,000/-	2,20,700/-	583/-
			336.57 वर्गफिट	अनारक्षित	26,28,000/-	2,62,800/-	693/-
			220.90 वर्गफिट	अनारक्षित	17,25,000/-	1,72,500/-	455/-
माता मंदिर योजना	दुकाने	08	5.28 वर्गमीटर 56.81 वर्गफिट	अनारक्षित	6,93,726/- से प्रारंभ	69,372/-	995/-
आमेर काम्पलेक्स (नाले के ऊपर) एम.पी.नगर जोन 2	दुकान क्रमांक 15	01	102.97 वर्गफिट 9.56 वर्गमीटर	अनारक्षित	18,08,730/-	1,80,873/-	212/-
लॉ चेम्बर	लॉ चेम्बर	06	7.50 वर्गमीटर 80.7 वर्गफिट से प्रारंभ	अधिवक्ता हेतु	8,73,180/- से प्रारंभ	87,318/-	6496/-
केन्टीन/पेन्ट्री	चेम्बर पेन्ट्री	01	110.28 वर्गमीटर 1186.61 वर्गफिट	अधिवक्ता हेतु	1,62,12,630/- से प्रारंभ	16,21,263/-	95530/-

आवासीय सम्पत्ति

योजना का नाम	प्रकोष्ठ/दुकान/भवन	रिक्त संपतियों की संख्या	कारपेट एरिया वर्गमीटर/वर्गफिट में	श्रेणी अनारक्षित	प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत रुपये प्रति संपत्ति मूल्य	रजिस्ट्रीकरण प्रभार (पंजीयन राशि) रुपये	वार्षिक भू-भाटक
अन्नपूर्णा काम्पलेक्स	आवासीय प्रकोष्ठ क्र. ई. 109	01	110.61 वर्गमीटर 1190.16 वर्गफिट	अनारक्षित	38,66,788/-	3,86,680/-	505/-
माता मंदिर	आवासीय प्रकोष्ठ क्र. एम 26	01	75.00 वर्गमीटर 807.00 वर्गफिट	अनारक्षित	24,02,250/-	2,40,250/-	2430/-
सोनिया गांधी	आवासीय प्रकोष्ठ LIG सी 2/5	01	23.18 वर्गमीटर 249.41 वर्गफिट	अनारक्षित	7,66,278/-	76,628/-	349/-
गीतांजली काम्पलेक्स	आवासीय प्रकोष्ठ LIG बेसमेंट ब्लॉक 9	01	71.68 वर्गमीटर 771.27 वर्गफिट	अनारक्षित	22,88,025/-	2,28,805/-	113/-
विद्या नगर	MIG प्रकोष्ठ ए-13, द्वितीय तल	01	86.71 वर्गमीटर 932.99 वर्गफिट	अनारक्षित	27,00,149/-	2,70,015/-	378/-
एम.जी. रूसिया नगर, पीपलनेर	MIG बी-टाईप डुप्लेक्स क्र. 145,146,147 एवं 150	04	94.48 वर्गमीटर 1016.60 वर्गफिट	अनारक्षित	37,70,300/-	3,77,000/-	16855/-
अजंता काम्पलेक्स	परिवर्तित LIG प्रकोष्ठ 3/66	01	23.51 वर्गमीटर 252.96 वर्गफिट	अनारक्षित	5,19,728/-	51,972/-	89/-
अमरावद खुर्द	LIG डुप्लेक्स 1-4, 6-12, 20, 23-26, 31-35, 38-40, 41-42	22	40.50 वर्गमीटर 435.78 वर्गफिट	अनारक्षित	13,43,000/-	1,34,300/-	70/-
स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा हिल्स	जूनियर MIG	45	56.43 वर्गमीटर 607.18 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	15,76,000/- से प्रारंभ	1,57,600/-	3,643/-
शहीद भगत सिंह गोदरमऊ योजना (नियत मूल्य पर)	2 बी.एच.के. द्वितीय तल	75	41.75 वर्गमीटर 449.23 वर्गफिट	अनारक्षित	10,97,000/-	1,09,700/-	198/-
	तृतीय तल			अनारक्षित	10,90,000/-	1,09,700/-	198/-
महर्षि पातंजली परिसर योजना (नियत मूल्य पर)	2 बी.एच.के. प्रकोष्ठ	22	41.75 वर्गमीटर 449.23 वर्गफिट	अनारक्षित	10,00,000/-	1,00,000/-	197/-
नवीबाग घरौंदा अफोंडेबल योजना (नियत मूल्य पर) रेरा नं. P-BPL-17-837	2 बी.एच.के. प्रकोष्ठ	309	41.05 वर्गमीटर 441.69 वर्गफिट	अनारक्षित	13,00,000/-	1,30,000/-	30/-

नोट - 1. नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेगी।
2. दुकान का आवंटन यथा-स्थिति में किया जावेगा।
3. नियत मूल्य की सम्पत्तियों के फार्म पृथक से दिये जायेंगे।

नोट- योजनाएं रेरा से पूर्व निर्मित हैं

सम्पत्तियों के ऑफर दिनांक 05.08.2020 को समय 12.00 बजे खोले जावेंगे।

आवेदन पत्र मुख्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते है।

ऑफर फार्म का मूल्य 500/-

उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

www.bda.org.in
प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन- I, एम.पी. नगर, भोपाल 462011 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2701836/37/38, 2557273 / 2557276 Email : info@bda.org.in

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444

Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®